HP/129/SML/2019-2021
RNI Reference No. 1328500
01-15 फरवरी, 2019

द रीव टाइम्स

The RIEV Times

हिमाचल,
वर्ष 1/ अंक 14/ पृष्ठ: 16
मूल्य: ₹ 25/-

www.therievtimes.com

आत्मविश्वास की परख पर ही आत्मनिर्भरता का जन्म होता है : डॉ॰ एल.सी. शर्मा

कौशल विकास से खुले रोज़गार के द्वार

मुख्यमंत्री ने IIRD की सेवाओ को सराहा

योगी आदित्यनाथ ने संस्था द्वारा संचालित केन्द्रों के प्रशिक्षुओं को प्रदान किए रोज़गार प्रमाण पत्र

आईआईआरडी द्वारा संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में युवाओं को विभिन्न ट्रेड में मिला प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ IIRD के प्रशिक्षु एवं अधिकारी

द रीव टाइम्स (हेमराज चौहान)

प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन के तहत आईआईआरडी द्वारा देश भर में युवाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार के द्वार खोले हैं। इसी के तहत उत्तर प्रदेश में आईआईआरडी द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन में युवाओं को सफल प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए भी सार्थक पहल की गई है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्हें रोजगार का भी प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदान किया गया। इन युवाओं ने आईआईआरडी द्वारा संचालित केन्द्रों पर कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया और रोजगार मेले में मुख्यमंत्री के हाथों उन्हें रोजगार नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए।

आईआईआरडी द्वारा उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले के सिविल लाईन में, गोरखपुर ज़िले के तुरा बाज़ार और महाराजगंज ज़िले के मिठौरा में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के संयुक्त तत्वावधान में युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसमें युवाओं को विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षित करने के बाद प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया जिसमें इन युवाओं को साक्षात्कार के बाद नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडलीय रोजगार एवं नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शिरकत की तथा इस उपलक्ष्य पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन के माध्यम से रोजगार के क्षेत्र में क्रांति आई है । उन्होंने कहा कि देश भर में कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को स्थाई रोजगार के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं तथा उत्तर प्रदेश भी इससे नए रोजगार के अवसर प्राप्त हुए है। उन्होंने यह भी कहा कि देशभर में युवाओं के लिए रोजगार के क्षेत्र में नई राहों को खोलने का कार्य किया गया है। आईआईआरडी के प्रतिनिधियों ने इस बाबत मुख्यमंत्री को प्रशिक्षण केन्द्रों की गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने इन गतिविधियों की सराहना की। साथ ही आईआईआरडी से प्रशिक्षित युवाओं को अपने हाथों से प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया तथा नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। आईआईआर्रडी की सुष्मिता साहनी, ऋतु और शीला को यह नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।

इस अवसर पर आईआईआरडी से प्रोजेक्ट हैड अमित श्रीवास्तव, आनंद यादव, आबिद हुसैन, अवनीश मिश्र, धर्मेन्द्र शर्मा, छम्मा कपूर, भी उपस्थित रहे । उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के निदेशक (आईएएस) प्रांजल यादव भी उपस्थित रहे ।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सराहे संस्था के प्रयास

रोजगार मेले के अवसर पर आईआईआरडी के अधिकारियों के द्वारा मुख्यमंत्री को विस्तार से प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे प्रशिक्षण केन्द्रों की जानकारी दी । मुख्यमंत्री ने सेवाओं की सराहना की तथा युवाओं से भी बात की ।

आईआईआरडी हिमाचल प्रदेश में भी कौशल विकास में देगा सेवाऐं

गौरतलब है कि आईआईआरडी और मिशन रीव के संयुक्त तत्वावधान में हिमाचल प्रदेश में भी युवाओं के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के संयुक्त तत्वावधान में युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में बड़ी पहल करने के अग्रणी भूमिका में है । इसके तहत शिमला के शनान में दो ट्रेड में युवाओं के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं । इसमें फार्मेसी एसिस्टेंट और जुनियर सॉफ्टवेयर डेवेल्पर के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है । पंजीकरण के लिए शिमला और आसपास में युवाओं को जागरुक करने के लिए भिन्न–भिन्न तरीकों से जानकारी प्रदान की जा रही है । बेरोजगार युवाओं ने इसमें अपनी रुचि दिखाई है । इन कोर्सिस के लिए मुख्य विशेषताऐं युवाओं का आकर्षण का केन्द्र है जिसमें प्रशिक्षण निःशुल्क रहेगा, निःशुल्क कोर्स पुस्तिका एवं किट, प्रशिक्षुओं के लिए सौ प्रतिशत रोज़गार, केन्द्र सरकार की ओर से कौशल प्रमाण पत्र तथा महिलाओं और दिव्यांगों को सरकार की ओर से वित्तिय लाभ शामिल है । इसके लिए प्रार्थी को आधार कार्ड की प्रतिलिपि, बैंक खाता प्रतिलिपि, पांच छायाचित्र (पासपोर्ट साइज) तथा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र साथ लाना होगा।

क्या कहते हैं प्रबंध निदेशक

प्रबंध निदेशक डॉ0 एल सी शर्मा ने बताया कि इस प्रयास को पूरे प्रदेश में युवाओं के लिए चलाया जा रहा है तथा शनान से इसकी शुरुआत की जा चुकी है । प्रदेश में कौशल विकास निगम के सहयोग से युवाओं के लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से गुणवत्ता के साथ–साथ रोज़गार को सुनिश्चित बनाया जा रहा है ।

विशेष कला ज़रदोज़ी में आईआईआरडी की सराहनीय पहल

उत्तर प्रदेश में सैंकड़ों युवाओं को मिले रोजगार के अवसर

द रीव टाइम्स (हेमराज चौहान)

युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन के अलावा दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के अन्तर्गत सराहनीय प्रयास किए जा रहे है। इसी योजना के तहत आईआईआरडी द्वारा उत्तर प्रदेश के कासगंज तथा चंदौली ज़िलों में विशेष कला ज़रदोज़ी वर्क में युवाओं को क्रमवार प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसमें 380 प्रतिभागियों को प्रशिक्षत एवं रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य है। यह प्रशिक्षण केवल ग़रीबी रेखा से नीचे के परिवार के युवाओं को दिया जा रहा है । ज़रदोज़ी वर्क भारतवर्ष में अपनी कारीगरी और कला के लिए सदियों से एक विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। विशेष रुप से कढ़ाई कला के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी नए प्रारुप में आकर्षण का केन्द्र रहा है। इसमें ज़रदोज़ी के अलावा तोड़ा, चिकनकरी, कंथा, सूजनी, कसूती आदि शामिल है। कढ़ाई कला को बहुत बड़े पैमाने पर भारत ही नहीं विश्वभर में एक अलग मुकाम हासिल है जिसमें साधारण कपड़ों और ड्रैस से लेकर फैशन के बड़े उद्योगों में भी इस धमक देखे जा सकते हैं। ज़रदोज़ी कला को भारत में हस्तकलाओं में सबसे पुराना एवं सबसे खूबसूरत कला का दर्ज़ा दिया गया है । इसे जब हाथों से बनाया जाता है तो इसके लिए कारीगर को बहुत समर्पण और निरंतरता की आवश्यकता होती है। आप कहीं भी रहते हो या आपका कोई भी सामाजिक स्तर हो, ऐसा कोई ही शक़्स होगा जिसने ज़रदोज़ी कला की अद्भुद और मनमोहक कलाकारी को न देखा हो। 12वीं शताब्दी में दिल्ली के प्रथम तुर्को–अफगान सुलतान द्वारा लाई गई यह सुनहरी व सिल्वर ज़रदोज़ी कढ़ाई कला एक प्राचीन फारसी कला है तथा यह संपन्न हिंदुओं, मुस्लिमों एवं यूरोपियन में बेहद मशहूर हो गया । आज भारत के वाराणसी, आगरा, लखनऊ, रामपुर, बरेली और फरुख़ाबाद में इस प्राचीन कढ़ाई कला को बड़ी तादात में लोगों ने न केवल अपनाया बल्कि इसके संरक्षण में आज भी प्रयासरत है। इस धातु कढ़ाई

शेष पेज 3 पर...

मिशन रीव–2 सदस्यता– नये विकल्प, बेहतर सुविधाएं

मिशन रीव संस्करण–2 के तहत हिमाचल के गांवों में बसे आम लोगों के लिए कई नई सेवाओं का समावेश किया गया है। तकनिकी के साथ–साथ आवश्यकता आकलन का नया स्वरुप भी लोगों के सामने है। खास बात यह कि दूसरे संस्करण में मिशन की सदस्यता का स्वरुप आपकी अपनी इच्छानुसार तैयार किया गया है। अब यह सदस्य बनने वाले व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वह मिशन रीव के साथ किस तरह से जुड़ना चाहता है और सदस्य के तौर पर उसके क्या विशेषाधिकार रहेंगे। मिशन रीव से जुड़ने का आरंभिक चरण मिशन रीव की सदस्यता से शुरु होता है। मिशन रीव के पहले संस्करण में सदस्य बनने के लिए केवल एक विकल्प ही उपलब्ध था लेकिन मिशन रीव संस्करण –2 में सभी के पास तीन नए विकल्प मौजूद हैं। द रीव टाइम्स के इस अंक में हम आपको बता रहे हैं कि आप कैसे सरल और सुगम तरीके के साथ मिशन रीव के सदस्य बनकर सेवाओं का लाभ ले सकते हैं।

कैसे बने मिशन रीव के सदस्य

मिशन रीव संस्करण –2 के तहत सदस्यता लेने का ऑनलाइन विकल्प ही आपके पास है। इसके लिए सबसे पहले वेबपार्टल http://www.hrmsv2.missionriev.in पर लॉगइन करना होगा। इसके बाद आपके सामने डैशबोर्ड खुलेगा। इसमें तीन लॉगइन टैब खुलेंगे। सदस्य बनने के लिए सबसे पहले रजिस्टर मेंबर पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने मेंबरशिप फार्म खुलेगा। सबसे पहले फार्म में मेंबरशिप बाक्स पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने तीन विकल्प होंगे– मेंबर, लाइफटाइम और वालंटरी। अगर आप केवल एक साल के लिए सदस्य बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेंबर के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अगर आप आजीवन सदस्यता चाहते हैं तो इसके लिए लाइफटाइम पर और एच्छिक सदस्यता पर क्लिक करना होगा। उसके बाद फार्म में पूछी गई सभी भरनी होगी। पूरी जानकारी अपलोड करने के बाद सबमिट विकल्प पर क्लिक करें और अपनी चयनित सदस्यता के मुताबिक शुल्क का भुगतान करें। भुगतान करते ही आपको मेंबर आईडी मिलेगी। इसी के आधार पर आप आगे अपनी आवश्यकताओं का आकलन कर मिशन रीव की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं।

Welcome to IIRD
www.hrmsv2.missionriev.in

यहां समझे तीन तरह की सदस्यता

सामान्य सदस्यता– इस प्रकार की सदस्यता के तहत व्यक्ति के पास एक साल की सदस्यता लेने का विकल्प है। कोई भी व्यक्ति 2000 हजार का शुल्क देकर सामान्य सदस्यता का लाभ ले सकता है। यह सदस्यता हर साल रिन्यू करानी होगी। इस तरह की सदस्यता लेने पर सदस्य को कुल सेवा शुल्क पर 10 फीसदी छूट का लाभ मिलेगा।

आजीवन सदस्यता– इस प्रकार की सदस्यता के लिए सदस्य बनने वाले व्यक्ति को एक ही बार सदस्यता शुल्क अदा करना होगा और वह जीवन भर मिशन की सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकेगा। आजीवन सदस्यता लेने के लिए व्यक्ति को कुल 10 हजार शुल्क एकमुश्त देना होगा और उसके बाद कोई सदस्यता शुल्क व्यक्ति से नहीं लिया जाएगा। आजीवन सदस्यता लेने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हर साल सदस्य को अपनी सदस्यता का नवीकरण नहीं कराना पड़ेगा और सेवा शुल्क पर ही 15 फीसदी छूट आजीवन सदस्य को मिलती रहेगी।

स्वैच्छिक सदस्यता– इस तरह की सदस्यता लेने के लिए व्यक्ति को किसी तरह का शुल्क अदा नहीं करना होगा। लेकिन स्वैच्छिक सदस्य बनने वाले व्यक्ति को सेवा शुल्क में किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी।

सदस्यता में परिवार की परिभाषा

सदस्य बनने के साथ ही आपके परिवार के सदस्य भी मिशन रीव की सेवाएं लेने के लिए अधिकृत हो जाते हैं। लेकिन यहां परिवार के सदस्य की परिभाषा मिशन रीव के नियमों और शर्तों के मुताबिक समझना अहम है। मिशन रीव के तहत सदस्य के परिवार में केवल उन्हें ही परिवार का सदस्य माना जाएगा जिनका नाम सदस्य बनने वाले व्यक्ति के साथ राशन कार्ड में दर्ज होगा। यानि राशन कार्ड में जितने सदस्यों का नाम होगा, वह सभी मिशन की सेवाएं ले सकते हैं। परिवार के सभी सदस्यों का पूरा और सही विवरण फार्म में भरना होगा।

क्यों बने सदस्य –

हमारी टीम, आपको मिशन रीव के सदस्य बनने पर आपकी की जरूरतों की पहचान करेगी। इसके पश्चात आपकी जरूरतों एवं समस्याओ की चरणबद्ध तरीके से सूची बनाकर आपकी जरूरतों के मुताबिक सेवाएं एवं समाधान प्रदान करेंगी ।

उदाहरण के लिए, मान लीजिए अगर आप कृषि से संबंधित किसी योजना का लाभ लेना चाहते हैं लेकिन जानकारी और समय के अभाव में सेवालाभ से वंचित रह रहे हैं तो इन योजनाओं का लाभ लेने में मिशन प्रतिनिधि आपकी पूरी मदद करेगा। इसमें दस्तावेज तैयार कराने से लेकर अन्य तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी मिशन प्रतिनिधि की होगी। आपको इसके लिए नियम और शर्तों के मुताबिक कुल देयशुल्क अदा करना होगा।

HRMS - IIRD
hrmsv2.missionriev.in/index.php/registration

Membership Form

Membership Type	Member / ** Member 1 Years / *** Lifetime / * Volunteer	ई-मेल Mail	enter E-Mail
आधार नंबर AADHAR No.	Enter AADHAR No.	फोन नंबर Contact	Contact No.
आवेदक का नाम Applicant Name	Enter Applicant Name	राज्य State	Select State
पिता/पति का नाम Father/ Husbad Name	Enter Father/Husband Name	जिला Distt	Select District
जन्मतिथि D.B.O.	yyyy/MM/dd	खंड Block	Select Block
लिंग Gender	Select	पंचायत Panchayat	Select Panchayat
शैक्षणिक योग्यता Educational Qualification	Educational Qualification	पता Address	
सामाजिक श्रेणी	Select	आप किस प्रकार के घर में रहते है।	Select
परिवार का प्रकार	Select	आर्थिक स्थिति	Select

आय के मुख्य स्त्रोत एवं वार्षिक आय
The source of income and annual income

आय के स्त्रोत	कृषि	सरकारी नौकरी	प्राइवेट नौकरी	अपना बिज़नस	मज़दूरी	अन्य (उल्लेख करें)	कुल आय
वार्षिक आय							

Add Family Members

S.No.	Name	Relation with Member	DOB	Gender	Qualification	e-mail	Contact No	Adhar No.
		Father	mm/dd/yyyy	Select				

Add another line

Declaration: I solemnly declare & fully understand that being member of Mission of Mission RIEV. my family will be privileged to seek various promotional. informatory and skill based benefits as and when needed or sought for within the limited purview of the Mission as per annexure I and shall abide by the membership terms and corditionsof the Mission as per annexure II.

☐ I Agree Terms & Condition Annexure II. Submit

List of Services Provisioned under Mission RIEV

SERVICE DIVISIONS
Services

Health Division
- Swasthya Slate - For preliminary health screening with 12 Tests.
- Mobile Medical Lab – For detailed investigation on 78 parameters.
- Generic Medicine Outlets – For providing low cost medicines at door step
- Telemedicine- Complete treatment at home with online interaction with doctor
- Comprehensive Health Profiling and surveillance.

Agriculture Division
- Soil Test Labs - For supporting members and farmers.
- Manure Production – By facilitating farmers and buying back with bio-pesticide etc.
- Seeds & Implements - Various best quality and treated seeds and agri implements.
- MIDA- Feed supplement Cattle nutrient for animal yield enhancement.
- Promotion of Organic Farming, Agro based Micro Planning and handholding support to farmers.

Utility, Licenses & Online Service Division
- All Government grant and subsidy based Schemes
- Various Registrations, Licenses, NOCs and Certificates from Govt. and other relevant authorities
- Various Utility Services including water, electricity, connections and many more
- Other online services including estamps, complaints, claim settlements, , etc.

Entrepreneurship & Business Development Division
- Resource & Potential mapping, selection of business ideaResource & Potential mapping, selection of business idea.
- Orientation, Training and skill building
- Development of project Report, Bank Loans and business establishment
- Mentorship for one year
- Business Enhancement Support in existing business

Banking, Finance & Insurance Division
- Facilitation in Banking including savings, deposits, etc at door step

Education & Training Division
- Online Tutorials for Maths, Science, English and Others.
- Psychometric and

Social Security & Emergency Service Division
- Children Care, Elders Care, women empowerment and

Rural Produce Marketing Division
- Procurement of unique and healthy product and produce from

कि दुनिया देखती रह जाए

The membership will be governed by the following terms and conditions

1 मात्र यह फॉर्म भरकर सदस्यता के लिए आवेदन करने से सदस्यता की गारंटी नहीं मिलती है । निर्धारित सदस्यता शुल्क जमा किये जाने पर टीम मिशन रीव द्वारा उपयुक्त स्तर पर स्वीकृत प्रदान की जाएगी ।

That merely applying for membership by filling the form does not guarantee the membership until prescribed membership fee is deposited and approval is conveyed by the Team Mission RIEV at appropriate level.

2 यह सदस्यता पति–पत्नी, बच्चों और माता–पिता सहित पूरे परिवार के लिए लागू होगी और परिवार केवल राशन कार्ड के अनुसार ही माना जाएगा । राशन कार्ड की प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है।

That this membership shall be applicable for entire family comprising spouse, children & parents and shall be considered as per ration card only. (copy to be enclosed)

3 यह सदस्यता स्वयं ही सभी नियमों, शर्तो का पालन करने और मिशन व इसके संचालन की प्रक्रियाएं के लिए सदस्यों की ओर से स्वीकृति की पुष्टि है ।

That the membership itself is the confirmation of the member to abide by all the terms, conditions and procedures of the Mission and its operations.

4 सदस्य को कभी भी समयसीमा के भीतर उपलब्ध विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने का विशेषाधिकार होगा और यह "पहले आओ पहले पाओ" आधार पर होगा ।

That the member shall have privilege to avail various services available at any point of time within the framework and shall be on "First Come First Serve" basis.

5 सदस्यता आवेदन की अवधि मु. रू. 2000/– की अदायगी के साथ एक वर्ष के लिए एक कुश्त राशि 10,000/– रूपये की अदायगी के साथ जीवन भर के लिए तथा स्वैच्छिक सदस्यता बिना किसी शुल्क व समयावधि के भी होगी । स्वैच्छिक सदस्यता से वार्षिक सदस्यता के लिए या आजीवन सदस्यता के लिए उन्नयन सदस्यता प्राप्ति के तीन महीने की अवधि के बाद ही हो सकेगा ।

That the membership application period shall be Annual with the subscription of Rs. 2,000/- (Rs. Two Thousand Only); Lifetime with Rs. 10,000/- (Rs. Ten thousand only) and Voluntary without any subscription and specific periodicity. The upgradation from voluntary membership to annual paid or life time and annual paid to life time shall take place not before the period of 3 months of obtaining membership.

6 वार्षिक सदस्यता का प्रतिवर्ष समाप्ति अवधि से पूर्व नवीकरण करना होगा । नवीकरण की सदस्यता अवधि समाप्त होने पर नई सदस्यता मानी जाएगी तथा कालातीत अवधि की गणना अवधि आधारित लाभ के लिए यदि भविष्य में कुछ हो तो नहीं की जाएगी ।

That the annual membership shall have to be renewed every year before expiry. If renewed after expiry date, the membership shall be treated as new membership and the lapsed year shall not be counted for tenure specific benefits, if any, in future.

7 अनुलग्न । में उल्लिखित सेवाऐ संसाधनों की उपलब्धता, स्त्रोत और पात्रता की शर्तों और उसी अवधि जिसके लिए आवेदन किया है, के अनुसार लागु होगी ।

That the services as mentioned in the annexure I shall be subject to availability of resources, applicability from the source and eligibility conditions as be applicable during the period of applying for the same.

8 सेवाओं की मात्रा, परिमाण और आवृत्ति, विवेकपूर्ण आवश्यकताओं,संसाधनों की उपलब्धता और सेवाओं का लाभ लेने के लिए सदस्यों के प्रयासों में स्थिरता या मिशन के नियन्त्रण से परे अन्य कारक पर निर्भर करेगी ।

That the quantum, magnitude and frequency of the services shall depend on the judicious needs, availability of resources and consistency in members' efforts to avail the services or any other factor beyond the control of the Mission.

9 एक बार भुगतान किया गया सदस्यता शुल्क किसी भी मामले में वापसी योग्य नहीं होगा ।

That the membership fee once paid shall not be refundable in any case.

10 एक बार भुगतान किया गया सदस्यता शुल्क किसी भी मामले में वापसी योग्य 10 सदस्य का मिशन के विभिन्न सेवा उत्पादो, संचालनात्मक प्रक्रियाओ को समझने अपनी राय या सुझाव देने तथा मिशन के विभिन्न मंचों मे सक्रिय भागीदारी का विशेषाधिकार होगा तथा मिशन की परिभाषित सीमाओं के अधीन मिशन के प्रबन्धन दल का हिस्सा माना जाएगा।

That the member shall have privilege to understand different service products, procedural steps, share opinions and suggestions and avail opportunities of active participation in different forums under Mission RIEV; hence shall be treated the part of the management team within the defined jurisdiction of the Mission.

11 सदस्य बनना, व्यक्ति या परिवार का, बिना किसी स्वार्थ के मिशन के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए किया गया स्वैच्छिक कार्य है तथा एक वर्ष बाद इसका नवीकरण करना या नहीं, व्यक्ति की ईच्छा पर निर्भर करेगा ।

That becoming member is a voluntary action of the individual or the family to support and promote the objectives of the Mission without any expectations whatsoever in return and the member shall have the option whether to renew the membership after one year or not.

12 व्यक्तिगत या परिवार का सदस्य होने के नाते, मिशन के लिए निरंतर सलाह और संरक्षण प्रदान करने का दायित्व होगा और किसी भी मामले में जो मिशन के कार्य, कृत्य या प्रगति की कार्यप्रणाली को रोकते हैं, में शामिल नहीं होंगे। सभी कानूनी जटिलताओं और कुकदमों से सदस्य मिशन के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है । हालांकि, सभी कानूनी मामलों का क्षेत्राधिकार केवल शिमला होगा

That being member, the individual or family shall have the obligation to keep on providing constant mentoring support and patronage to the Mission and in no case shall get involved in any kinds of the act, deed or action which hampers the progress and smooth functioning of the Mission. The member commits to safeguard the interest of the Mission from all legal complications and to be abstained from litigations; however, all the legal matters shall be subject to Shimla jurisdiction only.

13 मिशन की ज्ञानात्मक, सूचनात्मक, कोशलात्मक तथा तकनीक आधारित नि:शुल्क सेवाओं को उपयोग का सदस्य के पास "पहले आओ पहले पाओ" पर आधारित विशेषाधिकार रहेगा, साथ ही जिन सेवाओं में अधिक गहनता होगी, इनका शुल्क समयानुसार निर्धारित दरों के अनुसार अतिरिक्त देय होगा ।

That the member shall have the privileges to avail complementary services of technical support nature to bridge the gaps on information, knowledge, skills & technology from the Panchayat Facilitators or other Mission functionaries on "First Come First Serve Basis"; the higher as well as deeper interventions of services shall attract different unit prices as be applicable from time to time.

14 सदस्यों को सरकार में या अन्य संगठन में आवेदन की प्रक्रिया के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान अतिरिक्त करना होगा ।

The members will have to pay the charges for the process of application in Govt. or other organisation as per applicability separately.

15 सदस्यों द्वारा दी गई जानकारी के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा

Members shall be responsible for the information provided by them.

16 भविष्य में सदस्य को सुचना दिए बिना नियम और शर्तों सहित सदस्यता में परिवर्तन या गुणात्मक संशोधन, कुछ जोड़ने और हटाने के लिए सदस्य की सहमती होगी । सभी उद्देश्यों के लिए मिशन प्रबंधन का निर्णय अंतिम और सभी पर बाध्यकारी होगा ।

.All the addition, deletion, modification, alteration or value addition in the modalities of the membership including terms & conditions in future, if any, shall be agreeable to the member with or without notification. The decision of the Mission Management shall be final and binding on all for all purposes.

17 सरकार या अन्य संगठन द्वारा आवेदन की प्रक्रिया में किसी भी देरी के लिए आईआईआरडी जिम्मेदार नहीं होगा। और गुणवत्ता और निष्पादन के संबंध में किसी भी विवाद के कारण मिशन रीव प्रबंधन और / या कोई भी यहां दिए गए नियमों और शर्तों में से किसी का उल्लंघन और किसी भी हानि, क्षति, दावों, लागतों और खर्चों के विरूद्ध जो खर्च किया जा सकता है सदस्य मिशन प्रबंधन की क्षतिपूर्ति करेगा ।

IIRD shall not be responsible for any delay in the process of application by Govt. or other organisation. And the member shall indemnify and keep indemnified the Mission Management against any loss, damage, claims, costs and expenses which may be incurred or suffered by Mission RIEV Management due to any disputes in respect of quality and performance and / or any breach of any of the terms and conditions herein contained.

पेज 1 का शेष.....

का अक्सर वैदिक साहित्य एवं रामायण व महाभारत महाकाव्य में वर्णन मिलता है। यहां यह करना सर्वोचित होगा कि यह प्राचीन कला आज भी बेहद ख़ूबसूरती और अपने कलाकारी से चेहरे पर मुस्कान लाता है। ज़रदोज़ी एक जटिल कला है तथा भारत के विभिन्न भागों में कुछ ही समुदायों में संरक्षित है। इसी कला को और अधिक बढ़ावा देने तथा संरक्षण हेतु इस प्रकार के प्रशिक्षण डीडीयूजीकेवाई के तहत आईआईआरडी उत्तर प्रदेश में करवा रहा है। इसे साड़ी, कपड़े, बुनाई, पर्स, शमीज़, सलवार, लहंगा, ब्लाउज़ आदि पर रेशम, मातियों एवं ज़री डिजाईन से तैयार किया जाता है। इसे महिला और पुरुष दोनों ही सीख रहे हैं तथा संस्था का प्रयास है कि समस्त प्रशिक्षुओं को बारी–बारी से शत–प्रतिशत रोजगार मुहैया करवाया जा सके।

द रीव टाइम्स की सोलन में बढ़ रही है मांग गुणवत्ता एवं विषयवस्तु के साथ मिल रही है सराहना

द रीव टाइम्स का 14 संस्करण आ चुका है तथा धीरे–धीरे इस विकासात्मक समाचार पत्र की मांग बढ़ती जा रही है। शिमला के अलावा अन्य ज़िलों में भी समाचार पत्र पहुंच रहा है। सोलन में भी नियमित रुप से लोगों तक इसकी उपलब्धता को सुनिश्चित बनाया जा रहा है। गांव–गांव तक इस समाचार पत्र के माध्यम से न केवल मुख्य ख़बरों को स्थान दिया जा रहा है बल्कि युवाओं और विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिता संबन्धि संपूर्ण जानकारियों को भी प्रकाशित किया जा रहा है। साथ ही सरकार की योजनाओं को भी प्रमुखता दी जा रही है।

हिमाचल प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 70वां गणतंत्र दिवस, शिमला में हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल

द रीव टाइम्स ब्यूरो

70वां गणतंत्र दिवस पूरे प्रदेश में उल्लास व उत्साह के साथ मनाया गया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने ऐतिहासिक रिज मैदान शिमला पर आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। राज्यपाल ने परेड का निरीक्षण किया और 22वीं राजपूत राईफल के कैप्टन विक्रम देव सिंह के नेतृत्व मे आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी ली। लेडी गवर्नर दर्शना देवी तथा मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर व मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी डॉ. साधना ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।

इस अवसर पर सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, एस.एस.बी., पूर्व सैनिकों, राज्य पुलिस, होमगार्ड, स्काउट्स एवं गाइड्स, एन. सी.सी. तथा एनएसएस इत्यादि की टुकड़ियों द्वारा मार्च पास्ट प्रस्तुत किया गया । इस दौरान प्रदेश के सभी जिलों के सांस्कृतिक दलों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा विकासात्मक गतिविधियों को प्रदर्शित करती झांकियां प्रस्तुत की गईं। महात्मा गांधी जी की 11 मई, 1921 में शिमला यात्रा पर आधारित विशेष झांकी आकर्षण का मुख्य केन्द्र रही । ऊना के सांस्कृतिक दल ने प्रथम स्थान, एनजेडसीसी राजस्थान ने द्वितीय तथा योगा प्रदर्शन दल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी

प्रकार झांकियों में उद्योग विभाग ने प्रथम स्थान, पर्यटन विभाग ने द्वितीय स्थान तथा जन मंच पर आधारित लघु नाटिका ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। एनसीसी 'लड़कियों' की टुकड़ी ने प्रथम स्थान, एनसीसी 'लड़कों' की टुकड़ी ने द्वितीय स्थान तथा एनएसएस 'लड़कियों' की टुकड़ी को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। राज्यपाल ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया, जिनमें ज्योतिका दत्ता, नरेश कुमार, सुमिता मेहता, शिवम कुमार तथा अभिनव भास्कर शामिल हैं। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, विधायक विनोद कुमार तथा बलबीर वर्मा, नगर निगम शिमला के उप–महापौर राकेश कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी, पुलिस महानिदेशक एस.आर. मरड़ी, प्रशासनिक, पुलिस तथा सेना के अधिकारी सहित शहर के गणमान्य व्यक्ति तथा अन्य लोग इस अवसर पर उपस्थित थे।

आईआईआरडी में धूमधाम से मनाई सुभाष चंद्र बोस जयंती हिंद सेवा संगठन ने भी मनाया स्थापना दिवस

टीम रीव, शिमला

हिंद सेवा संगठन की स्थापना महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस के अवसर पर ही की गई थी तथा संगठन ने बोस के जीवन पथ को आधार बनाकर समाजसेवा का जज़्बा लेकर ही अपनी यात्रा आरंभ की थी। आईआईआरडी राज्य कार्यालय में आयोजित सामारोह में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया गया। प्रबंध निदेशक डॉ0 एल सी शर्मा ने नेताजी के जीवन को आदर्श जीवन बताते हुए कहा कि एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन का समर्पण इस देश की आज़ादी और माटी की सेवा में लगा दिया वो सदैव हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा रहेगी। उन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर हिंद सेवा संगठन का प्रादुर्भाव हुआ तथा प्रदेश और देश की सेवा में इस संगठन ने अपने स्थापना से अब तक सेवाऐं दी हैं जो निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि नेताजी ने अपनी काबलियत और हिम्मत से अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर देशवासियों में भी आज़ादी के लिए अलख जगा दी थी।

निदेशक आईआईआरडी सुषमा शर्मा ने कहा कि हिंद सेवा संगठन से ही हमारे सभी विंग निकले और सामाजिक क्षेत्र में मिसाल कायम की है। यह संगठन नेताजी के आदर्शों को समर्पित है।

ज़िला शिमला में बीमा क्षेत्र में मिशन रीव देगा गांव–गांव में सेवाऐं

शिमला मिशन रीव कार्यकर्ताओं के लिए दिया जाएगा प्रशिक्षण

टीम रीव, शिमला

भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी के साथ एमओयू होने के बाद प्रदेश भर में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने हेतु मिशन रीव ने कमर कस ली है। ज़िला शिमला में भी मिशन रीव की टीम ने लोगों से संपर्क करने के बाद कार्य करना आरंभ कर दिया है। हालांकि सभी सेवाकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा उसके बाद जो लोग किन्ही कारणों से किसी भी प्रकार के बीमा दायरे से छूट गए हैं उन्हें सुरक्षा घेरे में लाया जाएगा तथा उनका बीमा करवाया जाएगा।

शिमला ज़िला के अतिरिक्त कार्यकारी प्रबंधक मिशन रीव अंकुश नगरैक ने बताया कि शिमला में टीम तैयार है तथा लोगों से इस बाबत संपर्क किया जा रहा है । मिशन रीव के तहत गांव में सभी को एक मज़बूत और सुरक्षित जीवन की ओर इस पहल को तीव्रता से आगे बढ़ाया जाएगा।

सामान्य ज्ञान

1 एम्स का निर्माण कब तक पूरा होगा, निर्माण का जिम्मा किस कंपनी को दिया गया है–2023 तक, नागार्जुन कंपनी

2 सातवीं आर्थिक जनगणना कब की जाएगी– वित्त वर्ष 2019–20 में

3 महाराष्ट्र की पुणे में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हिमाचल की कबड्डी टीम ने कौन सा मेडल प्राप्त किया– गोल्ड मेडल

4 हाल ही में किस पुलिस प्रशिक्षण केंद्र को गृह मंत्रालय की ओर से सम्मानित किया गया है–डरोह, यह 1992 में शुरू हुआ था

5 बीज स्वावलंबन के लिए गठबंधन विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहां किया गया– महाराष्ट्र के नवथान नगर में

6 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ– 2014 में

7 इस अभियान के तहत हिमाचल के किस जिले को कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए सम्मानित किया जाएगा–मंडी

8 जून 2019 में इन्वेस्टर मीट कहां आयोजित की जाएगी– धर्मशाला में

9 बीएसएनएल ने उपभोक्ताओं के लिए हाल ही में कौन सी सुविधा शुरू की है– फाइब्र टू होम सेवा। धर्मशाला सर्किल इस सेवा को शुरू करने वाला पहला सर्किल बना है।

10 हिमाचल के किस आईआईटी संस्थान ने इंटर आईटी टेक मीट–2018 के स्टार क्लस्टर आइडेंटिफायर हैकाथॉन में कांस्य पदक जीता– भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, यह सदर तहसील के तहत कमांद में है और इसकी स्थापना 2009 में की गई। टिमोथी ए गोनजालविस इसके निदेशक हैं।

11 उच्चतर शिक्षा विभाग ने मेधावी छात्रों को कोचिंग दिलाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है– मेधा प्रोत्साहन योजना

12 बिलासपुर के कोठीपुरा में बनने वाले एम्स की कक्षाएं कहां पर शुरू होंगी– लाल बहादुर शास्त्री मेडीकल कॉलेज नेरचौक

13 हिमाचल से संबंध रखने वाले किस डाक्टर को देश के पहले एमसीएच ट्रामा सर्जन बनने का गौरव प्राप्त हुआ है –सोलन जिला से संबंध रखने वाले डा. अमूल्य रत्न

14 पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट–2011 के तहत कितने विभागों को शामिल किया गया है। अधिनियम के तहत राज्य की जनता को 187 सेवाएं मिलेंगी।

15 खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी –2 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हिमाचल को किस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है–कर्मण्य पुरस्कार

16 ओलंपिक में देश को रजत पदक दिलाने वाले किस खिलाड़ी को डीएसपी बनाया गया है– स्पोर्टस शूटर विजय कुमार, हमीरपुर के बड़सर जिला से है और 2012 में लंदन में आयोजित 25 मीटर रेपिड फायर में सिल्वर मेडल विजेता रहे थे।

17 हिमाचल ने जिन दो राज्यों के साथ अंतररायीय परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं– जम्मू कश्मीर और उत्तर–प्रदेश के साथ– 1985 के बाद उत्तर प्रदेश के साथ इस तरह का यह पहला समझौता है।

18 हिमाचल के विख्यात संगीतरकार डाक्टर राजेंद्र गुरंग किस जिले से है– धर्मशाला के श्यामनगर से

19 हिमाचल सरकार की ओर से किस एजेंसी को नॉलेज पार्टनर बनाया गया है– अर्नेस्ट एंड यंग एडवाइजरी एजेंसी

20. श्रीराम लोकमंदिर कहां पर है– सोलन के कंडाघाट के तहत रूड़ा में

21. ठियोग– हाटकोटी कौन सा एनएचएच है– एनएच–5

22. हाल ही मंडी में किन दो स्थानों पर विद्युत उपकेंद्रों का शिलान्यास मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया– धर्मपुर के जंगेल में 132 केवी और मढ़ी 32 केवी का उपकेंद्र

23. हिमाचल में नीलक्रांति किससे सं बंधित है– मछली उत्पादन से

24 नौणी विवि के किस वैज्ञानिक को गुजरात में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा– डा.राजकुमार ठाकुर को मधुमक्खी पालन और आर्थिक कीट विज्ञान के लिए

25 फागली उत्सव कहां मनाया जाता है– कुल्लू के बंजार में थाटीबीड़ स्थित पल्ली घाटी , वासुकीदेवता के मंदिर में

26. हरियाणवी फिल्म पगड़ी : द ऑनर जिसे राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया है, की प्रोड्यूसर कौन है– धर्मशाला की वंदना शर्मा भाटिया

27. प्रदेश के कौन से जिले से महिला उत्पीड़न का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया – लाहुल स्पीति

28. खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 में एथलेटिक्स इंवेट में हिमाचल के जिस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता – अंकेश चौधरी ने

टीम रीव, शिमला

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आईआईआरडी के मुख्य कार्यालय शनान, संजौली में बेरोजगार युवाओं को सुनहरा अवसर प्राप्त होने जा रहा है । यहां फार्मेसी और आईटी आधारित जूनियर सॉफ्टवेयर डेवेलपर के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है । यह प्रशिक्षण प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आईआईआरडी द्वारा दिया जा रहा है । इसके लिए एक कार्यशाला का आयोजन कार्यालय परिसर में किया गया जिसमें इस प्रशिक्षण से संबन्धित समस्त जानकारियां दी गई । इस प्रशिक्षण में प्रदेश का कोई भी युवा प्रवेश ले सकता है जिसकी आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो तथा वांछित योग्यताओं को पूरा करता हो । युवाओं को इस प्रशिक्षण की जानकारी विभिन्न संचार माध्यमों से प्रदान की जाएगी । समाचार पत्रों में विज्ञापन, समाचार चैनल, पंपलैट्स आदि के अलावा जगह–जगह पर स्टॉल लगाकर भी जानकारी दी जाएगी ताकि अधिक से अधिक युवा इसमें जुड़कर लाभान्वित हो सकें।

आईआईआरडी और एनएसडीसी के संयुक्त तत्वाधान में

IIRD हम जानते हैं गाँव को बेहतर Institute for Integrated Rural Development · HPKVN · Skill India कौशल भारत - कुशल भारत · N·S·D·C National Skill Development Corporation Transforming the skill landscape · PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

कौशल विकास से आएगा निखार खुलेंगे रोजगार के द्वार

अंदोरा में योग शिविर का आयोजन

मिशन रीव के तहत दिए गए स्वस्थ रहने के टिप्स

टीम रीव, ऊना

मिशन रीव के तहत ग्रामीण क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधियों के साथ ही समाज कल्याण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का भी आयोजन किया जा रहा है। ऊना में मिशन रीव के तहत प्रतिनिधियों की ओर से रक्तदान शिविर और योग शिविरों का आयोजन समय –समय पर किया जा रहा है और लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के टिप्स भी दिए जा रहे है। हाल ही में इसी तरह के योग शिविर का आयोजन अंदोरा पंचायत में किया गया। इस दौरान पंचायत के सभी युवा, बुजुर्ग और महिलाओं ने योग शिविर में बढ़चढ़ कर भाग लिया। अंदोरा के लोगों ने बताया कि मिशन रीव गांव के विकास को लेकर अहम भूमिका अदा कर रहा है। रीव के तहत जहां लोगों को जरूरत का सामान घर पर ही मिल रहा है वहीं राजस्व अथवा अन्य विभागों के काम भी मिशन प्रतिनिधियों के माध्यम से आसानी से हो रहे हैं।

मिशन रीव की जानकारी दी

मिशन रीव संस्करण –2 में मिलेगी बेहतर सेवाएं

टीम रीव, ऊना

ऊना में हाल ही में मिशन रीव के दूसरे संस्करण का आगाज किया गया है। इस संस्करण के तहत कई नई सेवाओं को शामिल किया गया है। लोगों तक बेहतर सेवाएं पहुंचाने और उन्हें मिशन रीव के दूसरे संस्करण की जानकारी देने के लिए मिशन रीव प्रतिनिधियों की ओर से विशेष जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में लोगों को मिशन रीव संस्करण –2 के तहत गांवों में दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं और उन 10 सेवा प्रभागों के बारे में जानकारी दी जा रही है जो विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देने के लिए मिशन रीव संस्करण दो में शामिल किए गए हैं। इन सेवा प्रभागों में लोगों की आवश्यकताओं के मुताबिक सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसके साथ ही लोग स्वंय भी अपनी आवश्यकताओं का आकलन कर सकते हैं और किसी भी सरकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी सदस्य इन सेवाओं का लाभ लेना चाहता है तो वह मिशन रीव के माध्यम से आसानी से इन सेवाओं का लाभ ले सकता है। इसके अलावा भी अन्य कई बेहतर सेवाओं को दूसरे संस्करण में शामिल किया गया है।

स्कोन गांव में दी जैविक खाद बनाने की जानकारी

टीम रीव, ऊना

मिशन रीव के तहत प्रदेश के हर जिले में ग्रामीणों को खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऊना में भी जैविक खाद लोगों की आर्थिकी को मजबूत करने का जरिया बनता जा रहा है। गगरेट के गुगलैहड़ में पिछले दो सप्ताह के भीतर करीब 20 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए जिसमें 50 से अधिक लोगों को जैविक खाद तैयार करने की विधि बताई गई।

हाल ही में बंगाणा ब्लॉक के तहत स्कोन गांव में जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण गांव के लोगों लोगों को दिया गया। मिशन रीव प्रतिनिधि लवली ने बताया कि स्कोन गांव के जगरनाथ और उनके परिवार वालों को सबसे पहले बताया कि जैविक खाद के उपयोग के क्या लाभ है। उसके बाद खाद तैयार करने के लिए लिक्विड तैयार करवाया गया। अब अगले एक सप्ताह के भीतर खाद तैयार करने की प्रकिया शुरू कर दी जाएगी। स्कोन के अलावा अन्य गांव में भी लोगों को जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और गांव के लोग इससे काफी खुश है। उल्लेखनीय है कि इस खाद को तैयार करने के लिए जीरो बजटिंग खेती के तहत आईआईआरडी के प्रतिनिधियों की ओर से गांव – गांव जाकर किसानों और बागवानों को निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया गया। हाल ही में सोलन में भी मिशन रीव के प्रतिनिधियों की निगरानी में गांव वालों से खाद तैयार करवाई गई और खाद की बिक्री के लिए बाजार भी उपलब्ध कराया गया है। इस प्रयास की ग्रामीण क्षेत्रों में काफी सराहना हो रही है।लोगों का कहना है कि खाद बनाना तो आसान है पर उसकी बिक्री अभी तक मुश्किल थी लेकिन मिशन रीव ने उसे आसान बना दिया।

जैविक खाद के लाभ

- भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है।
- सिचाई अंतराल में वृद्धि होती है।
- रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है।
- फसलों की उत्पादकता में वृद्धि।
- मिट्टी की दृष्टि से लाभ
- जैविक खाद के उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है।
- भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती हैं।
- भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होगा।

पाठकों से अपील

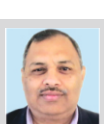

प्रिय पाठक वर्ग

पाक्षिक विकासात्मक समाचार पत्र 'द रीव टाइम्स' का 14वां अंक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है । आशा करता हूं कि पिछला अंक आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा होगा। द रीव टाइम्स लोगों को जीवन में प्रगतिशील बनने में कारगर सिद्ध हो, इसी उद्देश्य से आप की प्रतिक्रियाओं, आलोचनाओं, सुझावों तथा परामर्श को सादर आमंत्रित करते हैं ताकि विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने संबन्धि सभी पहलुओं का कमबद्ध समावेश किया जा सके।

आनन्द नायर प्रबन्ध संपादक

सड़क दुर्घटना में मिशन रीव प्रतिनिधि की मौत

मिशन अधिकारियों ने शोक संतप्त परिवार से की मुलाकात

टीम रीव, शिमला

बीते माह एक सड़क दुर्घटना में सोलन की सेर बनेड़ा पंचायत में बतौर मिशन रीव प्रतिनिधि कार्य कर रहे अरूण की मौत हो गई। अरूण दिसंबर 2017 से मिशन रीव के साथ जुड़े थे। इस दौरान उन्होंने बेहतरीन कार्य करते हुए मिशन रीव को अपनी पंचायत में एक अलग पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। इसके बाद मिशन रीव की ओर से शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की गई और मुश्किल की इस घड़ी में उन्हें हर संभव मदद देने का आश्वसान दिया गया। इतना ही नहीं अरूण के योगदान को देखते हुए मिशन रीव की ओर से उनके परिवार वालों को आर्थिक मदद भी दी गई। मिशन हैड आनंद नायर ने बताया कि अरूण का कार्य अच्छा था। उन्होंने कहा कि हाल ही में अरूण के परिवार वालों से मुलाकात की गई और उनका हाल भी जाना गया और कुछ आर्थिक मदद भी दी गई।

आर्थिक सहायता देने के साथ ही हर संभव मदद का दिया आश्वासन

घर पहुंचाया जरूरत का सामान

समय और पैसों की हो रही बचत

टीम रीव, ऊना

ऊना में मिशन रीव लोगों के जीवन में एक सहयोगी के तौर पर अपनी पहचान बना चुका है। मिशन रीव के तहत लोगों को स्वास्थ्य और कृषि संबंधि सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ ही लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों का सामान भी अपने स्तर पर उपलब्ध करा रहा है। मिशन रीव के तहत लोगों को विभिन्न तरह के उत्पाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रानिक सामान भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

हाल ही में मिशन रीव की ओर से गांव में लोगों की जरूरतों को पूछने के लिए मिशन प्रतिनिधियों की ओर से आवश्यकता आकलन किया। अंदरोटा में एक परिवार ने मिशन प्रतिनिधि अश्विनी को बताया कि उन्हें डबल बैड लेना है। लेकिन शोरूम जाना और वहां से सामान घर पहुंचाने का समय उन्हें नहीं मिल रहा। इसके बाद अश्विनी ने उस परिवार को शोरूम से डबलबैड घर तक पहुंचा कर दिया। इसी तरह गुगलैहड़, गगरेट और अन्य पंचायतों में भी लोगों की जरूरत का सभी सामान घर पर ही मिशन रीव के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें क्रॉकरी, इलेक्ट्रॉनिक व अन्य सामान भी लोगों को उनके घरों पर बाजार से बेहद कम दाम पर उपलब्ध कराया जा रहा है। मिशन रीव के तहत लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे विभिन्न तरह के सामान और सेवाओं से लोगों में भी काफी खुशी है। लोगों का कहना है कि पहले उन्हें छोटी – छोटी चीजों को खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ रहा था लेकिन अब मिशन रीव के तहत उन्हें हर तरह की सुविधाएं घर पर ही मिल रही है। इससे उनके समय और पैसे दोनों की ही बचत हो रही है।

लोगों की जरुरते समझने के लिए विशेष अभियान

स्वंय कर सकेंगे अपनी आवश्यक्ता आकलन

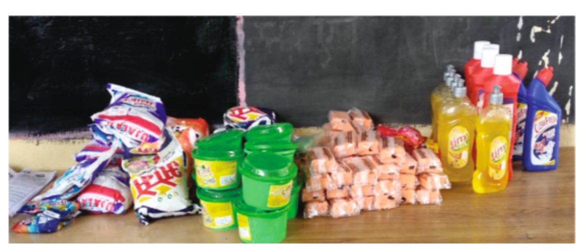

टीम रीव, सिरमौर

जिला सिरमौर में मिशन रीव संस्करण –2 के तहत विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए मिशन प्रतिनिधि गांव – गावं जाकर लोगों से उनकी जरूरतों को पूछेंगे और ऑनलाइन ही उन आवश्यकताओं का आकलन करेंगे। इसके अलावा मिशन के सदस्यों और गैर सदस्य स्वंय भी ऑनलाइन ही अपनी आवयश्यताओं का आकलन कर मिशन रीव की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसमें गांव के लोगों को मिशन रीव संस्करण दो के तहत उन सेवाओं की जानकारी दी जाएगी जो संस्करण एक में नहीं थी। इसके साथ ही लोगों को यह भी बताया जाएगा कि इन सेवाओं का लाभ कैसे लिया जा सकता है।

संस्करण दो के तहत मिशन रीव का प्राथमिक चरण इसके सदस्य बनने से आरंभ होता है। सदस्य बनने के लिए सर्वप्रथम ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। इसमें कुछ आधारभूत औपचारिकताओं को पूरा करना होता है। सदस्यता लेने के साथ ही आम जन अपनी चिंताओं को रीव के साथ साझा करने व समाधान के लिए संबद्व हो जाता है। इसमें उसका परिवार भी सेवाओ के लाभ का पात्र बन जाता है। द्वितीय संस्करण में सदस्यता प्रारुप अब और भी आसान और सरल प्रक्रिया में उपलब्ध है।

सदस्यता के बाद सबसे महत्वपूर्ण क़दम आवश्यकता आकलन का है जो कि आयु विशेष वर्ग को आधार बनाकर तैयार किया गया है। अपनी आयु वर्ग में अपनी आवश्यकताओं एवं समस्याओं को मात्र एक क्लिक करके समाधान तक की प्रकिया को ऑनलाईन देख सकता है। यह इस प्रकार का पोर्टल और ऑनलाइन सेवा है जिसमें समस्या / आवश्यकता पर क्लिक करते ही सामने उस समस्या के निदान के लिए किस विभाग या योजना से संपर्क करना है, उसका पूर्ण विवरण सामने आ जाता है। यानि समस्या के निदान की प्रकिया स्पष्ट रुप से सामने आ जाती है ।

उसके साथ ही उस सेवा के लिए भुगतान की जाने वाली राशि का पूर्ण विवरण भी सामने आ जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की मध्यस्तता की आवश्यकता ही नहीं रही और ऑनलाइन ही सारी सुविधाओं देखने, समझने और स्वीकार करने की यह एक अनूठी पहल है। शर्तो को स्वीकार करने के साथ ही मिशन रीव के स्वयंसेवक आपकी आवश्यकता आकलन को आधार बनाकर एक निश्चित समय के अंदर समाधान के लिए अनुबंधित हो जाते हैं।

आपके व्यवसाय को पंख देगा मिशन रीव

ग्रामीण युवा सीख सकेंगे स्वरोजगार के गुर

टीम रीव, कांगड़ा

ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के गुर सिखाने और पहले से स्थापित व्यवसाय को आगे ले जाने में मिशन रीव विशेष सहयोग करेगा। इससे जहां गांव के युवाओं को रोजगार के लिए गांव से बाहर नहीं जाना पड़ेगा वहीं गांव का विकास भी तेजी से होगा।

दरअसल आईआईआरडी की ओर से मिशन रीव उद्यमिता विकास कार्यक्रम (इडीपी) के तहत लघु/कुटिर उद्योग अथवा व्यवसाय स्थापित करने में पूरा सहयोग किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत आवेदक को पंजीकरण, अन्नापत्ति प्रमाण पत्र, लाइसेंस, प्रशिक्षण तथा व्यवसाय/उद्योग स्थापित करने आदि में संपूर्ण सहयोग दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण आवेदक को संबंधित जिला या आईआईआडी मुख्यालय में दिया जाएगा।

कार्यक्रम के उद्देश्य

- अपना व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक लोगों को मार्गदर्शन करना
- नए व्यवसाय को शुरू करने के लिए प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ना
- वांछित व्यवसाय शुरू करने के लिए उनकी क्षमता और कौशल का आकलन करना
- कम जोखिम में अधिकतम लाभ के सिद्धांत पर उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने में सहयोग देना
- उद्योग स्थापित करने के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना
- सर्वांगीण विकास में सहयोग करना
- भविष्य के लिए बेहतर योजना तैयार करने में सहयोग करना

ऐसे काम करेगा मिशन

अगर आप अपना कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो मिशन रीव उसमें एक सहयोगी के तौर पर आपका सहयोग करेगा। यहां पर बंद हो चुके व्यवसाय को पुनः शुरू करने का विकल्प भी मिशन रीव दे रहा है।

SELF - EMPLOYMENT

अगर आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो व्यवसाय शुरू करने से लेकर एक साल तक व्यवसाय स्थापित करने तक मिशन रीव आपके साथ रहेगा और आपके व्यवसाय को आगे ले जाने में पूरा सहयोग करेगा। इसके लिए जो भी दस्तावेजी औपचारिकताएं जैसे कि अन्नापति प्रमाण पत्र लेना, विभागीय अनुमति लेना, व्यवसाय शुरू करने से संबंधित योजनाओं की जानकारी, लोन का प्रबंध व अन्य दस्तावेजों से संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने में मिशन रीव व्यवसायी की पूरी मदद करेगा।

कैसे करें आवेदन

मिशन रीव के तहत इस योजना का लाभ लेने के लिए मिशन रीव की ओर से ऑनलाइन पोर्टल पर लिंक http://edp.missionriev.in उपलब्ध है। इस लिंक में दिशानिर्देशों के मुताबिक कोई भी अपना पंजीकरण करवा सकेगा। लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने स्कीम एप्लीकेशन खुलेगी। इसमें जैसे ही आप Select Scheme पर click करेंगे वैसे ही योजना का पूरा विवरण और इसके लिए योग्यता आदि जानकारी आपके सामने आ जाएगी।

आप अपनी इच्छा अनुसार उस योजना को चयनित कर सकते है जिसमें आप प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते है। इसके बाद निर्देशानुसार आपको अपने दस्तावेज अपलोड करने होंगे। पूरी जानकारी भरने के बाद अन्त में रजिस्टर बटन पर click करना होगा।

पंजीकरण होने के एक सप्ताह के भीतर आपको आपके द्वारा दिए हुए दूरभाष नं. अथवा ईमेल आईडी पर प्रशिक्षण की तिथि और स्थान के बारे में जानकारी दे दी जाएगी।

कृषि योजनाओं का लाभ चाहिए तो मिशन रीव से करें संपर्क

अब आसान हुई खेतों और बागीचों की देखभाल

टीम रीव, बिलासपुर

सरकार ने प्रदेश में कृषि के विकास के लिए अनेक योजनाएं बनाई है। लेकिन गांव के किसान जानकारी के अभाव में इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। किसानों की इसी समस्या को सुलझाने के लिए मिशन रीव की ओर से कृषि के विकास को लेकर विशेष पहल की जा रही है। अगर गांव के किसानो को कृषि से संबंधित किसी भी योजना की जानकारी प्राप्त करनी है तो वह मिशन रीव से प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही योजनाओं का लाभ लेने में भी मिशन पूर्ण सहयोग देगा।

अभी तक मिशन रीव के माध्यम से किसानों को सोलर स्प्रे पंप, उच्च किस्म के फसलों के बीज, फूलों के बीज उपलब्ध कराए जाते रहे हैं। अब खेतों की सिंचाई के लिए सरकार की सोलर पंप योजना का लाभ गांव के लोगों तक पहुंचाने में मिशन रीव सहयोग कर रहा है।

प्रदेश के अन्य जिलों की तरह जिला बिलासपुर में भी किसानों को इस योजना का लाभ लेने में सहयोग किया जाएगा।

क्या है सौर पंप योजना

साल 2022 तक देश के किसानों की आमदनी दोगुनी करने के केंद्र सरकार के लक्ष्य को पाने की दिशा में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप सेट खरीदने पर 90 से 100 फीसदी तक सब्सिडी देने का फैसला किया है।

कृषि और बागवानी उपज बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट में 20 करोड़ रुपये से सौर पंप योजना की शुरुआत की है। सौर पंप योजना की शुरुआत 9 अगस्त 2018 से की गयी है।

इसके तहत किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप खरीदने पर 90–100 फीसदी तक सब्सिडी मिलेगी। योजना के मुताबिक अगर किसान अकेले पंप लगवाना चाहता है तो पंप लगाने के लिए सरकार की ओर से 90 फीसदी सब्सिडी का प्रावधान है जबकि समूह बनाकर पंप लगवाने और पानी के स्रोत का प्रावधान होने पर 100 फीसदी सब्सिडी का प्रावधान है।

दरअसल किसान अब तक डीजल या बिजली से चलने वाले पंप से फसलों की सिंचाई करते हैं। इससे कृषि की लागत बढ़ती है। बिजली से चलने वाले सिंचाई प्रोजेक्ट पर भी लागत अधिक आती है। अब सौर पंप योजना से प्रदेश के दस लाख किसानों को लाभ मिलेगा। योजना के तहत सौर पंपों से सिंचाई के लिए पानी को उठाया जाएगा।

ग्रामीणो की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा का जिम्मा उठाएगा मिशन रीव

एलआईसी के साझेदार के तौर पर हमीरपुर में होगा काम

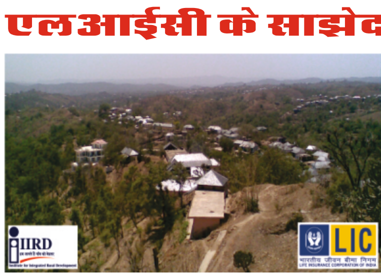

टीम हमीरपुर

हिमाचल में आज भी आधी आबादी ऐसी है जो न तो जीवन बीमा के महत्व को जानती है और न ही बीमा करवाना जरूरी समझती है। लेकिन जब जीवन में किसी तरह की आपदा आती है तो उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसे लोगों को बीमा के महत्व के बारे में बताने और उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में मिशन रीव एक जीवन सहयोगी के तौर पर काम करेगा।

आईआईआरडी ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्र में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के साथ साझेदारी कर राष्ट्रीय स्तर पर कॉर्पोरेट सदस्यता प्राप्त कर ली है। ये साझेदारी आईआरडीए के नियमों पर खरा उतरने के बाद हुई जिसके तहत अब संस्था विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे हिमाचल में तो लोगों को विभिन्न प्रकार का बीमा करवायेगी साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर भी राज्यों में इसका विस्तार किया जाएगा। हाल ही में चंबा से इस साझेदारी का आगाज किया गया है अब जल्द ही हमीरपुर में भी लोगों को यह सुविधा प्रदान की जाएगी।

गौरतलब है कि आईआईआरडी के जनोपयोगी प्रयास मिशन रीव ने हिमाचल प्रदेश के गांवों को विभिन्न सुविधाओं एवं कार्यक्रमों से जोड़ने का प्रयास किया है। लोगों को घर–द्वार पर सुविधाओं की सरल एवं गुणात्मक उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रीव के कार्यकर्ता सेवाएं दे रहे हैं। लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी संस्था ने मिशन रीव के माध्यम से लोगों को बीमा के दायरे में लाने का निर्णय लिया। इसके लिए भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ समझौता कर अब यह राह भी आसान हो गई है।

IRDA से प्रमाणीकरण एवं एलआईसी से साझेदारी के बाद प्रदेश के गांव–गांव में मिशन रीव के मज़बूत नेटवर्क के साथ लोगों को जीवन बीमा एवं अन्य प्रकार के समस्त आवश्यक बीमा हेतु जागरुक किया जाएगा तथा उन्हें आर्थिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाएगा। यह सुनिश्चित करने की मिशन रीव जिम्मेवारी लेगा कि कोई भी परिवार इस दायरे से बाहर न रहे। आकस्मिक दुर्घटना अथवा परिवार के मुखिया के साथ कोई अकस्मात घटना घटित हो जाने पर अंतिम समय में पड़ने वाले आर्थिक संकट के साथ–साथ पीछे छूट गए परिवार की आर्थिक सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। व्यक्तिगत सुरक्षा बीमा के अतिरिक्त सभी प्रकार के बीमा के लिए अब घर पर ही लोगों को सुविधाओं की उपलब्धता होगी। मिशन रीव इस के लिए प्रारंभिक योजना का प्रारुप तैयार कर इस पर कार्य आरंभ कर चुका है।

यह सारी प्रक्रिया बेहतर ऑनलाइन एवं ऑफलाईन प्रारुप के सहयोग से और अधिक सुगम्य बनाई जाएगी। बच्चों, जननी, युवा, बुजुर्ग यानि हर वर्ग के लिए बीमा के क्षेत्र में संबन्धित करने का लक्ष्य है। साथ ही वाहनों, संपत्ति, मकान, कार्यालय एवं अन्य समस्त प्रकार की बीमा को भी ग्रामीण क्षेत्रों में घर पर ही सुगम्य बनाया जाएगा।

मिशन रीव एलआईसी के सहयोग से देगा प्रशिक्षण

इस बड़े अभियान के लिए मिशन रीव के पास प्रदेश भर में कर्मियों का एक मज़बूत नेटवर्क है जो बीमा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देगा। इसके लिए मिशन रीव भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से इन चयनित रीव कर्मियों को प्रशिक्षण दे रहा है।

लोगों को दी मिशन रीव की जानकारी

टीम रीव, हमीरपुर

हमीरपुर के गांवों में लोगों को मिशन रीव के बारे में जानकारी देने के लिए विशेष अभियान चलाया गया हैं। इसके तहत मिशन के प्रतिनिधि लोगों के घर जाकर उनकी जरूरतों के बारे में पूछ रहे हैं और प्राथमिकता के आधार पर उन जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हमीरपुर में गांव के लोगों के साथ बैठक का आयोजन किया गया।

इस सभा के दौरान लोगों की जरूरतों को जानने के साथ ही द रीव टाइम समाचार पत्र भी लोगों को बांटा गया ताकि वह देश –दुनिया में होने वाली घटनाओं के बारे में अपडेट रह सके।

इसके बाद मिशन रीव के तहत गांवों में दी जा रही विभिन्न सेवाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर मिशन प्रतिनिधियों ने बताया कि मिशन रीव लोगों को उनके घर पर ही स्वास्थ्य संबंधि सुविधाएं भी दे रहा है।

इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी जरूरत पड़ती है तो उसमे भी मिशन रीव के प्रतिनिधि सहयोग कर रहे हैं।

जैविक खाद, मृदा जांच व सरकारी योजनाओं की दी जानकारी

स्वास्थ्य के अलावा कृषि, पशुपालन व ग्रामीण विकास से जुड़ी कई योजनाओं पर भी मिशन रीव कार्य कर रहा है। कृषि में जैविक खाद बनाने , मृदा जांच, उन्नत किस्म के बीज व अन्य उपकरण व अन्य सुविधाओं की जानकारी दी गई।

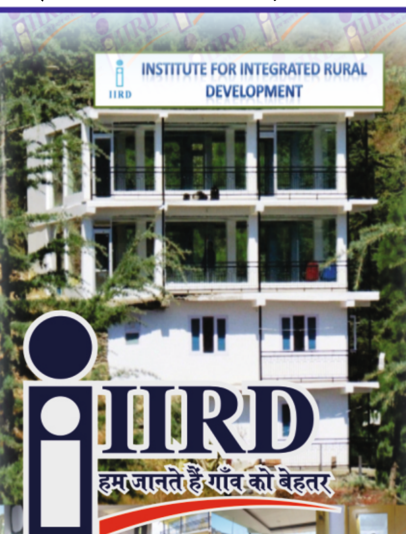

रीव जैविक खाद की मिशन रीव के अंतर्गत हिमाचल में उपलब्धता सुनिश्चित करवाई गई है। इसे प्राप्त करने के लिए इन दूरभाष नंबरों पर संपर्क करें.... 0177-2640761 और 0177-2843528, साथ ही आप हमारी वेबसाइट : missionriev.in / www.iirdshimla.org पर लॉगइन कर अधिक जानकारी ले सकते हैं।

पूर्ण जैविक हिमाचल की ओर बढ़ते क़दम........

रीव जैविक खाद

मिशन रीव किसानों को देगा विशेषज्ञ सेवाएं

बेहतर फसल उत्पादन में दिया जाएगा सहयोग

टीम रीव, कुल्लू

कुल्लू के विभिन्न जिलों में लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में लोगों को विभिन्न तरह की जानकारी मिशन प्रतिनिधियों की ओर से मुहैया करवाई जा रही है। हाल ही में इसी तरह के जागरूकता शिविरों का आयोजन कुल्लू की कुछ पंचायतों में किय गया। इनमें किसानों की ओर से कृषि से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी मांगी गई।

इसके अलावा कुल्लू के किसानों ने जैविक खाद के बारे में भी प्रशिक्षण शिविर लगाने की मांग की। शिविर के दौरान एक किसान सोहन लाल ने बताया कि उन्होंने करीब तीन माह पूर्व मिशन रीव की ओर से आयोजित एक कैंप में जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण के प्राप्त किया था। इसके बाद उन्होंने अपने घर पर खाद बनाना शुरू की। अब वह अपने खेतों में 80 फीसदी जैविक खाद का ही प्रयोग कर रहे हैं। अपने साथ ही गांव के दूसरे लोगों को भी वह जैविक खाद का उपयोग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सोहन लाल की तरह ही अन्य किसान भी जैविक खाद को लेकर खासी रूची दिखा रहे हैं। कुछ किसान जैविक खाद का निर्माण बाजार में बिक्री के लिए भी करना चाहते हैं। ऐसे में किसानों के लिए मिशन रीव के संस्करण–2 के तहत विशेष अभियान चलाने की तैयारी की जा रही हैं। इस संस्करण में किसानों की जरूरतों को देखते हुए खास तौर पर कृषि डिविजन तैयार किया गया है। इसमें प्रशिक्षण के अलावा किसानों को विशेष तौर पर सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही किसानों को उन योजनाओं का लाभ लेने में मिशन रीव की ओर से विशेष सहयोग दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कृषि विशेषज्ञों को साथ लेकर गांव के किसानों को कृषि के बेहतर तरीकों की भी जानकारी दी जाएगी। किसानों को मृदा जांच की भी सुविधा दी जाएगी। इसके लिए भी विशेषज्ञों की सहायता से किसानों को बताया जाएगा कि जांच के आधार पर वह कैसे अपने खेतों की मृदा का और अधिक उपजाऊ बना सकते हैं तथा मृदा को किस तरह के पाषक तत्वों की अधिक आवश्कता है।

कुछ समय पहले ही जगातसुख में मिशन रीव और अन्य विकासात्मक योजनाओं के बारे में लोगों को ग्रामसभा के दौरान जागरूक किया गया। ग्राम सभा के दौरान लोगों को बताया गया कि कैसे मिशन रीव के तहत विभिन्न तरह की सेवाएं गांव में लोगों को दी जा रही है। मिशन रीव के तहत ग्रामीणों के रोजमर्रा की वस्तुओं की आपूर्ति भी घर पर की जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य जांच और बेहतर कृषि पैदावार के लिए जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसके तहत जिला कुल्लू में अभी तक सैंकड़ो किसानों को जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। प्रशिक्षण के अलावा किसानों को खाद की बिक्री के लिए बाजार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इन सेवाओं के अलावा अन्य योजनाओं की जानकारी भी ग्रामसभा

नशे के खिलाफ जागरुकता के साथ प्यार्वरण सुरक्षा का भी पाठ

मिशन रीव के तहत चलेगा विशेष अभियान

टीम रीव, मंडी

वर्ष 2018 में सितंबर माह में आईआईआरडी की ओर से प्रदेश भर में नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए **जिंदगी जिएं नशें को नहीं** अभियान चलाया गया था। इस अभियान के दौरान पूरे प्रदेश में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया था। अब विभिन्न जिलों में मिशन रीव के तहत इस अभियान के तहत लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने का अभियान जारी है। इसी कड़ी में जिला मंडी में भी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है और लोगों को नशे के खिलाफ विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। अब इस अभियान के साथ ही लोगों को पर्यावरण स्वच्छता और सुरक्षा के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। तय योजना के मुताबिक खाली और अनुपयोगी पड़ी भूमि पर गांव के लोगों को पौधारोपण के लिए जागरूक किया जाएगा। इसमें वन विभाग की भी मदद ली जाएगी। इसके बाद नर्सरी तैयार करने में भी सहयोग किया जाएगा। इससे गांव के लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे और प्रदेश में वन क्षेत्र को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

सामाजिक कार्यो को करने के साथ ही मिशन रीव के तहत मंडी में कई कार्य किए जा रहे हैं। मिशन रीव के पहले संस्करण के दौरान किसानों को जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया गया और साथ ही विभिन्न तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं भी लोगों को उनके घर पर ही मुहैया करवाई गई। मंडी के भंगरोटू में खोला गया जनऔषधि केंद्र लोगों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो रहा है। लोगों को कहना है कि केंद्र से दवाईयां आसानी से मिल जाती है। अब दवाईयों के लिए बाजार के चक्कर नहीं काटने पड़ते और कई बार तो मिशन प्रतिनिधि घर पर ही दवाईयों पहुंचा देते हैं। इससे महिलाओं और बुजुर्गों को काफी राहत है। स्वास्थ्य के अलावा लोगों को जरूरत का अन्य सामान भी घर पर उपलब्ध कराया गया। अब जल्द ही मिशन रीव संस्करण –2 के तहत और भी बेहतर सुविधाएं मंडी के लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि और स्वास्थ्य के अलावा दूसरे संस्करण में अपना व्यवसाय स्थापित करने, वित्त से संबंधित समस्याओं को सुलझाने समेत दस विभिन्न सेवा प्रभागों के तहत ग्रामीण लोगों को सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

रैबीज के खतरे पर मिशन रीव कर रहा जागरुक

किलाड़ में पागल कुत्तों का आतंक

टीम रीव, चंबा

जनजातीय क्षेत्र पांगी के किलाड़ मुख्यालय में पागल कुत्तों ने बीतें दिनों 14 लोगों को काट कर लहूलुहान कर दिया। कुत्तों का शिकार बने लोगों का उपचार किलाड़ अस्पताल में किया गया। सभी लोगों को ऐंटी रैबिज के इंजेक्शन लगाए गए हैं।

रैबीज के खतरे को लेकर मिशन रीव की ओर से लोगों को समय मसय पर जागरूक किया जा रहा है। साथ ही लोगों को एंटी रैबीज टीके लगाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है।

मिशन रीव जिला समन्वयक ने बताया कि कि किलाड़ बाजार में बीते शाम को दो पागल कुत्ते आए और सड़क पर आवाजाही करने वाले राहगीरों पर टूट पड़े। कुत्तों ने करीब आठ लोगों को काटा। इसके बाद रात को इन लोगों को किलाड़ अस्पताल में एंटी रेबिज के इंजेक्शन लगवाए गए। राहगीरों को काटने के बाद पागल कुत्ते बाजार में फिर से आतंक मचाने लगे। इस दौरान कुत्तों ने तीन दुकानदारों और तीन राहगीरों को घायल कर दिया। इसके बाद लोगों के परिजन और अन्य लोग हाथ में डंडे लेकर कुत्तों को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़े। करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने दोनों कुत्तों को डंडो से पीट–पीट कर मार डाला। इतना ही नहीं पागल कुत्तों ने लोगों को काटने के साथ अन्य आवारा कुत्तों को भी शिकार बनाया है। इसको लेकर लोगों में डर है कि समय रहते आवारा कुत्तों को किलाड़ से नहीं निकाला गया तो वह भी लोगों पर हमला करना शुरू कर देंगे।

लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि किलाड़ से कुत्तों को हटाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। इसके साथ ही मिशन रीव की ओर से भी लोगों को कुत्तों से सावधन रहने और रैबीज के संभावित खतरों से निपटने के लिए जागरूक किया जा रहा है।

वहीं बीएमओ किलाड़ के मुताबिक किलाड़ में 14 लोगों को पागल कुत्तों ने काटा है। सभी लोगों को एंटी रैबिज के इंजेक्शन लगा दिए गए हैं।

जैविक खेती से बदल रही कृषि की तस्वीर

मिशन रीव से किसानों ने साझा किए अनुभव

टीम रीव, चंबा

हिमाचल में जैविक खेती का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के जिला चंबा में भी किसान जैविक खेती में खासी रूची दिखा रहे हैं। किसानों को जागरूक करने के अपने अभियान के दौरान जब मिशन रीव ने कुछ किसानों से बात की तो उन्होंने बताया कि जैविक खेती मुनाफे का सौदा साबित हो रही है। जिला चम्बा की परहनुई पंचायत के छोटे से गांव ढाका मोहरी के एक समृद्ध किसान पवन कुमार ने बताया कि कृषि ही उनका मुख्य व्यवसाय है। उन्होंने बताया कि वह पिछले काफी समय से जैविक खाद का इस्तेमाल सब्जियां उगाने में कर रहे हैं। इसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। पवन का कहना है कि उनके गांव के अन्य किसान भी जैविक खेती को अपनाना चाह रहे हैं। उन्होंने मिशन रीव की ओर से गांव के लोगों को जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण देने का भी स्वागत किया और कहा कि आज जैविक खाद समय की मांग है। ऐसे में मिशन रीव की ओर से जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जाना गांव के किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं।

मिशन रीव के तहत चंबा में तैयार हो रहा जैविक खाद का भंडार

हिमाचल को जैविक राज्य बनाने की दिशा में बड़ी उपलब्धि

टीम रीव, चंबा

हिमाचल की मिट्टी को रासायनिक खादों के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए मिशन रीव के तहत हिमाचल के किसानों को जैविक खाद का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसानों को जैविक खाद बनाने का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

प्रदेश की विभिन्न पंचायतों में ग्रामीणों को प्रशिक्षण देकर मिशन रीव के तहत जैविक खाद का भंडार तैयार किया गया है। पिछले कुछ समय से जिला चंबा में भी इसी तरह का प्रशिक्षण किसानों को दिया गया। प्रशिक्षण के बाद किसानों ने खाद बनाना शुरू की और इसमे सफल रहे। इस कार्य को करने में मिशन रीव के प्रतिनिधियों की ओर से पूरा सहयोग किया गया। इसके बाद किसानों ने इस खाद का इस्तेमाल अपने खेतों में करने के साथ ही दूसरे लोगों को भी खाद उपयोग करने के लिए दी। इसके काफी अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि इस खाद को तैयार करने के लिए जीरो बजटिंग खेती के तहत आईआईआरडी के प्रतिनिधियों की ओर से गांव गांव जाकर किसानों और बागवानों को निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके तहत आईआईआरडी के प्रतिनिधियों की निगरानी में गांव वालों से खाद तैयार करवाई गई और उनसे खरीदकर मिशन रीव के तहत उन्हें खाद की बिक्री के लिए बाजार भी उपलब्ध कराया गया है।

द रीव टाइम्स
आपकी आवाज़ ही है
हमारी आवाज़

मृदा परीक्षण से लाभान्वित होंगे किसान

मिशन रीव चंबा में किसानो को देगा सुविधा

टीम रीव, चंबा

मिशन रीव के अंतर्गत गांव में किसानों को मृदा जांच के लिए सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इसके लिए किसानों से गांव में जाकर जानकारी दी जा रही है और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश भी की जा रही है। हाल ही में जिला शिमला में मिशन रीव के कृषि प्रभाग से शशि किरण ने विकास खण्ड मशोबरा के विभिन्न गांवों का सर्वेक्षण किया और किसानों से बात की। उन्हें मृदा जांच के बारे में बताया और मिशन रीव द्वारा घर पर ही इस सुविधा को उपलब्ध करवाने की जानकारी दी। अब इसी तर्ज पर जिला चंबा में भी किसानों को मृदा परीक्षण की सुविधा मिशन रीव के तहत दी जाएगी। इसके लिए गांव में ही विशेष जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में विशेषज्ञों के माध्यम से किसानों को फसलों की पैदावार बढ़ाने के साथ ही मृदा परीक्षण के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके बाद जांच के लिए मिट्टी के नमूने कैसे लिए जाते हैं और जांच के आधार पर मृदा में कैसे पोषक तत्वों के संतुलन को बनाए रखा जा सकता है, इस बारे में भी विस्तार से जानकारी दी जाएगी। मृदा जांच में यह पता लग जाता है कि खेत को किन पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता है और किस प्रकार की फसलें खेत में लगानी होगी।

जानिए क्या होती है सीआरपीसी की धारा-144

अक्सर हम सभी सुनते या पढ़ते हैं कि पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा–144 लगा दी है । कहीं भी किसी भी शहर में हालात बिगड़ने की संभावना या किसी घटना के बाद धारा–144 लगा दी जाती है । आईए जानते हैं कि आखिर धारा–144 है क्या और इसका पालन न करने पर क्या सजा हो सकती है ।

क्या है धारा-144

सीआरपीसी के तहत आने वाली धारा–144 शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लगाई जाती है । इस धारा को लागू करने के लिए ज़िला मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी एक नोटिफिकेशन जारी करता है । और जिस जगह भी यह धारा लगाई जाती है, वहां चार या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। इस धारा को लागू किए जाने के बाद उस स्थान पर हथियारों के लाने ले जाने पर भी रोक लगा दी जाती है।

क्या है सजा का प्रावधान

धारा–144 का उल्लंघन करने वाले या इस धारा का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है । उस व्यक्ति की गिरफ्तारी धारा–107 या फिर धारा–151 के तहत की जा सकती है । इस धारा का उल्लंघन करने वाले या पालन नहीं करने के आरोपी को एक साल क़ैद की सजा भी हो सकती है । वैसे यह एक जमानती अपराध है, इसमें जमानत हो जाती है ।

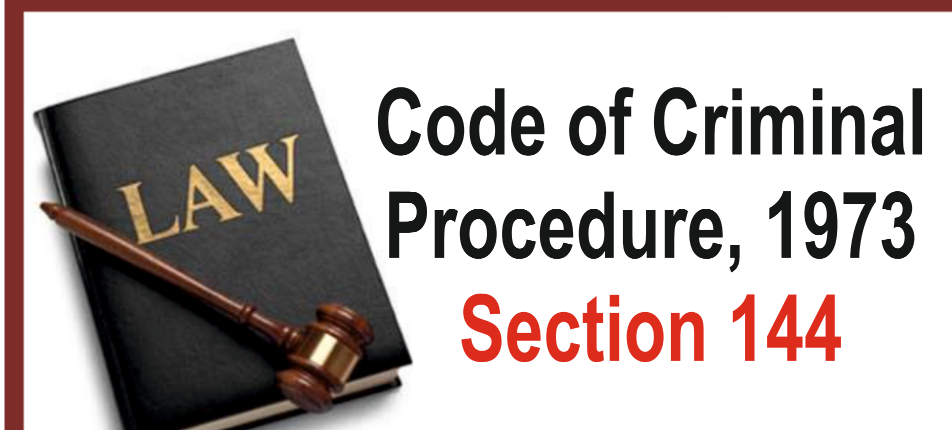

सीआरपीसी के तहत आने वाली धारा 144 शांति व्यवस्था को बनाये रखने के लिए लगायी जाती है। इस धारा को विशेष परिस्थितियों जैसी दंगा, लूटपाट, आगजनी, हिंसा, मारपीट को रोककर, फिर से शान्ति स्थापित करने के लिए किया जाता है। इस धारा को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसके बाद उस तनावपूर्ण इलाके में ये धारा लागू कर दी जाती है।

इस धारा के लागू होने के बाद, उस इलाके में 4 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते और उस क्षेत्र में हथियारों के लाने-ले जाने पर भी रोक लग जाती है। बाहर घूमने पर भी प्रतिबन्ध लगाया जाता है और यातायात को भी इस अवधि के लिए रोक दिया जाता है।

धारा 144 लागू होने के बाद इसका पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है और इसका पालन नहीं करने या धारा 144 का उल्लंघन करने पर, पुलिस द्वारा गिरफ्तारी भी की जा सकती है जो धारा 107 या धारा 151 के तहत होती है । इस धारा का उल्लंघन करने वाले आरोपी को एक साल कैद की सजा भी हो सकती है। वैसे ये एक जमानती अपराध है जिसमें जमानत हो जाती है ।

सीआरपीसी की धारा 144 अक्सर आपके शहर या आसपास के इलाके में लागू की जाती रही होगी, पर क्या कभी आपने यह जानने की कोशिश की कि धारा 144 क्या है और इसमें कौन कौन से प्रावधान हैं। क्यों इस धारा को लगाया जाता है और इसका पालन न करने से क्या क्या नुकसान हो सकता है।

आमतौर पर राज्यों और शहरों में धारा 144 शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए की जाती है लागू जब कहीं भी किसी हिंसा या तनाव के बाद इलाके का माहौल खराब होता है या खराब होने की संभावना होती है।

ऐसे हालात में जब तनाव बढ़ने की उम्मीद होती है तो धारा 144 को ऐहतियातन उस इलाके में लागू किया जाता है। यह मजिस्ट्रेट द्वारा जारी एक निषेधाज्ञा होती है, जिसमें आम जनता पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। आमतौर पर इसे दंगा, लूटपाट, आगजनी, हिंसा, मारपीट को रोकने तथा फिर से शांति की स्थापना के लिए किया जाता है।

धारा 144 समय समय पर एहतियात के तौर भी लगाई जाती है जिसमें लोगों को इन बातों का ध्यान रखना होता है।

1. अस्त्र–शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ को लेकर आने–जाने पर सामान्यतया प्रतिबंध होता है। केवल धार्मिक आधार पर व सुरक्षा में जुड़े लोगों को इससे अलग रखा जाता है।
2. पांच व उससे अधिक व्यक्ति को एक साथ एकत्रित होने, एक साथ मिलकर सभा करने या फिर उसके लिए प्रेरित करने पर प्रतिबंध होता है। पर मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारे, शवयात्रा, विवाह व बरात इत्यादि जैसे आयोजनों को इससे मुक्त रखा जाता है।
3. किसी व्यक्ति या समूह के बैनर, पोस्टर, पर्ची के जरिए ऐसे किसी प्रचार प्रचार को प्रतिबंधित किया जाता है, जो आम लोगों में डर, भय, असुरक्षा या क्षेत्र में अशांति पैदा करता हो।
4. जन समस्याओं की आड़ में धरने, प्रदर्शन, रेल रोको, चक्का जाम जैसे आयोजनों पर प्रतिबंध होता है।
5. प्रशासन ऐसे समूह व व्यक्ति को जिला या क्षेत्र विशेष से कुछ समय के लिए बाहर भी भेज सकता है, अगर उससे शांति व्यवस्था प्रभावित होती है।
6. धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई होती है, जिसमें एक महीने के करावास या 200 रुपए जुर्माने का प्रावधान है।
7. इस दौरान संदिग्ध लोगों को 107(16) में पाबंद किया जा सकता है।
8. अशांति फैलाने वालों की 151 के तहत गिरफ्तारी की जा सकती है।
9. वैसे तो यह जमानती अपराध है और मजिस्ट्रेट के पासे से ही जमानत हो जाया करती है। पर अगर जमानत न कराई जाय तो संबंधित व्यक्ति को जेल जाना पड़ता है।

एडवोकेट प्रदीप वर्मा
कानूनी सलाहकार, आईआईआरडी, 94180 25649

पाठकों के प्रश्न एवं कानूनी समस्याऐं सादर आमंत्रित है । आपके प्रश्नों के उत्तर हमारे कानून विशेषज्ञ ऐडवोकेट प्रदीप वर्मा अगले अंक में देंगे। प्रश्न हमारी मेल आई डी पर डालें therievtime@iirdshimla.org hem.raj@iirdshimla.org

स्पाइनल इंफेक्शन

दर्द से रुला देता है स्पाइनल इंफेक्शन, जानें इसके कारण लक्षण और बचाव

- यह इंफेक्शन बैक्टीरिया की वजह से ही होता है
- रक्तवाहिनियों के जरीए यह बैक्टीरिया रीढ़ की हड्डी तक फैल जाता है

- रक्तवाहिकाओं के जरिए बैक्टीरिया वर्टिब्रल डिस्क में फैल जाता है

स्पाइनल इन्फेक्शन एक तरह का रेयर इंफेक्शन है, जो रीढ़ की हड्डियों के बीच मौजूद डिस्क स्पेस कोशिकाओं और स्पाइनल कैनाल या उस के आसपास के सौफ्ट टिशूज को प्रभावित करता है। आमतौर पर यह इंफेक्शन बैक्टीरिया की वजह से ही होता है और रक्तवाहिनियों के ज़रिए यह बैक्टीरिया रीढ़ की हड्डी तक फैल जाता है। रक्तवाहिकाओं के जरिए बैक्टीरिया वर्टिब्रल डिस्क में फैल जाता है, जिस से डिस्क और उस के आसपास के हिस्सों में इंफेक्शन होने लगता है और डिसाइटिस होने का खतरा पैदा हो जाता है।

स्पाइनल इंफेक्शन के कारण

- कुछ परिस्थितियां स्पाइनल इंफेक्शन से पीडित मरीज की रोगप्रतिरोधक क्षमता पर काफी प्रभाव डालती हैं और मरीज की रोगप्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देती हैं ।
- इन में डाइबिटीज मैलिटस, रोगप्रतिरोधक क्षमता को दबाने या कम करने वाली दवा का इस्तेमाल, कुपोषण, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की हिस्ट्री और नसों के जरीए लिए जाने वाले

नशीले पदार्थों के सेवन जैसी परिस्थितियां शामिल हैं।

- स्पाइनल इंफेक्शन सामान्यतया स्टेफिलोकौकस औरियस बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो आमतौर पर हमारे शरीर की स्किन में रहता है। इस के अलावा इस्चेरिचिया कोली, जिसे ई कोलाई बैक्टीरिया भी कहा जाता है, उस से भी यह इन्फैक्शन हो सकता है। ज्यादातर स्पाइन इंफेक्शन लंबर स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी के मध्य या निचले हिस्से में होते हैं, क्योंकि इसी हिस्से से रीढ़ की हड्डी में ब्लड सप्लाई होता है।
- इस के बीच पैल्विक इन्फैक्शन, यूरिनरी या ब्लैडर इन्फैक्शन, निमोनिया या सौफ्ट टिशू इन्फैक्शन में होते हैं। नसों के जरीए लिए जाने वाले नशे से संबंधित इन्फैक्शन में ज्यादातर गरदन या सर्वाइकल स्पाइन प्रभावित होती है।

स्पाइनल इंफेक्शन के लक्षण

- वयस्कों में स्पाइनल इंफेक्शन बहुत धीमी गति से फैलता है और इसी वजह से उस के लक्षण बहुत कम नजर आते हैं, जिस के कारण काफी देर से इस का पता चलता है।
- कुछ मरीजों को तो डायग्नोज किए जाने के कुछ हफ्ते या महीने पहले ही इस के लक्षणों का एहसास होना शुरू हो जाता है। इसके लक्षण आमतौर पर गरदन या पीठ के किसी हिस्से में टिंडरनैस आने के साथ शुरू होते हैं और पारंपरिक दवा लेने और आराम करने के बावजूद मूवमेंट करते वक्त महसूस होने वाला दर्द कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता ही जाता है।

डॉ० के आर शांडिल
आईआईआरडी, शिमला
अधिक जानकारी के लिए लिखें: therievtime@iirdshimla.org

वो मंजर जब महात्मा गांधी को लगीं तीन गोलियां

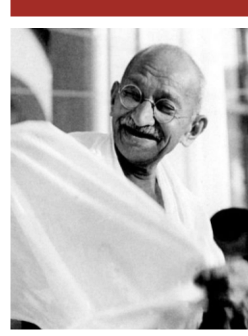

धाँय...धाँय...धाँय... ।' बंदूक से तीन गोलियाँ निकलीं । गोलियों की आवाज के बाद अगली आवाज थी 'हे...राम... ।' 65 साल पहले आज ही के दिन अहिंसा की प्रतिमूर्ति हिंसा की शिकार हुई थी । 30 जनवरी, 1948 का वह दिन भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति दिलाने के महासंग्राम के महानायक मोहनदास करमचंद गांधी का अंतिम दिन था और मुख से निकला 'हे राम' अंतिम शब्द था। गांधी जी ने अपने जीवन के 12 हजार 75 दिन स्वतंत्रता संग्राम में लगाए, परंतु उन्हें आजादी का सुकून मात्र 168 दिनों का ही मिला। नाथूराम गोडसे की बंदूक से निकली तीन गोलियाँ बापू के शरीर को छलनी करती गईं।

पहली गोली– बापू के शरीर के दो हिस्सों को जोड़ने वाली मध्य रेखा से साढ़े तीन इंच दाईं तरफ व नाभि से ढाई इंच ऊपर पेट में घुसी और पीठ को चीरते हुए निकल गई। गोली लगते ही बापू का कदम बढ़ाने को उठा पैर थम गया, लेकिन वे खड़े रहे।

दूसरी गोली– उसी रेखा से एक इंच दाईं तरफ पसलियों के बीच होकर घुसी और पीठ को चीरते हुए निकल गई। गोली लगते ही बापू का सफेद वस्त्र रक्तरंजित हो गया। उनका चेहरा सफेद पड़ गया और वंदन के लिए जुड़े हाथ अलग हो गए। क्षण भर वे अपनी सहयोगी आभा के कंधे पर अटके रहे। उनके मुंह से शब्द निकला हे राम। तीसरी गोली– सीने में दाईं तरफ मध्य रेखा से चार इंच दाईं ओर लगी और फेफड़े में जा घुसी। आभा और मनु ने गांधीजी का सिर अपने हाथ पर टिकाया। इस गोली के चलते ही बापू का शरीर ढेर होकर धरती पर गिर गया, चश्मा निकल गया और पैर से चप्पल भी। छा गई खामोशी : इन तीन गोलियों ने दो सौ वर्षों तक भारत को गुलामी की जंजीर में जकड़े रखने वाले अंग्रेजों को अहिंसक आंदोलन के जरिए झुका देने वाले महात्मा गांधी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया । साथ ही मौके पर सन्नाटा छा गया। हर कोई स्तब्ध रह गया। कई तो यह जान ही नहीं पाये कि हुआ क्या, लेकिन जब देखा, खून से लतपत बापू जमीन पर पड़े हैं, तो आंसुओं की मानो बाढ़ आ गई। तीन गोलियों ने बापू के तीन दशक के संघर्ष को पूरा कर दिया। आंधी आंखें खुली हुई थीं उन्हें बिरला भवन स्थित उनके खंड में ले जाया गया। आंखें आधी खुली हुई थीं। लग रहा था शरीर में अभी जान बची है। कुछ देर पहले ही बापू के पास से उठ कर गए सरदार पटेल तुरंत वापस आए। उन्होंने बापू की नाड़ी देखी। उन्हें लगा कि नाड़ी मंद गति से चल रही है। इसी बीच वहां हाजिर डॉ. द्वारका प्रसाद भार्गव पहुंचे। गोली लगने के दस मिनट बाद पहुंचे डॉ. भार्गव ने कहा, 'बापू को छोड़ कर गए दस मिनट हो चुके हैं।' मौके पर मौजूद लोग सिसक–सिसक कर रोने लगे। कुछ देर बाद डॉ. जीवराज मेहता आए और उन्होंने बापू की मृत्यु की पुष्टि की। रक्तरंजित वस्त्रों से लिपट गये नेहरू जानकारी मिलते ही पं. जवाहरलाल नेहरू पहुंचे। नेहरू गांधीजी के मृत शरीर के पास घुटनों के बल बैठे और बापू के रक्तरंजित वस्त्र में मुंह डाल कर रुदन करने लगे। इसके बाद गांधीजी के पुत्र देवदास और मौलाना अबुल कलाम आजाद भी पहुंचे । और फिर अगले दिन अगले दिन सुबह होते ही गांधीजी के सहयोगियों ने उनकी पार्थिव देह को नहलाया। गले में हाथ से काती हुई सूत की माला और एक अन्य माला पहनाई। ग्यारह बजे गांधीजी के तीसरे पुत्र रामदास नागपुर से पहुंचे। नई दिल्ली के अल्बुकर्क रोड पर से बापू की अंतिम यात्रा शुरू हुई, जिसमें करीब पंद्रह लाख लोग पहुंचे। सायं 4 बज कर 20 मिनट पर बापू की पार्थिव देह यमुना किनारे पहुंची और माहौल 'महात्मा गांधी की जय' के नारों से गूंज उठा। जब बापू बोले– अब जीने की इच्छा नहीं आजादी से पहले 125 वर्षों तक जीने की इच्छा व्यक्त करने वाले बापू स्वतंत्रता और विभाजन के बाद देश में भडके साम्प्रदायिक दंगों से निराश हो गए थे। उन्होंने आजादी के बाद 2 अक्टूबर, 1947 को पहली और आखिरी बार मनाए गए जन्म दिन के मौके पर कहा था, 'अब अधिक जीने की इच्छा नहीं है। मेरे बोल का वजन नहीं पड़ता है।' अक्सर इंसान किसी लक्ष्य के लिए संघर्ष करता है, तो उसका उस लक्ष्य को पाने के बाद उसे भोगने की भी इच्छा रखना भी स्वाभाविक है, लेकिन महात्मा गांधी का जीवन उस इंसान जैसा साबित हुआ, जो पेड़ तो लगाता है, लेकिन उसकी छाँव और फल की अपेक्षा नहीं करता। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए महात्मा गांधी ने 15 अगस्त, 1947 तक इस आंदोलन में हिस्सा लिया। कुल मिला कर उन्होंने 12 हजार 75 दिन स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित किए, लेकिन जिस आजादी के लिए उन्होंने जीवन के इतने दिन (करीब 27 वर्ष) समर्पित किए, उस आजादी की खुली हवा में वे केवल 168 दिन ही सांस ले सके।

साभार : ऑन लाइन

कुंभ मेले की निरंतरता की वाहक रही हमारी संस्कृति

हर बारह वर्षों के अंतराल में कुंभ मेले का आयोजन भारतवर्ष में चार स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन तथा नासिक में सदियों से होता रहा है तथा हर छह वर्षों बाद अर्द्धकुंभ। यह मानव समाज का इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा आयोजन होता है जहां करोड़ों की संख्या में लोग श्रद्धाभाव से त्रिवेणी में स्नान कर अपने आपको लाभान्वित समझते हैं। साधु समाज इस आयोजन को विशेष महत्व देते हैं और कंदराओं से यदाकदा निकलने वाले तपस्वी भी इस आयोजन में अवश्य पधारकर स्नान करके चुपचाप अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ते हैं। धार्मिक दृष्टि से यह पर्व सनातनी मान्यताओं में सर्वोपरी माना जाता है।

कहा जाता है कि कुंभ की पावन बेला पर ईश्वर स्वंय भी मेला स्थली में उपस्थित रहते हैं और कई ईश्वर तुल्य संत भी इस अवसर का लाभ लेने से नहीं चूकते। इस आशय का उल्लेख कई आद्यात्मिक प्रकाशनों में भी मिलता है तथा ऐसा ही उल्लेख परमहंस योगानंद के जीवन पर आधारित योगी कथामृत में भी मिलता है। सत्य जो भी हो, इस महामेले के आयोजन से ईश्वर के प्रति यदि आस्था बढ़ती है तो इसमें समाज में समरसता आती है। ईश्वर से

प्रेम करने वाले व्यक्ति अन्यों की अपेक्षा समाज के लिए अधिक उपयोगी होते हैं क्योंकि उन पर वातावरण में फैली बुराईयों का प्रभाव कम पड़ता है। यह इस महाआयोजन का सांसारिक लाभ है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य लाभ हो तो यह इसकी गूढ़ता जानने वाले व्यक्ति ही बता सकते हैं। लेकिन यह जानना आवश्यक है कि शास्त्रों का 'त्रिवेणी' व 'कुंभ' शब्दों से प्रायोजन क्या है। क्या यह वास्तव में वहीं स्थान है जहां तीन नदियों का संगम हो; वह त्रिवेणी और वही कुंभ।

यौगिक दृष्टि से देखें तो बात अंदर की हो जाती है क्योंकि शास्त्रों की रचना मात्र इस उद्देश्य से हुई कि मनुष्य स्वंय को जान सके। अर्थात आत्मसाक्षात्कार की ओर बढ़े। सभी बंधनों से मुक्त हो। कालांतर में अंदर की प्रक्रियाएं बाहर की वस्तुओं में परिवर्तित होती गई। यही बात शायद त्रिवेणी व कुंभ में भी लागू होती है। वास्तव में तीन नदियों की संज्ञा 'ईड़ा, पिंगला सुष्मना' को दी गई है। ईड़ा को गंगा, पिंगला को यमुना, और सुषम्ना को सरस्वति की संज्ञा दी गई है। जहां इन तीनों का संगम होता है वही त्रिवेणी है। हमारे शरीर में 'कुटस्थ' दोनों भृकुटियों के मध्य में, नाक की जड़ में, आंखों से ऊपर, इन तीनों का मिलन स्थान है। अतः यही संगम है, ज्ञान संकलनि तंत्र मे कहा हैः

ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदि
ईड़ा पिंगल्यो मध्ये सुष्मना च सरस्वति
त्रिवेणी संगमों यत्र तीर्थ राजः सः उच्चयते
तत्र स्नानाम प्रकुर्विता सर्वपापः प्रमुच्यते

इन तीनों नाड़ियों के माध्यम से हम दिन–रात श्वसन, पूरक, रेचक व कुंभक क्रियाएं करते रहते हैं। पूरक सांस का अंदर लेना, रेचक सांस का बाहर छोड़ना और सांस को अंदर रोकना आंतरिक कुंभक व बाहर रोकना बाह्य कुंभक कहलाता है। प्राणायाम श्वसन क्रिया की गति को धीरे–धीरे कम करते हुए श्वसन किया को पूर्ण रूप से बंद करने के उपरांत पूर्ण कुंभक की स्थिति में प्रवेश किया जा सकता है। यहीं वास्तव में 'त्रिवेणियों का कुंभ' है। यहीं से स्थितप्रज्ञता की स्थिति में प्रवेश किया जा सकता है। यहीं कुंभ मेले का वास्तविक आयोजन होता है।

डॉ0 एल सी शर्मा
प्रधान संपादक
md@iirdshimla.org

विश्वविद्यालय के नाम पत्र

बचपन में स्कूल की दिवार पर लिखा वाक्य, **'कम टू लर्न एंड गो टू सर्व'** ठीक से समझ नहीं आता था, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद सेवा करने का अवसर मिले या नहीं, कोई निश्चितता नहीं होती। यदि अवसर मिले भी, तो न जाने कहां जाकर काम करना पड़ेगा। वहां भी काम में लोगों की सेवा हो पाएगी या नहीं, न जाने काम कैसा होगा। उस समय वाक्य की व्यापकता समझ में नहीं आती थी।

बड़े होने पर समीकरण बदलने लगते हैं। कॉलेज की पढ़ाई के बाद जब प्रवेश विश्वविद्यालय में होता है तो पहले एक–दो वर्ष में डिग्री पूरी करने के कौतुहल में युं–त्यों बीत जाते है। आखिरी स्मेस्टर से आगे के समय पर चिंतन आरंभ हो जाता है। नौकरी के लिए हाथ–पांव मारने शुरू हो जाते हैं। उस समय डिग्री और परीक्षा की चिंता कम पर रोजगार से जुड़ी सूचनाओं को एकत्र करने , आवेदन करने और परीक्षा देने में व्यस्तता अधिक बनती जाती है। 133 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में सिमटती सरकारी नौकरियों में 99 प्रतिशत अभ्यर्थियों को निराशा मिलनी अपरिहार्य है। इसी कम को आगे बढ़ाने के लिए छात्र को एक डिग्री के बाद किसी दूसरी डिग्री में प्रवेश लेना अनिवार्य लगता है ताकि विश्वविद्यालय के हॉस्टल में जगह बनी रहे और नौकरी की तैयारियां भी होती रहे। इस प्रकार दो–तीन अतिरिक्त डिग्रियां भी मिल जाती है। लेकिन उनकी पढ़ाई मात्र पास होने के उदेश्य से हुई होती है क्योंकि मन पर रोजगार और अन्य चिंताएं हावी हुई होती है। ऐसे में न तो छात्र सामान्यतः प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रवीण बन पाते हैं और न ही अनुकूल रोजगार पाने में।

अंततः उम्र बढ़ने से विवाह की विवशताएं घेर लेती हैं और वापस गांव की ओर जाकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। यह एक सामान्य परिदृष्य हैं जहां लाखों माता–पिताओं के अपने बच्चों के लिए देखे गए स्वपन अधर में लटकते हैं और शेष जीवन निराशामय होकर गुजराना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है हमारी शिक्षा पद्धति दक्षता की ओर ठीक से बढ़ावा नहीं दे पाती। यदि ऐसा ही होना है तो जीवन के कीमती क्षण कोई क्यों विश्वविद्यालय में बिताए। यह बात कुशाग्र नहीं अपितु सामान्य स्तर के छात्रों पर लागू होती है। कुशाग्र तो येन–केन–प्रकारेण अपनी जगह बना ही लेते हैं पर उनकी संख्या एक प्रतिशत से अधिक नहीं होती।

यहां पर विश्वविद्यालयों के पास एक विकल्प हो सकता है 'कॉरपोरेट पार्टनरशिप' का। किसी ऐसे निकाय के साथ अनुबंध किया जा सकता जो छात्रों में आधारभूत कौशल पैदा कर उनके रोजगार की सही से व्यवस्था कर सके। यहां पर एक विशेष प्रकार के कौशल की बात नहीं जो विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत चल रहे हैं। अपितु बहुत ही आधारभूत जिससे कि व्यक्ति सही दिशा में चिंतन कर सके, अपने विचारों को परिस्थिति अनुसार नियोजित कर सके, अपनी बात दूसरों तक प्रभावी ढंग से पहुंचा सके और उसमें एक आदर्श कार्यकर्ता के गुण आ जाए। ये आधारभूत बातें छात्र को किसी भी रोजगार व व्यवसाय में आगे बढ़ने के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी।

मिशन रीव अगले तीन वर्षों में हिमाचल में करीब 35000 युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं तलाश रहा है और किसी भी विश्वविद्यालय के साथ करार कर इस दिशा मे आगे बढ़ने की संभावनाओं पर भी विचार कर रहा है।

संपर्क– डाक्टर शशी किरण
मो॰ 9418114449
shashi.riev@iirdshimla.org

डॉ0 एल सी शर्मा
प्रधान संपादक
md@iirdshimla.org

तुम मुझे खून दो– मैं तुम्हें आज़ादी दूगा

जानें सुभाष चंद्र बोस की कुछ जरुरी बातें...

1. सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी, 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था । उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था. जानकीनाथ कटक के मशहूर वकील थे ।

2. कटक में प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने रेवेनशा कॉलिजियेट स्कूल में दाखिला लिया । जिसके बाद उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की । 1919 में बीए की परीक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी से पास की, यूनिवर्सिटी में उन्हें दूसरा स्थान मिला था

3. उनके पिता की इच्छा थी कि सुभाष आईसीएस बनें. उन्होंने अपने पिता की यह इच्छा पूरी की । 1920 की आईसीएस परीक्षा में उन्होंने चौथा स्थान पाया मगर सुभाष का मन अंग्रेजों के अधीन काम करने का नहीं था । 22 अप्रैल 1921 को उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया ।

4. सुभाष चंद्र बोस की पहली मुलाकात गांधी जी से 20 जुलाई 1921 को हुई थी । गांधी जी की सलाह पर वे भारतीय स्वत्रंत्रता संग्राम के लिए काम करने लगे ।

5. वे जब कलकत्ता महापालिका के प्रमुख अधिकारी बने तो उन्होंने कलकत्ता के रास्तों का अंग्रेजी नाम हटाकर भारतीय नाम पर कर दिया ।

6. भारत की आजादी के साथ–साथ उनका जुड़ाव सामाजिक कार्यों में भी बना रहा । बंगाल की भयंकर बाढ़ में घिरे लोगों को उन्होंने भोजन, वस्त्र और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का साहसपूर्ण काम किया था । समाज सेवा का काम नियमित रूप से चलता रहे इसके लिए उन्होंने 'युवक–दल' की स्थापना की।

7. भगत सिंह को फांसी की सजा से रिहा कराने के लिए वे जेल से प्रयास कर रहे थे । उनकी रिहाई के लिए उन्होंने गांधी जी से बात की और कहा कि रिहाई के मुद्दे पर किया गया समझौता वे अंग्रेजों से तोड़ दें । इस समझौते के तहत जेल से भारतीय कैदियों के लिए रिहाई मांगी गई थी । गांधी जी ब्रिटिश सरकार को दिया गया वचन तोड़ने के लिए राजी नहीं हुए, जिसके बाद भगत सिंह को फांसी दे दी गई । इस घटना के बाद वे गांधी और कांग्रेस के काम करने के तरीके से बहुत नाराज हो गए थे ।

8. अपने सार्वजनिक जीवन में सुभाष को कुल 11 बार कारावास की सजा दी गई थी । सबसे पहले उन्हें 16 जुलाई 1921 को छह महीने का कारावास दिया गया था । 1941 में एक मुकदमे के सिलसिले में उन्हें कलकत्ता की अदालत में पेश होना था, तभी वे अपना घर छोड़कर चले गए और जर्मनी पहुंच गए । जर्मनी में उन्होंने हिटलर से मुलाकात की । अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध के लिए उन्होंने आजाद हिन्द फौज का गठन किया और युवाओं को 'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा' का नारा भी दिया ।

9. 1934 ई. में सुभाष अपना इलाज कराने के लिए ऑस्ट्रिया गए थे । उस समय उन्हें अपनी पुस्तक टाइप कराने के लिए एक टाइपिस्ट की जरूरत थी । उन्हें एमिली शेंकल नाम की एक टाइपिस्ट महिला मिली । 1942 में सुभाष ने इस टाइपिस्ट से शादी कर ली ।

10. 18 अगस्त 1945 को वे हवाई जहाज से मंचूरिया जा रहे थे । इस सफर के दौरान ताइहोकू हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उनकी मौत हो गई । उनकी मौत भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बनी हुई है । उनकी रहस्यमयी मौत पर समय–समय पर कई तरह की अटकलें सामने आती रहती हैं ।

हर तरफ है धुंआ.....धुंआ.......उबलता मौत का कुंआ

बीड़ी–सिगरेट ने हिमाचल की भी सेहत की ख़राब

हेमराज चौहान (सहायक संपादक)
chauhan.hemraj09@gmail.com

स्वास्थ्य से बड़ा धन इस ब्रह्मांड में तो कोई हो ही नहीं सकता। स्वस्थ मन में ही स्वस्थ आत्मा का वास होता है..........ऐसा कुछ बचपन से ही हम पढ़ते और सुनते बड़े हुए हैं। लेकिन इसकी समझ आज के समाज में इंसानों की दुर्दशा को देखते हुए धीरे–धीरे हो रही है। देश में बीड़ी–सिगरेट की बढ़ती खपत और कारोबार को देखते हए तो लगता है कि ये लत बड़े व्यापक पैमाने पर इंसानी पिंजरे को खोखला करती जा रही है। इसका पान करने वाला स्वयं तो नुकसान कर ही रहा है, साथ ही अपने आसपास के धुमपान न करने वालों को तो कई गुना अधिक नुकसान कर रहे हैं।

आंकड़े चौकाने वाले हैं ...

भारत देश में बीड़ी से लोगों की सेहत पर बहुत ग़लत असर पड़ा है। इतना ही नहीं भारत का एक अच्छा–खासा बजट भी लोगों की सेहत को लेकर खर्च किया जा रहा है। वर्ष 2017 में इसी प्रकार स्वास्थ्य पर एक बड़ा खर्चा सरकार ने वहन किया तो वहीं बीड़ी पीने वालों की अकस्मात मृत्यु का आंकड़ा भी बहुत बढ़ गया था। एक सर्वेक्षण के अनुसार हमारी जीडीपी का 0.5 प्रतिशत और कुल स्वास्थ्य पर खर्च बजट का 2.24 प्रतिशत इस पर ही खर्चा किया गया। भारत लगभग 80,550 / करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। यानि भारत को इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है।

- भारत में 72 मिलीयन लोग जो कि 15 वर्ष की आयुवर्ग से नीचे में आते हैं, बीड़ी पीते हैं। यह आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला है।
- 2016–2017 के एक सर्वेक्षण जो कि भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के संयुक्त तत्वावधान में करवाया गया था, में इस प्रकार के हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आए।
- वर्ष 2016–2017 में बीड़ी कारोबार से ही 417 करोड़ रुपये का राजस्व कर प्राप्त हुआ।
- बीड़ी कारोबार में रोजगार की भी अपार संभावनाऐं बनी रही है। देश में एक बड़ा वर्ग इस व्यवसाय से जुड़ा है। जिनकी आमदन इसी कारोबार पर निर्भर है।
- बीड़ी में सिगरेट से कम तंबाकु होता है। फिर भी यह ज़्यादा नुकसान करती है क्योंकि निकोटिन की बीड़ी में अधिक मात्रा होती है।
- बीड़ी से होने वाले नुकसान के कारण करीब 1.5 करोड़ लोग भयंकर ग़रीबी का सामना कर रहे हैं।

स्वास्थ्य के लिए बीड़ी सबसे अधिक घातक

बीड़ी और सिगरेट में एक ये बात असामान्य है कि बीड़ी पतली होती है तथा पीने वाला इसे अधिक पीता है यानि बीड़ी का टोटा तक पी जाता है। जबकि सिगरेट को फिल्टर तक पीकर धुम्रपान करने वाला फेंक देता है। बीड़ी पीने वाले को सिगरेट पीने वाले से अधिक ख़तरा रहता है क्योंकि बीड़ी अधिक नुकसान करती है। बीड़ी पतली होती है तथा तेंदु आदि पत्तों से बनाई जाती है जिसमें तंबाकु भरा जाता है। यह पत्ता ही सबसे अधिक हानिकारक होता है और उस पर तंबाकु के साथ इसका धुंआ फेफड़ों को गंभीर बीमारियों से ग्रस्त कर देता है।

यहां यह बात उल्लेखित करते हुए कहना ग़लत न होगा कि छोटी होने पर भी बीड़ी स्वास्थ्य के लिए घातक है। इसके पीने से कई प्रकार की बीमारियां शरीर में हो जाती है और धीरे–धीरे स्वस्थ्य व्यक्ति भी मौत के मुहाने पर खड़ा हो जाता है। कई प्रकार के कैंसर, टयूबोक्लोसिस, दिल की बीमारी, स्ट्रोक आदि बीड़ी सेवन से होते हैं। इसके लिए हर प्रकार का धुम्रपान जिम्मेवार है किंतु बीड़ी इसमें सबसे अधिक एवं शीघ्रता से नुकसानदायक होती है।

बनिस्पत सिगरेट के बीड़ी सस्ती

भारत के मज़दूर एवं किसान वर्ग में बीड़ी की खपत या यों कह लो कि मांग सबसे अधिक है। इस क्षेत्र में बीड़ी का साम्राज्य भारत के कोने–कोने में हैं। दूसरी ओर.. भारत में सिगरेट पर टैक्स बीड़ी से अधिक है। इसलिए सिगरेट मंहगी है और बीड़ी उसके बनिस्पत सस्ती। इस कारण भी बीड़ी की खपत अधिक है। बीड़ी की खपत लागत अनुपात में सिगरेट से कहीं अधिक है।

रोजगार का बड़ा अस्थाई जुगाड़

भारत में रोजगार के क्षेत्र में भी बीड़ी निर्माण कारोबार में एक बड़ा वर्ग शामिल है तथा एक स्थाई रोजगार न होने के बावजूद भी अच्छी आमदनी का ज़रिया बना हुआ है। इसे मजदूर पार्ट टाइम भी करके पैसा कमा रहे हैं। ऐसे में एक गंभीर एवं चुनौतीपूर्ण प्रश्न सामने खड़ा हो जाता है कि देश में आज भी

गुणवत्ता नियंत्रण (क्वालिटी कंट्रोल) नहीं है। इससे तेंदु पत्तों में तंबाकु के साथ और क्या–क्या भरा है, उसमें क्या डाला जाता है, उसकी मात्रा कितनी होती है... ...ये सभी कुछ सरकार या पीने वालों को पता नहीं है। इससे कहीं न कंही स्वास्थ्य के विनाश की मज़बूत नींव रखी जा चुकी है।

पुरुष ही नहीं महिलाऐं भी अब धुम्रपान में आगे

भारत में एक सर्वे के अनुसार वर्ष 2005 में धुम्रपान करने वाली महिलाओं की तादात महज़ 11 फीसद थी यानि इतनी महिलाऐं सिगरेट पीती थी , वहीं 2009 में यह 20 फीसद हो गई और वर्तमान में इस आंकड़े के दोगुना होने की बात सामने आ रही है। ग्रमीण महिलाओं में विशेषकर अधेड़ उम्र में बीड़ी की लत आज भी जस की तस बनी हुई है। आज भी गांव में महिलाऐं शौक के साथ बीड़ी का बंडल कुरते ही जेब में डाले धुंआ उड़ाते मिल जाएगी। वहीं लड़कियों में सिगरेट, शराब और अन्य प्रकार के नशों की लत बढ़ती ही जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों तक....स्थितियां बेकाबु होती जा रही है। सर्वे इस बात के साक्षी है कि लड़कियों में नशा या सिगरेट का कश फैशन और समाज में रुतबे के दिखावे का प्रतीक बन रहा है।

नहीं छोड़ सकते हम बीड़ी.....

ग्रामीण क्षेत्रों में हालात ऐसे हैं कि जो पुरुष या महिलाऐं बीड़ी पीते हैं उनके लिए यह जीने का ज़रिया है। रीव टाइम्स ने इस बाबत जब गांव में लोगों से बात की तो पता चला कि लोग इसके इतने आदी है कि खाना बेशक दिन में न मिले परन्तु बीड़ी पीने का टाइमटेबल बिल्कुल नहीं बदलता। मज़दूर काम करते समय थोड़ी–थोड़ी देर से बीड़ी पीते हैं। उसके बिना हाथ–पांओ काम नहीं करते। बहुत सी बुजुर्ग महिला सारा दिन बीड़ी का सेवन करती है। यहां तक कि नौजवान जो मज़दूरी करते हैं वो भी बीड़ी के शौकीन है। अब स्थितियां यहां ऐसी है कि जो नहीं भी पीता है उसे काम करते समय या घर पर अथवा साथ चलते हुए मजबूरन उस भयंकर धुऐं का पान करना ही पड़ता है जो कि सीधे बीड़ी पीने से भी अधिक घातक है। हैरानी तो तब होती है जब दादा–दादी अपने पौत्र–पौत्रियों को गोदी में बिठाकर बीड़ी पीते हैं और उन्हें दुलार भी करते रहते हैं। यह स्थिति हर ओर है। यह एक भयानक स्थित है क्योंकि बच्चों के मासूम हृदय पर इसका कितना विपरीत असर होता है .... यह शोचनीय है।

हिमाचल प्रदेश में भी स्थितियां बेकाबु

हिमाचल प्रदेश की ठंडक पर धुंए के छल्ले भारी पड़ते नज़र आ रहे हैं। यहां दिनोंदिन नशे के प्रति जागरुकता के बावजूद नशेड़ियों की तादात में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। इसमें युवावर्ग की संलिप्तता अधिक है।

- हिमाचल में धुम्रमान करने वालों में 88 प्रतिशत बीड़ी पीते हैं।
- प्रदेश में लोग सिगरेट के बजाए बीड़ी के रोगी अधिक बन रहे हैं।
- गैटस दो के सर्वेक्षण को आधार बनाए तो ये आंकड़े चौंकाने वाले है। हांलाकि 15 वर्ष की उम्र से अधिक वर्ग में तंबाकू का इस्तेमाल करने वाले अब 16.1 प्रतिशत ही रह गए हैं जबकि सात वर्ष पहले यह आंकड़ा 21.2 प्रतिशत था। यानि यहां तंबाकू के उपयोग में 24.6 प्रतिशत की कमी दर्ज़ की गई है।
- एक सरकारी सर्वेक्षण में यह भी खुलासा किया गया कि तंबाकु उत्पादों में बीड़ी पीने वालों की सबसे अधिक संख्या का समावेश है। सबसे अधिक 12.6 प्रतिशत व्यस्क बीड़ी का इस्तेमाल करते हैं। सिगरेट 208, खैनी 2. 06, हुक्का 0.05 और गुटखा 0.5 प्रतिशत व्यस्क लोग इस्तेमाल करते थे जिनका वर्तमान में आंकड़ा अनुमानतः बढ़ा हुआ है।
- हिमाचल में 26.7 प्रतिशत पुरुष एवं 1.6 प्रतिशत महिलाऐं धुम्रपान करते हैं। जबकि 14.2 प्रतिशत व्यवस्क स्मोकिंग करते हैं।
- इसके अलावा इंडोर कार्य करने वाले 12 प्रतिशत लोगों को सैंकड हैंड स्मोक की चपेट में आने के कारण जोखिम उठाना पड़ा। यह स्थिति तो अधिक घातक हो जाती है क्योंकि सैंकड हैंड स्मोक के दुष्परिणाम अत्यंत हानिकारक होते हैं।
- बीड़ी पीने वालों को मासिक खर्चा सिगरेट पीने वालों की तुलना में बढ़ा है।

धुम्रमान और शराब के बाद चिट्टे ने चिटकाया समाज

बीड़ी–सिगरेट और शराब के बाद अब चिट्टा ने हिमाचल की नींद उड़ा दी है। पूरा प्रदेश इसकी चपेट में आ गया है । चिट्टा, अफीम आदि के प्रतिदिन नए–नए मामले सामने आ रहे हैं । नशे पर ज़ीरो टॉलरैंस के बावजूद प्रदेश के युवा इसे धड़ल्ले से अपनी आमदनी और सुख का ज़रिया बना रहा है । इसके पीछे एक बड़ा माफिया काम कर रहा है । मात्र मामले पकड़ने तक ही सीमित नहीं है बल्कि इससे मौतें भी गाहे–ब–गाहे सुनने को मिल ही जाती है । युवा पीढ़ी की इस विनाशकारी दौड़ में समाज विखंडन की स्थिति में आ गया है । संस्थान, स्कूल, सार्वजनिक स्थल आदि पर नशे के साम्राज्य की छाप देखी जा सकती है ।

चलचित्र / सिनेमा ने भी किया आग में घी का काम

जितनी भी फिल्में हम देखते हैं उसका समाज से सीधा संबन्ध होता है जो आगे चलकर हमारे व्यवहार में कुछ न कुछ परिवर्तन के लिए जिम्मेवार होता है। आज सिनेमा फूहड़ता की हदें पार कर अधिकतर तो वही परोस रहा हैं जो

(ये होते हैं रोल मॉडल....तो क्या सीख मिलेगी)

समाज के भटके हुए लोगों को ही समर्थन करता है। फिल्मों में नशे का प्रचलन दिखाना.....गीतों और नृत्यों में खुलकर धुऐं के छल्लों और शराब का चलन....ये सब भी भटकाव की स्थिति पैदा करता है। गाने भी हदें पार कर चुकें हैं। 'बीड़ी जलाईले जिगर से पिया.....आज सारे दोस्तों ने महफिल बनाई सारी टेंशन धुंए में उड़ाई है.....धुंए का छल्ला बनाकर .....आदि आदि। ये गाने क्या संदेश देते है और इनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा....चिंता का विषय है। फिल्म आरंभ

होने पर या धुम्रमान का सीन आने पर मात्र ये लिख देने से कि धुम्रपान हानिकारक है..... इनकी जिम्मेवारी पूरी नहीं हो जाती है।

ज़िंदगी जिऐं–नशा नहीं....मुहिम ने हिमाचल में जगाई अलख

जनकल्याण में सेवारत संस्था आईआईआरडी ने हिमाचल में व्यापक पैमाने पर नशे के ख़िलाफ आवाज़ को बुलंद किया है। पूरे प्रदेश में सभी वर्गों को साथ लेकर नशे पर जागरुकता और जानकारी का आदान–प्रदान किया गया। प्रथम चरण में प्रदेश के अधिकतर विद्यालयों में स्कूली बच्चों को संभाषण प्रतियोगिताओं आदि से जागरुक किया गया। इसमें संस्था को युवा मंडलों, महिला मंडलों, स्वयं सहायता समूहों और प्रदेश सरकार का भी सहयोग प्राप्त हुआ। इसमें भी बड़े चौकाने वाले तथ्य सामने आए। स्कूली बच्चों को किस प्रकार नशे के जाल में फंसाया जाता है.....इसका खुलासा भी हुआ था। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश भर से चयनित विद्यार्थियों ने अपने उदबोधन से सरकार की आंखे भी खोलने का काम किया। इसका समापन प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने संस्था के राज्य कार्यालय शनान में किया था तथा संस्था के इस प्रयास को सराहा भी। उन्होंने कहा कि नशा प्रदेश को खोखला करता जा रहा है और ऐसे में संस्था के ये स्वैच्छिक प्रयास सर्वथा सराहनीय है।

ग़रीबीमुक्त भारत से पहले बीड़ीमुक्त भारत कैसे हो..........

भारत में तंबाकू उत्पादों की तादात में सरकार के नियंत्रण के दावे खोखले साबित हुए हैं। ज़मीन पर स्थितियों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं दिख रहा है। लोग नशे की चपेट से बाहर नहीं आ पा रहे हैं और बीड़ी–सिगरेट एक पारंपरिक नशा होने के साथ ही शरीर में रच–बस चुका है। हैरानी नई पीढ़ी के युवाओं को देखकर हो सकती है जिन्होंने इतनी जागरुकता के बावजूद इसे अपनाने की होड़ लगा रखी है। बीड़ी से होने वाले नुकसान के बाद स्वास्थ्य पर खर्च हो रहे लाखों–करोड़ों से स्वयं की आर्थिक स्थित तो डांवाडोल हो रही है साथ ही देश को हो रहे नुकसान की भरपाई भी न के बराबर ही है। ऐसे में ग़रीबी मुक्त भारत से पहले बीड़ी मुक्त भारत का सपना पहले साकार करने की आवश्यकता है। सरकार टैक्स राजस्व से पहले यहां के लोगों के स्वास्थ्य के राजस्व को प्राप्त करने की दिशा में सकारात्मक सोच के साथ नीति निर्माण और कार्यान्वयन के लिए सकारात्मक पहल करें।

तीन नए बीटेक कोर्स शुरु करेगा एनआईटी हमीरपुर

द रीव टाइम्स ब्यूरो

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) हमीरपुर में नए शैक्षणिक सत्र से तीन नए विभागों में बीटेक शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसे मंजूरी मिलने पर मैथेमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, फिजिक्स इंजीनियरिंग और बायोसाइंस एंड बायो इंजीनियरिंग में भी बीटेक की पढ़ाई होगी। यह संस्थान भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन है। सिनेट में मुहर लगने के बाद प्रस्ताव को बोर्ड ऑफ गवर्निंग में भेजा जाएगा। वर्तमान में आईआईटी बांबे और दिल्ली में ये बीटेक कोर्स चल रहे हैं।

बिलासपुर में दो साल में बनकर तैयार होगा एम्स जनता को मिलेंगी ये सुविधाएं

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश के लिए सोमवार का दिन ऐतिहासिक रहा। बिलासपुर के कोठीपुरा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के भूमि पूजन करने के साथ एम्स के भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया। कुल 1351 करोड़ के एम्स प्रोजेक्ट को नामी कंपनी नागार्जुन बनाएगी।

इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि दो साल में एम्स भवन तैयार कर दिया जाएगा। इस साल अगस्त माह में एम्स की ओपीडी शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए छह माह के भीतर कोठीपुरा में ही एक भवन बना दिया जाएगा।

विधायकों की सीलिंग बढ़ाने से सरकार का इनकार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल में विधायकों के दिल्ली और चंडीगढ़ में ठहरने में हो रहे खर्च की सीलिंग नहीं बढ़ेगी। प्रदेश सरकार ने सीलिंग बढ़ाने से इनकार कर दिया है। सरकार ने भले ही विधायकों को दिल्ली और चंडीगढ़ के निजी होटलों में ठहरने के लिए साढ़े सात हजार रुपये तक के कमरे की छूट दी हो, लेकिन वे यह खर्च ढाई लाख रुपये की सीलिंग के भीतर ही कर पाएंगे। यानी साल में इन विधायकों को ढाई लाख रुपये से ज्यादा खर्च नहीं मिलेगा। अभी तक प्रदेश सरकार विधायकों के दिल्ली और चंडीगढ़ में महंगे होटलों में ठहरने के सारे बिल पास नहीं किए जाते थे। ऐसे में इन विधायकों को हिमाचल भवन या सदन में ही ठहरना होता था। विधायकों ने तर्क दिया है कि सरकार के इन होटलों में बुकिंग रहती है।

मलाणा के नाम से बिक रही नेपाल की चरस: एसआर मरडी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

कुल्लू के साथ देश–विदेश में नेपाल से आने वाली चरस को मलाणा की चरस के नाम से बेचा जा रहा है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक एसआर मरडी ने कुल्लू में यह बात कही। उन्होंने कहा कि नेपाल की चरस को मलाणा के नाम से बेचना माफिया व तस्करों के लिए मुनाफे का सौदा है।

बिजली का स्मार्ट मीटर दूर करेगा बिल का झंझट

द रीव टाइम्स ब्यूरो

बिजली का बिल और उसका भुगतान करना अब जल्द ही पुरानी बात हो जाएगी। बिजली का इस्तेमाल करने के लिए उपभोक्ताओं प्री–पेड रिचार्ज करवाना पड़ेगा। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने एक विशेष प्री–पेड मीटर तैयार किया है।

हालांकि धरातल पर लागू करने से पहले इस मीटर की जांच–परख की जा रही है। इसके बाद सरकार की ओर से बिजली विभाग में प्री–पेड मीटर की विशेष योजना को लागू कर दिया जाएगा। इस मीटर के जरिए उपभोक्ता मोबाइल रिचार्ज की तरह ही बिजली रिचार्ज करवा सकेंगे। सूत्रों के अनुसार एक अप्रैल तक इस तरह के मीटर लोगों की सुविधा के लिए स्थापित किए जा सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि रिचार्ज खत्म होने पर बत्ती गुल हो जाएगी। खासकर विभाग को इससे भारी–भरकम बिलों की अदायगी के झंझट से भी निजात मिलेगी।

प्राइवेट स्कूलों में 12 साल में दोगुना बढ़ गए दाखिले

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का चलन बढ़ता जा रहा है। बीते 12 साल के दौरान प्राइवेट स्कूलों में दाखिले दोगुने से ज्यादा हो गए। साल 2006 में प्राइवेट स्कूलों में दाखिले 19 फीसदी थे, जो 2018 तक बढ़कर 40.7 फीसदी हो गए।

प्राइवेट स्कूलों की भारी–भरकम फीस होने के बावजूद अभिभावक सरकारी स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते। एनुअल स्टेटस आफ एजुकेशन रिपोर्ट (असर) 2018 में यह खुलासा हुआ है। प्रदेश के 12 जिलों के 358 गांवों में हुए सर्वे के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है।

निगम लापरवाह, लैप्स हो गया गरीबों को बसाने के लिए मिला करोड़ों रुपया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

शहरी गरीब परिवारों और तहबाजारियों को बसाने के लिए केंद्र सरकार से मिली करोड़ों रुपये की ग्रांट लैप्स हो गई है। नगर निगम की लापरवाही के चलते अब इन प्रोजेक्टों के लटकने का संकट खड़ा हो गया है। कैग रिपोर्ट में यह चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।

इनमें लिफ्ट के पास बन रहा निगम का महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट आजीविका भवन भी शामिल हैं। इस भवन में 222 दुकानें बननी है जिसमें शहर की तिब्बती मार्केट और पंजीकृत तहबाजारियों को शिफ्ट करने का दावा था। केंद्र से इस प्रोजेक्ट के लिए करीब ढाई करोड़ मिलने थे जिसकी पहली किस्त जारी हो चुकी है। कैग रिपोर्ट के अनुसार चौलेंज फंड के तहत इस भवन का निर्माण जून 2015 तक पूरा किया जाना था लेकिन यह लटक गया।

हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले में भूकंप के झटके

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले में मंगलवार की शाम में निम्न तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की वजह से जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। शिमला मौसम केंद्र के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया, 'मंगलवार की शाम में रिक्टर पैमाने पर 3.5 तीव्रता का भूकंप का झटका महसूस किया गया।' उन्होंने बताया कि भूकंप का केंद्र चंबा जिले के पूर्वोत्तर में 10 किलोमीटर की गहराई में था। उन्होंने बताया कि आसपास के इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए।

हिमाचल में बर्फ से लकदक हुए पहाड़ बर्फबारी से ऐसा नजर आया शिमला

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल में सोमवार रात से भारी बर्फबारी का दौर जारी रहा। शिमला समेत प्रदेश के नौ जिले बर्फ से पूरी तरह प्रभावित हुए। आधे हिमाचल में व्हाइट कर्फ्यू जैसे हालात हैं। पांच नेशनल हाईवे और 500 के करीब छोटी–बड़ी सड़कें भी इस दौरान बंद हो गई। शिमला में 45, कुफरी में 60 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड हुई। 2017 में राजधानी शिमला में जनवरी माह में 82.7 सेंटीमीटर बर्फ पड़ी थी। रोहतांग में सबसे ज्यादा 100 सेंटीमीटर हिमपात हुआ है। शिमला, मनाली, डलहौजी, रामपुर, रोहडू, किन्नौर, लाहौल देश दुनिया से कट गए।

शिमला सहित हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी से बढ़ी ठंड

शिमला सहित समूचे हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है। वहीं निचले क्षेत्रों में जमकर बारिश से किसानों बागवानों ने राहत की सांस ली है। बर्फबारी और बारिश से प्रदेश शीतलहर की चपेट में आ गया है। ठंड अपने चरम पर है। इस बार जनवरी में बर्फबारी ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इससे पर्यटकों की आवाजाही तो बढ़ ही गई है लेकिन स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

इस साल इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बजट खर्च करेगी प्रदेश सरकार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

जयराम सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र के विभागों पर सबसे ज्यादा बजट खर्च करेगी। नई योजना में सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र पहली प्राथमिकता होगी। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा 3048.5 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है। यह कुल व्यय का 42.93 प्रतिशत होगा। राज्य योजना बोर्ड ने 7100 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना मंजूर की है

राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। गत वर्ष की वार्षिक योजना पिछले साल की 6300 करोड़ रुपये से 800 करोड़ रुपये अधिक है। यानी 12.70 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसमें सामाजिक सेवा क्षेत्र, परिवहन, संचार, कृषि, संबंधित गतिविधियों, ऊर्जा, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण आदि को अतिरिक्त प्राथमिकता दी गई है।

इस बोर्ड की बैठक में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सामाजिक सेवा क्षेत्र के लिए 3048.15 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान होगा। परिवहन एवं संचार क्षेत्रों को द्वितीय प्राथमिकता में रखा गया है, जिसके लिए 1241.98 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।

यह कुल व्यय का 14.49 प्रतिशत है। गांवों को यातायात योग्य सड़कों के निर्माण तथा पहले से मौजूद अधोसंरचना के रखरखाव के लिए ऐसा किया गया है। तीसरी प्राथमिकता कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों को रहेगी।

शिमला में दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें मनाली के बाद राजधानी में 14 तक पहुंचेंगी 30 गाड़ियां

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मनाली के बाद अब शिमला में भी जल्द इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में शिमला के लिए बसें तैयार कर दी हैं, जो 14 फरवरी तक शिमला पहुंच जाएंगी। इसके पश्चात अन्य औपचारिकताएं पूरा होते ही राजधानी की सड़कों पर भी इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आएंगी। पथ परिवहन निगम के नौ सदस्यीय दल ने हाल ही में शिमला के लिए तैयार इलेक्ट्रिक बस का निरीक्षण किया है। यह ट्रायल सफल रहा।

शहर में चलेंगी 31 सीटर बसें

शिमला में चलने वाली इलेक्ट्रिक बसें नौ मीटर लंबी होंगी, जो 31 सीटर होंगी। मनाली में 25 सीटर बसें चल रही हैं, लेकिन मनाली में चलने वाली बसों के चार्जिंग में छह घंटे तक का समय लगता है, जबकि शिमला के लिए तैयार बसें आधे घंटे में फुल चार्ज हो जाएंगी। फुल चार्ज होने पर बस 200 किलोमीटर तक चलेंगी।

द रीव टाइम्स
आपकी आवाज़ ही है
हमारी आवाज़

खाई में गिरी बस 15 पर्यटक घायल

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में चंडीगढ़–मनाली हाइवे पर एक 50 फीट गहरी खाई में गिरने से एक बस में सवार 15 पर्यटक घायल हो गए। घटना मंगलवार सुबह 4:30 बजे स्वरघाट में हुई। घायल पर्यटकों में से 4 की हालत गंभीर थी। उन्हें इलाज के लिए चंडीगढ़ PGI ले जाया गया।

अब जल्द होगा केंद्रीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास: जयराम

द रीव टाइम्स ब्यूरो

बिलासपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के भूमि पूजन के बाद अब जल्द ही केंद्रीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया जाएगा। यह बात धर्मशाला में एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही।

उन्होंने कहा कि एम्स पर कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक तौर पर बयानबाजी कर रही है, जो काम कांग्रेस को इतने वर्षों में सत्ता में रहकर करने चाहिए थे, उन्हें आज भाजपा कर रही है।

शिमला: 10 प्रतिशत कोटा को मंजूरी देने वाला चौथा राज्य बना हिमाचल प्रदेश

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हाइलाइट्स

- हिमाचल प्रदेश सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को राज्य में मंजूरी दे दी है
- गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश के अलावा हिमाचल प्रदेश ऐसा करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है
- संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद बीती 12 जनवरी को राष्ट्रपति कोविंद ने बिल को मंजूरी दे दी थी

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में सरकारी नौकरियों और शिक्षा क्षेत्र में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ वह ऐसा करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। इससे पहले शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपने राज्य में इसे मंजूरी दे दी थी। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अलावा गुजरात और झारखंड में भी सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए आरक्षण को राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है।

हिमाचल के डॉ. ओमेश और अजय ठाकुर को पद्मश्री

द रीव टाइम्स ब्यूरो

गृह मंत्रालय ने शुक्रवार शाम को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। हिमाचल के डा. ओमेश कुमार भारती और कबड्डी खिलाड़ी अजय ठाकुर को पदमश्री अवार्ड के लिए चुना गया है। डा. ओमेश ने कुत्तों और बंदरों के काटने के लिए इलाज के लिए एंटी रैबीज प्रोटोकोल तैयार किया है। डा. ओमेश वर्तमान में शिमला के परिमहल में तैनात हैं। मूल रूप से कांगड़ा के ज्वालामुखी के रहने वाले डा. ओमेश की ओर से तैयार किए गए प्रोटोकाल से रैबीज से बचने का इलाज सस्ता हो गया है। पहले जहां रैबीज के इलाज पर 30 से 35 हजार रुपये खर्च आता था, वहीं इनके किए शोध के बाद मात्र 300 रुपये से भी कम में रैबीज का इलाज हो जाता है। इनके किए शोध को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मान्यता देते हुए इसे विश्व स्तर पर लागू करने के निर्देश दिए थे।

अर्की में 49वें पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह पर HRTC डिपो कुनिहार को थाना और आदर्श विद्यालय की घोषणा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सोलन जिले के कुनिहार में 49वें राज्यत्व दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए अर्की में पथ परिवहन निगम के उप–डिपो खोलने तथा पुलिस चौकी कुनिहार को पुलिस थाना में स्तरोन्नत करने की घोषणा की|मुख्यमंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र कुनिहार को अटल आदर्श विद्या केन्द्र बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुनिहार के खेल मैदान के लिए 20 लाख रुपये प्रदान की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों को राज्यत्व दिवस के शुभ अवसर पर बधाई देते हुए कहा कि राज्य ने पिछले 48 वर्षों के अभूतपूर्व प्रगति की है, जो प्रदेश के लोगों के सक्रिय भागीदारी व सहयोग से सम्भव हुआ है|जय राम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार ने 27 दिसम्बर, 2018 को एक वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है और सरकार ने इस दौरान नई योजनाओं व पहलों को आरम्भ कर प्रदेश के सभी क्षेत्रों व वर्गों को लाभान्वित करने के सार्थक प्रयास किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की बागडोर संभालने के तुरन्त बाद, प्रदेश सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए तुरन्त पग उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी पहली मंत्रिमंडल की बैठक में वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान देने के लिए बिना किसी आय सीमा के सामाजिक सुरक्षा पेंशन की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया, जिससे 1.30 लाख वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हुए और अब लगभग 2 लाख वरिष्ठ नागरिक प्रतिमाह 1300 रुपये बढ़ी हुई पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लड़कियों व महिलाओं की सुरक्षा के लिए गुड़िया हेल्पलाइन और शक्ति बटन ऐप आरम्भ की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने धर्मशाला में प्रदेश सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री ने न प्रदेश सरकार के केवल शपथ ग्रहण समारोह की शोभा बढ़ाई बल्कि एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर लोगों को आशीर्वाद भी दिया।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया

भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आठवां मतदाता दिवस 25 जनवरी 2019 को देश भर में मनाया गया। इस महत्त्वपूर्ण दिवस का आयोजन सभी भारतवासियों को अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की याद दिलाता है और साथ ही यह भी बताता है कि हर व्यक्ति के लिए मतदान करना बहुत ज़रूरी है।

प्रसिद्ध हिंदी लेखिका कृष्णा सोबती का निधन

हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका कृष्णा सोबती का 25 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 93 वर्ष की थीं। उनकी रचनाओं में महिला सशक्तिकरण और स्त्री जीवन की जटिलताओं का जिक्र मिलता है। सोबती को राजनीति–सामाजिक मुद्दों पर अपनी मुखर राय के लिए भी जाना जाता है।

वर्ष 2017–18 में बिहार की विकास दर शीर्ष पर: CRISIL रिपोर्ट

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल द्वारा 17 राज्यों की रैंकिंग (ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रॉडक्ट यानी जीएसडीपी) जारी की गई है, इसमें वर्ष 2017–18 के लिए बिहार की विकास दर सबसे बेहतर बताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार वित्त वर्ष 2017–18 में राज्यों के विकास दर के मामले में टॉप पर रहा। क्रिसिल द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दौरान बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रॉडक्ट यानी जीएसडीपी) 11.3प्रतिशत की दर से बढ़ा है।

केंद्र सरकार ने सुभाष चन्द्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की

केंद्र सरकार ने 23 जनवरी 2019 को सुभाष चन्द्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की है। इस पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयंती के अवसर पर की जाएगी। सुभाष चन्द्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के द्वारा उन व्यक्तियों तथा संस्थानों को सम्मानित किया जायेगा जिन्होंने ने आपदा प्रबंधन में देश में बेहतरीन कार्य किया है।

डीडी साइंस और इंडिया साइंस चैनल शुरू

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने 15 जनवरी 2019 को दूरदर्शन (डीडी) और प्रसार भारती के साथ मिलकर नई दिल्ली में विज्ञान संचार के क्षेत्र में दो पहलों 'डीडी साइंस' तथा 'इंडिया साइंस' की शुरुआत की। केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने इन दोनों महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत करते हुए कहा कि यह न केवल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संचार, बल्कि हमारे समाज की वैज्ञानिक सोच विकसित करने के क्षेत्र में भी एक ऐतिहासिक पल है।

भारत 2019–20 में दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा: यूएन रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की वैश्विक आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं (डब्ल्यूईएसपी) 2019 रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2019 और 2020 में दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि वृद्धि को मजबूत निजी उपभोग और अधिक विस्तार वाले वित्तीय रुख तथा पिछले सुधारों के लाभ से सहारा मिल रहा है। इसमें कहा गया है कि मध्यम अवधि की वृद्धि दर के लिए निजी निवेश में सतत सुधार महत्वपूर्ण है।

विश्व का पहला मानवाधिकार को समर्पित टीवी चैनल लंदन में आरंभ

इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ़ ह्यूमन राइट्स द्वारा विश्व में पहली बार मानवाधिकार को समर्पित टीवी चैनल आरंभ किया गया है। यह चैनल लंदन स्थित ऑफिस से आरंभ किया गया है। मानवाधिकार को समर्पित यह टीवी चैनल वेब आधारित होगा लेकिन यह यूरोप, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व समेत 20 देशों के लोगों के लिए मानवाधिकार से सम्बंधित मुद्दों पर कार्यक्रम का प्रसारण करेगा।

भारतीय नौसेना ने सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास शुरु किया

भारतीय नौसेना ने 22 जनवरी 2019 को "26/11" हमले के दस साल बाद अपने सबसे बड़े तटीय रक्षा अभ्यास शुरू किया ह। इस अभ्यास का कोडनेम 'सी विजिल 2019' है। यह दो दिवसीय रक्षा अभ्यास था। यह अभ्यास समुद्र तट से सटे सभी 13 राज्यों की 7,516 किमी लंबी सीमा पर चलाया जा रहा है।

इसरो छात्रों द्वारा तैयार 'कलामसैट' और इमेजिंग सैटेलाईट 'माइक्रोसैट आर' लॉन्च करेगा

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) 24 जनवरी 2019 को विश्व के सबसे छोटे सैटेलाइट 'कलामसैट' को लॉन्च करेगा। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी सी–44 के तहत कलामसैट और माइक्रो सैट–आर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जायेगा। कलामसैट की खासियत यह है कि इसे छात्रों ने विकसित किया है। इसके अलावा, माइक्रोसैट–आर की खासियत है कि यह अन्तरिक्ष से पृथ्वी की तस्वीरें लेने में सक्षम है।

प्रधानमंत्री मोदी ने बीपीसीएल की आईआरईपी परियोजना राष्ट्र को समर्पित की

भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जनवरी 2019 को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की एकीकृत रिफाइनरी विस्तार परियोजना (आईआरईपी) राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही उन्होंने एक पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स की आधारशिला भी रखी। रिफाइनरी के उद्घाटन के अवसर पर राज्यपाल पी. सदाशिवम तथा केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी उपस्थित थे।

एलआईसी ने आईडीबीआई में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सार्वजनिक क्षेत्र के आईडीबीआई बैंक में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस अधिग्रहण के साथ एलआईसी अब आईडीबीआई बैंक में बहुलांश शेयरधारक हो गया है। आईडीबीआई द्वारा 21 जनवरी 2019 को यह जानकारी सार्वजनिक की गई। आईडीबीआई बैंक ने मुंबई शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा कि यह अधिग्रहण आईडीबीआई बैंक और एलआईसी दोनों के लिए बेहतर परिणाम लाएगा। इससे आपसी सहयोग के जरिये दोनों इकाइयों के शेयरधारकों, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिये नये अवसर पैदा किये जा सकेंगे।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया

केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल को 23 जनवरी 2019 को वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। दरअसल, केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली अस्वस्थ हैं और इलाज के लिए विदेश में हैं। इस वजह से उनके मंत्रालयों का प्रभार पीयूष गोयल को दिया गया है।

भारतीय वैज्ञानिक सीएनआर राव प्रथम शेख सौद पुरस्कार हेतु चयनित

भारत रत्न से सम्मानित प्रसिद्ध वैज्ञानिक सीएनआर राव को प्रथम शेख सौद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की संस्था सेंटर फॉर एडवांस मैटेरियल द्वारा उन्हें यह पुरस्कार मैटेरियल रिसर्च के लिए दिया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च (जेएनसीएएसआर) द्वारा जारी जानकारी में बताया गया कि प्रथम शेख सौद पुरस्कार के लिए प्रो सीएनआर राव का चयन पुरस्कार समिति ने सर्वसम्मति से किया है। उन्हें पुरस्कार के रूप में एक प्रशस्ति पत्र, मेडल और एक लाख अमेरिकी डॉलर (करीब 71 लाख रुपये) दिए जाएंगे।

जैव ईंधन से सैन्य विमान उड़ाने की मंजूरी

सेंटर फॉर मिलिट्री एयरविदनेस एंड सिटिफिकेशन (सीईएमआईएलएसी) ने 22 जनवरी 2019 को जैव ईंधन से सैन्य विमान उड़ाने की मंजूरी दे दी हैं। जमीन पर और आसमान में महीनों तक किये गये व्यापक परीक्षणों के बाद देश में उत्पादित जैव ईंधन के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है। सीईएमआईएलएसी द्वारा मंजूरी मिलने के बाद भारतीय वायुसेना (आईएएफ) द्वारा जैव ईंधन का इस्तेमाल सबसे पहले अपने परिवहन बेड़े और हेलिकॉप्टरों में किए जाने की उम्मीद है।

मिश्रित जैव और जेट ईंधन के साथ पहली उड़ान

इस मंजूरी के बाद वायुसेना 26 जनवरी को पहली बार आईएएफ एन–32 विमान को मिश्रित जैव और जेट ईंधन के साथ उड़ाने की प्रतिबद्धता पूरी कर सकेगी।

यह मंजूरी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इससे अंततः लगातार परीक्षण और जैव ईंधन के वाणिज्यिक स्तर के नागरिक विमान में इस्तेमाल को लेकर पूर्ण सत्यापन मिल सकेगा। ये परीक्षण शीर्ष राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सत्यापन एजेंसियों द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया के हिसाब से किए गए हैं।

नौसेना वायु स्टेशन आईएनएस कोहासा की शुरुआत की गई

एडमिरल सुनील लांबा पीवीएसएम, एवीएसएम, एडीसी, चेयरमैन सीओएससी और नौसेना प्रमुख ने 24 जनवरी 2019 को अंडमान–निकोबार स्थित नौसेना वायु स्टेशन आईएनएस शिबपुर की आईएनएस कोहासा के रूप में शुरुआत की। आईएन कोहासा को यह नाम व्हाइट बेलिड सी ईगल के नाम पर दिया गया है जो अंडमान–निकोबार द्वीप समूह का स्थानीय बड़ा शिकारी पक्षी है।

सरकार ने 2015–18 के गांधी शांति पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की

केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2019 को पिछले चार वर्षों के लिए गांधी शांति पुरस्कारों की घोषणा की है। केंद्र सरकार द्वारा 2015 से 2018 तक के गांधी शांति पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की गई। इस पुरस्कार से अंतिम बार वर्ष 2014 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को सम्मानित किया गया था।

गुजराती साहित्यकार सितांशु यशश्चंद्र को सरस्वती सम्मान दिया गया

गुजरात के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं पद्म श्री से सम्मानित सितांशु यशश्चंद्र को 22 जनवरी 2019 को वर्ष 2017 के प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से नवाज़ा गया है। के.के बिरला फाउंडेशन द्वारा जारी जानकारी में बताया गया कि यशश्चंद्र को उनके काव्य संग्रह 'वखार' के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है।

चीन को पछाड़कर भारत दूसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश बन सकता है: रिपोर्ट

भारत कच्चे तेल की मांग के मामले में वर्ष 2019 में चीन को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश बन सकता है। यह अनुमान रिसर्च एंड कंसल्टेंसी ग्रुप वुड मैकेंजी ने लगाया है। रिसर्च एंड कंसल्टेंसी ग्रुप वुड मैकेंजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ऑटो ईंधन और एलपीजी की खपत में वृद्धि के कारण यह मांग बढ़ेगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 'फिलिप कोटलर' पुरस्कार से सम्मानित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 14 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में पहली बार फिलिप कोटलर प्रेसिडेंसियल सम्मान सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि हर वर्ष राष्ट्रीय नेता को दिए जाने वाले इस सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार तीन आधार बिन्दुओं पर केंद्रित है– जिसमें लोग, लाभ और प्लेनेट शामिल है।

वेनेजुएला संकट: विश्व में उभरती नई समस्या

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो द्वारा हाल ही में अमेरिका के साथ सभी राजनीतिक संबंध समाप्त किये जाने की घोषणा की गई। इस घोषणा के बाद वेनेजुएला का राजनीतिक संकट एक बार फिर चर्चा में आ गया है। वेनेज़ुएला में जनता द्वारा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन किये जा रहे हैं।

दुनिया के सबसे भरोसेमंद देशों में से एक है भारत: रिपोर्ट

एडलमैन की ट्रस्ट बैरोमीटर–2019 रिपोर्ट के अनुसार, सरकार, कारोबार, एनजीओ और मीडिया के लिहाज़ से भारत दुनिया के सबसे भरोसेमंद देशों में शामिल है। हालांकि, देश के कारोबारी ब्रांड की विश्वसनीयता इनमें सबसे कम है। विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के वार्षिक सम्मेलन के शुरू होने से पहले 21 जनवरी 2019 को जारी की गई एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर–2019 रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वैश्विक विश्वसनीयता सूचकांक तीन अंक के मामूली सुधार के साथ 52 अंक पर पहुंच गया है।

कैबिनेट ने जीएसटी अपीलीय अधिकरण की राष्ट्रीय पीठ के गठन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 23 जनवरी 2019 को वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राष्ट्रीय पीठ (जीएसटीएटी) के गठन को मंजूरी दे दी है। अपीलीय अधिकरण की राष्ट्रीय पीठ नई दिल्ली में स्थित होगी। जीएसटीएटी की अध्यक्षता इसके अध्यक्ष करेंगे एवं इसमें एक तकनीकी सदस्य (केन्द्र) और एक तकनीकी सदस्य (राज्य) शामिल होंगे। जीएसटीएटी की राष्ट्रीय पीठ के गठन पर एकमुश्त व्यय 92.50 लाख रुपये का होगा, जबकि आवर्ती व्यय सालाना 6.86 करोड़ रुपये होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती के अवसर पर 23 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में लालकिले में सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया. इस संग्रहालय में सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज से जुड़ी चीजों को प्रदर्शित किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सुभाष चंद्र बोस के पोते भी मौजूद थे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने याद–ए–जलियां संग्रहालय (जलियांवाला बाग और प्रथम विश्वयुद्ध पर संग्रहालय) और 1857 (प्रथम स्वतंत्रता संग्राम) पर संग्रहालय और भारतीय कला पर दृश्यकला संग्रहालय का भी उद्घाटन किया।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

अफगानिस्तान में तालिबानी हमले में करीब 65 लोगों की मौत : अधिकारी

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

अफगानिस्तान के एक खुफिया ठिकाने पर हुए तालिबानी हमले में करीब 65 लोगों की मौत हो गई। एक स्थानीय अधिकारी ने मंगलवार को बताया। इससे पहले 12 लोगों के मारे जाने की जानकारी दी गई थी। वरदाक प्रांत के प्रांतीय परिषद के उपप्रमुख मोहम्मद सरदान बख्यारी ने बताया, 'हमने कल मलबे से करीब 65 शव निकाले।' सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए सोमवार को बरदाक प्रांत में यह हमला किया गया था। एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर मृतकों की संख्या 70 के आस–पास बताई।

भारत सूखा से निपटने में नेतृत्व प्रदान कर सकता है: संयुक्त राष्ट्र

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण उपशमन व्यवस्था (यूएनसीसीडी) का कहना है कि भारत के पास मरुस्थलीकरण और सूखा जैसी चुनौतियों को उन्नत भू–उपयोग और प्रबंधन के माध्यम से अवसरों में तब्दील करने तथा इस संबंध में ठोस कार्रवाई की जरुरत महसूस कर रही दुनिया को नेतृत्व प्रदान करने की प्रचुर संभावना है।

यूएनसीसीडी की कार्यकारी सचिव मोनिक बारबुट की यह टिप्पणी तब आयी जब उन्होंने घोषणा की कि भारत मरुस्थलीकरण, भू–क्षरण और सूखे पर अगले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा. यह सम्मेलन नयी दिल्ली के विज्ञान भवन में 7–18 अक्टूबर तक चलेगा । संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण उपशमन व्यवस्था से जुड़े 197 देशों के सहभागियों के समक्ष पहली बार अहम नये वैज्ञानिक आंकड़े मौजूद होंगे । उनके सम्मुख 2000 से भू–क्षरण की प्रवृत्तियों पर पर्यवेक्षण आंकड़े उपलब्ध होंगे जो मरुस्थलीकरण से प्रभावित 169 देशों में से 120 से जुटाये गये हैं।

ट्रेड वार: तीन दशक में सबसे सुस्त रही ड्रैगन की रफ्तार, भारत पर नहीं पड़ेगा कोई फर्क

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो (एनबीएस) के मुताबिक चीन की अर्थव्यवस्था साल 2018 में 6.6 फीसद की रफ्तार से बढ़ी है । 1990 के बाद से यह उसकी सबसे धीमी आर्थिक वृद्धि दर है । दिसंबर में खत्म हुई तिमाही में चीन की आर्थिक वृद्धि दर 6.4 फीसद रही, जो कि इससे पहले की तिमाही में 6.5 फीसद थी । साल 2017 की आर्थिक वृद्धि दर 6.8 फीसद थी । दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को अमेरिका के साथ व्यापार मोर्चे पर जारी तनाव और निर्यात में गिरावट की सर्वाधिक चपत लगी है ।

एशिया में प्रभाव

पिछले एक दशक में चीन इंटीग्रेटड सर्किट, कच्चा पेट्रोलियम, लोहा और तांबा खरीदकर एशिया के अधिकांश देशों के लिए सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है । इसलिए यदि चीन की आर्थिक वृद्धि दर धीमी पड़ती है और वह सामान नहीं खरीदता है तो इससे सभी भागीदार देश प्रभावित होंगे । विश्व बैंक के अनुसार, एशिया प्रशांत क्षेत्र में विकास दर इस साल पिछले साल 6.3 फीसद की तुलना में 6 फीसद ही रह सकती है ।

हिंदू महिला और मुस्लिम पुरुष की शादी अनियमित, अवैध : सुप्रीम कोर्ट

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू महिला और मुस्लिम पुरुष की शादी न तो 'नियमित है और न ही वैध' लेकिन इस शादी से पैदा हुई संतान वैध है और वह अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा पाने का हकदार है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि कानून इस तरह की शादी में महिला भत्ता पाने की हकदार तो है लेकिन उसे अपने पति की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। कोर्ट ने यह आदेश संपत्ति विवाद की सुनवाई के दौरान दिया।

न्यायाधीश एनवी रमन और एमएम शांतगोदर की पीठ ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें कहा गया कि मोहम्मद इलियास और वल्लिमा (शादी के वक्त हिंदू युवती) के बेटा जायज है और अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा पाने का हकदार है। पीठ ने कहा, 'हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऐसी किसी महिला से जो मूर्तिपूजा करती हो या फिर अग्नि को पूजती हो उससे मुस्लिम पुरुष का विवाह न तो वैध है और न ही मान्य है, यह केवल महज एक अनियमित विवाह है। ऐसे विवाह से पैदा हुई संतान अपने पिता की संपत्ति पर दावा करने का हकदार है।'

धूमकेतु की धूल के लिए अमेरिका और जापान आमने–सामने

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

अमेरिका और रूस समेत कई देश जहां चांद और मंगल पर जीवन की तलाश में लगे हैं, वहीं जापान और अमेरिका धूमकेतु से धूल लाकर उसपर आगे जांच करने की तैयारी में लगे हुए हैं। इसके लिए इन दोनों देशों ने अपने–अपने अंतरिक्ष यान छोड़ रखे हैं, जो अगले साल तक यह कारनामा कर सकते हैं।

चावल के तीन दानों के बराबर होगा वजन : जापान ने रायगु नामक धूमकेतु पर हायाबुसा–2 नाम से अंतरिक्ष यान 3 दिसंबर 2014 को छोड़ा। यह जून 2018 में रायगु पर पहुंच गया। वहां से नमूने लेकर अगले साल यानी 2020 में इसके धरती पर पहुंचने की उम्मीद है। आपको जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि इस अंतरिक्ष यान का लक्ष्य केवल तीन मिलीग्राम धूल लाना है, जो चावल के तीन दानों के बराबर वजन की होगी । इस काम के लिए जापान पिछले दो दशक से लगा हुआ ।

ब्राजील: अचानक से ढह गया बांध 7 लोगों की मौत, 150 लापता

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

दक्षिण पूर्वी ब्राजील में लौह अयस्क की एक खदान के परिसर में एक बांध के ढहने से कम से कम सात लोगों की मौत हो गई और करीब 150 लोग लापता हैं। इस बांध का लंबे समय से उपयोग नहीं किया जा रहा था।

वेल के सीईओ फैबियो श्वार्ट्समैन नेरियो डी जेनेरो में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बांध अचानक ध्वस्त हुआ जिससे पूरे परिसर में मिट्टी फैल गई। वहां करीब 300 खदान कर्मचारी काम कर रहे थे। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। बचाव एवं राहत कार्य जारी है।

चीन को पछाड़ भारत बनेगा दूसरा बड़ा तेल खरीदार

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

भारत तेल की मांग के मामले में 2019 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा। रिसर्च एंड कंसल्टेंसी समूह वुड मैकेंजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ऑटो ईंधन और एलपीजी की खपत में वृद्धि के कारण यह मांग बढ़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक, 2018 में भारत में तेल की मांग में जोरदार वृद्धि हुई है। जीएसटी और नोटबंदी लागू होने के बाद इसने वैश्विक मांग में 14 फीसदी या 2.45 लाख बैरल प्रतिदिन (बीपीडी) का योगदान दिया है।

वुड मैकेंजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हम 2019 में समान स्तर पर तेल की मांग बढ़ने का अनुमान लगा रहे हैं। इसका परिणाम यह होगा कि भारत 2019 में चीन को पछाड़कर तेल की मांग वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा। हालांकि, अमेरिका भारत से तब भी आगे रहेगा। वहीं, अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (ईआईए) के अनुसार, भारत वर्तमान में अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। 2017–18 के दौरान भारत में तेल की खपत 20.62 करोड़ टन (40 लाख बीपीडी से अधिक) थी। अप्रैल–दिसंबर के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की खपत 15.74 करोड़ टन रही है, जो पिछले साल की तुलना में 2.5 फीसदी अधिक है।

डीजल की खपत सबसे अधिक

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में डीजल की खपत सबसे अधिक है। 2019 में यह 2018 के 93,000 बीपीडी के मुकाबले 6.4 फीसदी बढ़कर 1.12 लाख बीपीडी हो जाएगा। पिछले अगस्त में ओपेक ने 2040 तक भारत में तेल की मांग बढ़कर 58 लाख बीपीडी होने का अनुमान लगाया था।

एक बार फिर चर्चा में है बांग्लादेश का 28 वर्षीय ट्री मैन, पहले भी 25 बार हो चुकी है सर्जरी

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

बांग्लादेश का एक शख्स जिसके हाथ–पैर में पेड़ जैसे उगते हैं। सुनने में भले ये अटपटा लगे, लेकिन सच है। पिछले करीब दो साल में इस शख्स की 25 बार सर्जरी हो चुकी है। बावजूद उसे इस बीमारी से छुटकारा नहीं मिला है। अब उसे फिर से सर्जरी की आवश्यकता है।

अबुल को एपिडर्मोडिस्प्लैजिया वेरुसिफोर्मिस (epidermodysplasia verruciformis) नाम की बीमारी है, जो दुनिया की सबसे अजीब बीमारी है। ये एक तरह का रेयर जेनेटिक स्किन डिसऑर्डर है। उसकी बीमारी ने दुनिया भर के डॉक्टरों को हैरत में डाल रखा है। इन दिनों अबुल की हालत काफी खराब है। उसके हाथ–पैर में उगने वाली पेड़ जैसी आकृति इतनी बड़ी हो चुकी है कि उनके लिए दैनिक कार्य करना भी असंभव हो चुकी है।

मिस्र : राष्ट्रपति का विचित्र फरमान, काहिरा की इमारतों को मटमैले–नीले रंग से नहीं रंगने पर होगी सजा

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

ममी और पिरामिड... इन शब्दों को सुनते ही मिस्र का ध्यान आ जाता है । प्राचीन इतिहास और सभ्यता को संजोए रखे इस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल–सिसी ने एक विचित्र फरमान जारी किया है। अल–सिसी का आदेश है कि नील नदी के किनारे बसे राजधानी काहिरा की सभी इमारतें मटमैले रंग की दिखनी चाहिए। और नदी के किनारे बसे इलाकों में इलारतें नीले रंग की होनी चाहिए। यही नहीं, इमारतों के रंग–रोगन काम भी मार्च महीने तक हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार कर्मचारियों और मकान मालिकों को सजा दी जाएगी।

इमारतों को रंगना राष्ट्रीय परियोजना का हिस्सा

राष्ट्रपति अल–सिसी का मानना है कि काहिरा में एक रंग की इमारतें होने से शहर में एकरूपता आएगी । इससे शहर की बनावट एक जैसी लगेगी और एक अलग पहचान बनेगी । अभी शहर की इमारतें बहुत ही बेतरतीब दिखाई देती हैं ।

ब्रिटेन में ये अफ्रीकी चलन पकड़ रहा है जोर, सुनकर रह जाएंगे दंग

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

यौन प्रताड़ना और दुष्कर्म जैसे अपराधों से लड़कियों को बचाने के लिए ब्रिटेन में भी एक अफ्रीकी चलन जोर पकड़ रहा है। अफ्रीका में लड़की का शरीर विकृत करने के लिए उसकी छाती को गर्म पत्थर से दागा जाता है। इस आशय की जानकारी शनिवार को मीडिया ने दी है। द गार्डियन ने खबर में कहा है कि लंदन, यार्कशायर, एसेक्स और वेस्ट मिडलैंड्स में काम करने वाले समुदाय ने ऐसे मामलों के बारे में बताया। कई अफ्रीकी देशों के प्रवासी समुदाय के लोग किशोर वय से पूर्व की लड़कियों को इस तरह के दर्दनाक, निंदनीय और बेकार चलन का शिकार बनाते हैं।

संयुक्त राष्ट्र ने इस चलन को दुनिया के पांच सूचित नहीं होने वाले अपराधों में माना है। ये अपराध लिंग आधारित हिंसा से संबंधित हैं। आम तौर पर मां इसे लड़कियों को पुरुषों के अवांछित आकर्षण से बचाने वाला पारंपरिक उपाय मानती हैं। चिकित्सकीय विशेषज्ञ और पीड़ित इसे बाल उत्पीड़न मानते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इससे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आघात, संक्रमण, स्तनपान में अक्षमता, विकृति और ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है।

आपका Facebook डेटा सेफ है या नहीं? CEO मार्क जुकरबर्ग ने दिया ये जवाब

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

फेसबुक के संस्थापक और सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का बचाव करते हुए कहा कि कंपनी अपने यूजर का डाटा किसी को नहीं बेच रहा है । जुकरबर्ग ने वाल स्ट्रीट जर्नल में एक विचारपरक आलेख में लिखा, 'हम लोगों का डाटा नहीं बेचते हैं, फिर भी अक्सर कहा जाता है कि हम ऐसा करते हैं।'

उन्होंने कहा, ''अल्पावधि के दौरान क्लिकबेट व अन्य जंक में ऐसा हो सकता है, मगर हमारे लिए जानबूझकर ऐसा करने की बात झूठ है, क्योंकि यह वैसी बात नहीं है जैसाकि लोग चाहते हैं।

खालिस्तान समर्थक नहीं रोक सके गणतंत्र दिवस परेड, US में लगे 'भारत माता की जय' के नारे

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

एक तरफ जहां गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे भारत में जश्न मनाया जा रहा है, वहीं अमेरिका के वॉशिंगटन में कुछ लोग गणतंत्र दिवस परेड का विरोध कर रहे थे । स्थानीय भारतीयों द्वारा हाथ में तिरंगे झंडे और बैनर लेकर निकाली जा रही गणतंत्र दिवस परेड का विरोध कुछ खालिस्तान समर्थक कर रहे थे। हालांकि उनका विरोध बेकार गया, क्योंकि भारत मां के सच्चे भक्त पीछे नहीं हटे और 'भारत माता की जय' के नारे लगाते रहे। वहीं सिख फॉर जस्टिस ग्रुप ने अपनी वेबसाइट पर झूठा दावा किया कि उसने अमेरिका में भारतीय दूतावास के सामने भारतीय झंडा जलाया है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि यह दावा पूरी तरह झूठा है।

कैंसर से बचना है तो शुरु कर दीजिए ब्रोकोली खाना

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

दुनिया भर के वैज्ञानिक और पोषणविज्ञानी खाने–पीने की ऐसी चीजों की खोज कर रहे हैं जो लोगों को कैंसर से दूर रख सकें। इसी संबंध में प्रसिद्ध लैसेंट पत्रिका में प्रकाशित शोध के निष्कर्ष उत्साहवर्धक पाए गए। शोध का नेतृत्व कर रहीं विशेषज्ञ उलरिके गोंडर ने कहा कि ब्रोकोली के रसायन कैंसर रोकने में मददगार होते हैं। इसमें न सिर्फ सल्फर कंपाउंड होते हैं, बल्कि इसे चबाने, काटने या पकाने पर ग्लूकोसिनोलेट्स नामक तत्व रिलीज होता है, जो कैंसर रोधी होता है। इसमें कई कैंसर रोधी गुण होते हैं।

कर्च जलसंधि में भारतीय नागरिकों को ले जा रहे दो पोतों में लगी आग, 14 की मौत

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

क्रीमिया को रूस से अलग करने वाले कर्च जलसंधि में दो पोतों में आग लग जाने से कम से कम 14 लोग मारे गये । इन दोनों पोतों पर चालक दल के भारतीय, तुर्की और लीबियाई सदस्य सवार थे । मंगलवार को मीडिया में आयी खबरों से यह जानकारी मिली ।

रूस की जलसीमा के पास दोनों पोतों में आग लगी । इन पोतों पर तंजानियाई झंडा लहरा रहा था । इनमें से एक पोत द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) ले जा रहा था, जबकि दूसरा एक टैंकर ले जा रहा था । आग उस वक्त लगी जब इनमें से एक पोत दूसरे पोत को ईंधन दे रहा था । इस घटना के शिकार हुए कैंडी नाम के पोत के चालक दल में 17 सदस्य सवार थे जिसमें नौ तुर्की और आठ भारतीय नागरिक थे । दूसरे पोत माइस्त्रो के चालक दल में 15 सदस्य थे जिनमें तुर्की के सात, भारत के सात और लीबिया का एक नागरिक था । रूस की समाचार एजेंसी 'ताश' ने समुद्री अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी ।

ट्रंप चाहते हैं योग्यता के आधार पर अमेरिका आए लोग, दीवार बनाने पर दिया जोर

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को इस बात पर जोर दिया कि सीमा पर दीवार बनाकर ही अवैध प्रवासियों और मादक पदार्थों को देश में आने से रोका जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि लोग योग्यता के आधार पर अमेरिका आए ।

ट्रंप ने आव्रजन प्रस्ताव पर व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक में पत्रकारों से कहा, 'हम चाहते हैं कि लोग योग्यता के आधार पर आए। हम चाहते हैं कि ऐसे लोग आए जो हमारे देश में चल रही इन सभी कंपनियों को आगे बढ़ाने में सफलतापूर्वक मदद कर सकें।'

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

बीते 15 दिनों की समसामयिक घटनाओं पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी

- तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से जिस बीजेपी सांसद को ज्यूरी कमेटी स्पेशल अवॉर्ड 'सांसद रत्न पुरस्कार' से सम्मानित किया है– अनुराग ठाकुर
- गृह मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, 15 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक उम्र के भारतीय पर्यटक अब नेपाल और जिस देश के यात्रा के दौरान आधार कार्ड का इस्तेमाल वैध यात्रा दस्तावेज़ के रूप में कर सकेंगे– भूटान
- गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा पिछले साल घोषित किए गए सबसे उम्रदराज़ पुरुष मसाज़ो नोनाका का जितने वर्ष की उम्र में जापान के अशोरो में निधन हो गया है–113 वर्ष
- भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले से उत्तर प्रदेश को 1.2 लाख करोड़ रुपये की कमाई और जितने लाख लोगों को रोज़गार मिलने की उम्मीद है–6 लाख
- केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिलिट्री पुलिस में जितने फीसदी महिलाओं को भर्ती करने की घोषणा की हैं–20 फीसदी
- वह शहर जिसे यूनेस्को द्वारा वर्ष 2020 के लिए विश्व की पहली आर्किटेक्चर राजधानी घोषित किया है – रियो डी जेनेरियो
- लिंगायत समुदाय से संबंध रखने वाले 111 वर्षीय शिवकुमार स्वामीजी का हाल ही में निधन हो गया। वे जिस मठ के प्रमुख थे उसका नाम है–सिद्ध गंगा मठ
- इसरो द्वारा इस सरकारी विभाग की सहायता के लिए विशेष सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की गई है–रक्षा विभाग
- नासा का वह मिशन जिसके द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर नासा ने शनि ग्रह के छल्लों की आयु 1 से 10 करोड़ वर्ष के बीच बताई है–कैसिनी मिशन
- रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामण ने इस स्थान पर देश के दूसरे रक्षा औद्योगिक गलियारे को लॉन्च किया है–तमिलनाडु
- सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने जितने वर्ष से अधिक उम्र के छात्रों को राहत देते हुए अंतरिम तौर पर आईआईटी जेईई मेन व एडवांस परीक्षा में बैठने की इजाज़त दे दी है–25 वर्ष से अधिक
- हाल ही में जर्मनी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए जिस देश की एयरलाइन कंपनी 'महान एयर' पर बैन लगा दिया है– ईरान
- फ्रांस की डेटा निगरानी संस्था ने नए डेटा प्राइवेसी कानून 'जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन' (जीडीपीआर) का पहली बार इस्तेमाल कर गूगल पर जितने करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है–404 करोड़ रुपये
- एडलमैन की ट्रस्ट बैरोमीटर–2019 रिपोर्ट के अनुसार, सरकार, कारोबार, एनजीओ और मीडिया के लिहाज़ से जो देश विश्व के सबसे भरोसेमंद देशों में शामिल है– भारत
- झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 22 जनवरी 2019 को विधानसभा में पिछली बार के 80200 करोड़ रुपये के मुकाबले जितने करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया है–85,429 करोड़ रुपये
- वह खिलाड़ी जिसने पहली बार तीनों आईसीसी अवॉर्ड्स (क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर) एक साथ अपने नाम किए हैं–विराट कोहली
- वह लुप्तप्राय प्रजाति की डॉल्फिन जिसे हाल ही में बांद्रा–वर्ली समुद्री लिंक के समीप देखा गया है – हंपबैक डॉल्फिन
- वह संस्था जिसके द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 1 प्रतिशत लोगों के पास 50 प्रतिशत आबादी के बराबर संपत्ति है–ऑक्सफैम
- वह कम्पनी जिसने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के आईडीबीआई बैंक में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है–एलआईसी
- वह देश जिसके राष्ट्र बैंक ने देश में 100 रुपये से अधिक मूल्य के भारतीय नोटों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है– नेपाल
- फ्रांस और जिस देश ने एक नई मैत्री संधि 'आहेन' पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जिसका उद्देश्य एक–दूसरे का बचाव, दोनों देशों में मित्रता बढ़ाना और दोनों देशों के नागरिकों के जीवनस्तर में सुधार करना है– जर्मनी
- रिसर्च व कंसल्टेंसी फर्म वुड मैकेंज़ी की रिपोर्ट के मुताबिक, कच्चे तेल की मांग के मामले में जो देश वर्ष 2019 में चीन को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश बन सकता है– भारत
- जिस भारतीय विकेटकीपर–बल्लेबाज़ को आईसीसी के पुरुष इमर्जिंग प्लेयर ऑफ इयर 2018 चुना गया है– ऋषभ पंत
- आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के अनुसार, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े तबके को दिए गए 10 प्रतिशत के आरक्षण में से जितने प्रतिशत राज्य के कापू जाति के लोगों को दिया जाएगा
- –5 प्रतिशत
- वह राष्ट्रीय स्मारक जिसमें प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस से जुड़े संग्रहालय का उद्घाटन किया गया
- – लाल किला
- वह राज्य जो 11.3 प्रतिशत की दर के साथ वित्त वर्ष 2017–18 में राज्यों के विकास दर के मामले में टॉप पर रहा –बिहार
- यूएनसीसीडी (मरुस्थलीकरण से लड़ने के लिए सयुक्त राष्ट्र अभिसमय) कांफ्रेंस ऑफ़ पार्टीज के 14वें सत्र का आयोजन इस देश में किया जायेगा–भारत
- सुप्रीम कोर्ट के अनुसार न्यायिक अधिकारी पद के लिए सुनाई और देखने में अयोग्यता की वैध सीमा का प्रतिशत है– 50 प्रतिशत
- भारत रत्न से सम्मानित वह वैज्ञानिक जिन्हें हाल ही में प्रथम शेख सौद अंतराष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है–सीएनआर राव
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के सद्भावना दूत का नाम जिन्हें हाल ही में वर्ष 2018 का गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई–योहेई ससाकावा
- वर्ष 2015 के लिए इन्हें गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया
- –विवेकानंद केंद्र, कन्याकुमारी
- वह शहर जहां मानवाधिकार को समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल आरंभ हुआ–लंदन
- वह देश जिसके सत्यरूप सिद्धांत 7 पर्वत शिखरों और 7 ज्वालामुखी पहाड़ों को फतह करने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गए हैं– भारत
- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना और जिस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दिनेश महेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया है

– कर्नाटक हाईकोर्ट

- केन्द्रीय नागरिक विमानन मंत्री द्वारा इस स्थान पर आयोजित वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन 2019 में विज़न 2040 दस्तावेज जारी किया गया–मुंबई
- वह राज्य सरकार जिसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राज्य में कोयले के परिवहन पर 19 फरवरी को अगली सुनवाई तक तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है– मेघालय सरकार
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय निर्यात–आयात बैंक (एक्जिम बैंक) में 6,000 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी डालने और उसकी प्राधिकृत पूंजी को दोगुना कर जितने करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी–20,000 करोड़ रुपये
- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इतने केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु 3,639 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं–13
- दिल्ली के जूडो खिलाड़ियों ने पुणे में आयोजित खेलो इंडिया युवा खेल 2019 में 12 स्वर्ण, 3 रजत और जितने कांस्य पदकों पर कब्जा करके बाकी टीमों को पछाड़ दिया है–6
- वह आयोग जिसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के खिलाफ भेदभावपूर्ण आचरण की शिकायत को खारिज कर दिया है
- – भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
- ब्रिटेन की हायर एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स एजेंसी (एचईएसए) के मुताबिक, ब्रिटेन में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट के बाद 2017–18 में पहली बार जिस देश के छात्रों की संख्या बढ़कर 19,750 हुई
- – भारत
- जिस राज्य सरकार ने 50,000 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी कर्ज माफी योजना 'जय किसान ऋण मुक्ति योजना' का औपचारिक शुभारंभ किया
- – मध्य प्रदेश सरकार
- जिस वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का महानिदेशक (अन्वेषण) नियुक्त किया गया हैं
- – प्रभात सिंह
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय आयात निर्यात बैंक में जितने हज़ार करोड़ रुपये के पुनः पूंजीकरण को मंजूरी दे दी है–6 हज़ार करोड़ रुपये
- प्रवासी भारतीय दिवस इस बार जिस शहर में 21 से 23 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा– वाराणसी
- जिस पहलवान ने प्रतिष्ठित लॉरियस स्पोर्ट्स अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं

– विनेश फोगाट

- वह बल्लेबाज़ जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 40 वर्ष की उम्र में एक से अधिक दोहरा शतक जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं– वसीम जाफर
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने विशेष निदेशक राकेश अस्थाना समेत जितने सीबीआई अधिकारियों का कार्यकाल तत्काल प्रभाव से घटा दिया है–04
- जिस लिमिटेड कंपनी ने एक तिमाही में 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक शुद्ध मुनाफा कमाने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है

– रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड

- वह राज्य जिसके पूर्व मुख्यमंत्री गेगोंग अपांग ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया– अरुणाचल प्रदेश
- अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने 15 जनवरी 2019 को जिसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त कर दिया– मनु साहनी
- मुंबई के खार जिमखाना क्लब ने ऑल–राउंडर हार्दिक पांड्या की मानद सदस्यता जितने साल के लिए निलंबित कर दी है– तीन साल
- जिस राज्य के डी. गुकेश 15 जनवरी 2019 को विश्व के दूसरे और भारत के सबसे युवा ग्रैंडमास्टर बन गए–तमिलनाडु
- टाइम्स हायर एजुकेशन की प्रतिष्ठित 'इमर्जिंग इकोनॉमीज यूनिवर्सिटी रैंकिंग' (वर्ष 2019) में भारत के जितने संस्थानों को जगह मिली है–49
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016–18 में रेल दुर्घटनाओं में मारे गये हाथियों की संख्या है– 49
- भारत और वह देश जिसके बीच प्ढम्म 2018–19 नामक युद्ध अभ्यास शुरू हो गया है–म्यांमार
- वह देश जिसने हाल ही में चांद पर कपास का बीज अंकुरित करने में सफलता हासिल की है–चीन
- वह राज्य जहां प्रधानमंत्री मोदी ने झारसुगुड़ा में मल्टी–मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) राष्ट्र को समर्पित की है–उड़ीसा
- जीएसटी परिषद की 32वीं बैठक के निर्णय के अनुसार रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इतने सदस्यों वाले जीओएम का गठन किया गया है–सात
- वह देश जहां पहली भारत–मध्य एशिया वार्ता का आयोजन किया गया–उज्बेकिस्तान
- वह केंद्र शासित प्रदेश जिसने हाल ही में 1 मार्च 2019 से प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाये जाने की घोषणा की है–पुडुचेरी
- कुंभ मेले के दौरान मौसम का पूर्वानुमान व्यक्त करने के लिए प्रयागराज में स्थापित किये गये स्वचालित मौसम केन्द्रों की संख्या–चार
- 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला दिवस है–सेना दिवस
- एक्सेंचर के सीईओ व चेयरमैन का नाम जिन्होंने हाल ही में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफ़ा दे दिया–पियरे नान्तमी
- वह नोबल पुरस्कार विजेता जिसके द्वारा हाल ही में श्वेत और अश्वेत लोगों की बौद्धिक क्षमता अलग–अलग होने का दावा किये जाने पर उनसे उनकी पुरानी प्रयोगशाला ने 3 मानद सम्मान छीन लिए–जेम्स वॉटसन
- चुनाव आयोग द्वारा शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) को दिया गया चुनाव चिन्ह है – चाबी
- इन्होंने हाल ही में ताईवान की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है – सु त्सेंग–चांग
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस राज्य में बलांगिर–बिचुपाली रेल लाइन का उद्घाटन किया तथा सोनपुर केंद्रीय विद्यालय की आधारशिला रखी–ओडिशा
- वह फिल्म जिसने सांता मोनिका स्थित बार्कर हैंगर में हुये 24वें क्रिटिक्स च्वॉइस अवॉर्ड में चार सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हासिल किये–रोमा
- जिस राज्य सरकार ने 12 जनवरी 2019 को 'एक परिवार, एक नौकरी' योजना का शुभारंभ किया– सिक्किम
- पाकिस्तान की 'यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद' ने युवाओं में इस्लामिक रिवाज़ों और पूर्वोत्तर की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु 14 फरवरी (वैलेंटाइन डे) को जिस डे के रूप में मनाने की घोषणा की है– सिस्टर्स डे
- वह देश जिसने कहा की ईरान से तेल खरीदने के लिए भारत को और रियायत नहीं दी जाएगी– अमेरिका
- वह भारतीय बल्लेबाज़ जिसने पूर्व दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एबी डिविलियर्स (204 छक्के) को पछाड़कर वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने के मामले में पांचवें नंबर पर पहुंच गए हैं– रोहित शर्मा
- भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 जनवरी 2019 को जिस देश के सेना प्रमुख जनरल पूर्ण चंद्र थापा को 'भारतीय सेना के जनरल' की मानद पदवी से सम्मानित किये– नेपाल
- वह पहला राज्य जिसने भारत में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की–गुजरात
- मेसेडोनिया द्वारा हाल ही में देश का नाम बदलकर यह रखा गया है – उत्तरी मेसेडोनिया गणराज्य
- कुंभ मेले के दौरान मौसम की जानकारी के लिए इस नाम से विशेष मोबाइल एप्प सेवा जारी की गई है–कुंभ मेला मौसम सेवा
- इन्हें हाल ही में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है – डॉ. सी पी जोशी
- जीएसटी कम्पोजीशन योजना के तहत कारोबारियों को अप्रैल 2019 से इतनी राशि तक की छूट देने की घोषणा की गई है–डेढ़ करोड़ रुपये

हिमाचल

1 डाक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी और एवं वानिकी विश्वविद्यालय के शोध के मुताबिक कौन सी जड़ीबूटी खून संबंधि रोगों खासकर कैंसर को ठीक करने में सहायक है–वायोलापिलोसा बनक्शा

2. केंद्र सरकार की योजना अपनी धरोहर अपनी पहचान के तहत हिमाचल में जितनी धरोहरों को विकसित किया जाएगा–20

3.वर्तमान में कहां से ट्राउट आयात की जाती है और अब किन दो देशों से आयात करने की योजना है– जम्मू–कश्मीर और अब डेनमार्क और नार्वे से भी आयात करने की योजना है।

4. राज्य स्तरीय लोहड़ी पर्व का आयोजन कहां पर किया जाता है– देश के प्रथम गांव परागपुर , कांगड़ा में

5. हिमाचल में एकमात्र ब्रॉडगेज रेलवे लाइन कौन सी है– ऊना नंगल

6. हाल ही में केंद्रीय राज्य रेल मंत्री मनोज सिन्हा ने जहां 16 किलोमीटर रेल खंड का लोकार्पण किया– अंब– अंदौरा व दौलतपुर चौक के मध्य 16 किलोमीटर

7. नंगल डैम–ऊना– तलवाड़ा रेललाइन को मुकेरियां से कब तक लिंक करने की योजना है– देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर वर्ष 2022 तक

8. हिमाचल में मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है–2020 तक

9. स्पर्श अभियान किससे संबंधित है और यह कब शुरु किया गया– कुष्ठ जागरूकता अभियान से, यह 30 जनवरी 2019 में महात्मा गांधी के शहीदी दिवस पर शुरु किया गया है और 2 अक्तूबर 2019 को राष्ट्रपिता की 150वीं जयंति पर इसका समापत किया जाएगा।

10. सरकारी संस्थानों में कितनी निशुल्क दवाईयां उपलब्ध कराई जा रही है–330

11. हाल ही में केंद्र ने किस राज्य के आलू के बीज पर प्रतिबंध लगा दिया है– हिमाचल

12. हिमाचली आलू के बीज को किस कारण प्रतिबंधित किया गया– बीज में सूत्र कृमि निमेटोड मिलने पर

13. देश की दूसरी सबसे पुरानी नगर परिषद कौन सी है और हाल ही कौन अध्यक्ष बना– नगर परिषद नाहन–12 अप्रैल को अपनी 150वीं वर्षगांठ मनाएगा। शहर का इतिहास 400 साल पुराना है जबकि डेढ़ सदी पूर्व यानी 1868 में यहां शहरी निकाय की स्थापना हो गई थी। वर्तमान में नगर परिषद का दर्जा प्राप्त निकाय के लिए 12 अप्रैल को ऐतिहासिक दिन होगा, जिसे धूमधाम से मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कार्यक्रम का नाम जश्न–ए–नाहन दिया गया है जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे।

14. वर्ष 2019–20 के लिए हिमाचल राज्य योजना बोर्ड की ओर से कितने की वार्षिक योजना को मंजूरी दी गई है– 7100 करोड़, गत वर्ष यह 6300 करोड़ था

15. इस वर्ष की वार्षिक योजना में पिछले साल के मुका बले कितने फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई है– 12.70 प्रतिशत

16. योजना के तहत किस क्षेत्र पर सबसे अधिक व्यय किया जाना प्रस्तावित है– सामाजिक सेवा क्षेत्र पर 3048.15 करोड़ रुपये, यह कुल व्यय का 42.93 प्रतिशत है

17. वर्तमान मुल्य दरों पर हिमाचल की प्रतिव्यक्ति आय कितनी है– 1 लाख 58 हजार, यह 2016–17 में 1 लाख 46 हजार 294 रुपये थी जिसमें 2017–18 में 8°3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

18. हिमाचल में पहला कोबरा– कमांड बटालियन फॉर रिसाल्यूट ट्रेनिंग सेंटर कहां खोला जाएगा– हरिपुर

19. 15 दिसंबर 2018 तक हिमाचल में हिमाचल गृहणी सुविधा योजना के तहत कितने प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया है–97 प्रतिशत

20. बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना के पैतृक गांव का क्या नाम है– धबोई, यहां उन्होंने कुलदेवी अंबिका मंदिर निर्माण भी करवाया है।

21. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्यन्यायाधीश कौन है– सूर्यकांत

22. स्वच्छता बनाए रखने और संक्रमण नियंत्रण में किस अस्पताल ने पहला और दूसरा स्थान प्राप्त किया– डलहौजी ने पहला और सरकाघाट दूसरे स्थान पर रही

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

मुख्यमंत्री मधु विकास योजना बढ़ाएगी हिमाचल में मिठास

प्रदेश में शहद के व्यवसायिक उत्पादन में क्रांति लाने के लिए उद्यान विभाग ने मुख्यमंत्री मधु विकास योजना शुरु की...

प्रदेश में शहद के व्यवसायिक उत्पादन में क्रांति लाने के लिए उद्यान विभाग ने मुख्यमंत्री मधु विकास योजना शुरू की है। मधुमक्खी से जहां प्रदेश में मीठा कारोबार बढ़ेगा, वहीं पॉलीनेशन से यहां फल, फूल, दलहन, तिलहन की उत्पादकता व गुणवत्ता भी बढ़ेगी। प्रदेश में उद्यान विभाग के माध्यम से मधु विकास योजना चलाई जा रही है। द रीव टाइम्स के इस अंक हम आपको इस योजना की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं।

शहद प्राचीनकाल से ही मनुष्य की जीविकापार्जन का साधन रहा है। मनुष्य के भोजन का एक–तिहाई भाग पर–परागण फसलों से मिलता है और परागण यानि पॉलीनेशन में मधुमक्खियों की अहम भूमिका होती है। इसके महत्व को समझते हुए प्रदेश में 10 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री मधु विकास योजना शुरू की गई है। इस योजना से प्रदेश में शहद के व्यवसायिक उत्पादन को पंख लगेंगे और यहां बेरोजगार युवा भी बी–कीपिंग को व्यवसाय के रूप में अपनाकर अपनी आर्थिकी को मजबूत कर सकते हैं।

ये मिलती है सुविधाएं मिलेगी मधु विकास

मुख्यमंत्री मधु विकास योजना को विभाग ने शुरू कर दिया है। योजना शुरू करने के लिए बेरोजगार युवा, किसानों व बागबानों के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है। बी कीपिंग यूनिट (कालोनी) के लिए 80 फीसदी तक सब्सिडी विभाग की ओर से दी जाती है। एक व्यक्ति को अधिकतम 50 यूनिट तक पर सब्सिडी विभाग की ओर से दी जाती है। किसान इसके लिए बक्से अपने स्तर पर भी ले सकते हैं। इसके अलावा किसान व बागवान मौन पालन कार्यालय शिमला से भी बक्से के लिए डिमांड दे सकते हैं। मौन पालन में प्रयोग होने वाले यंत्रों में की खरीद के लिए प्रतिव्यक्ति 16000 रुपए दिए जाते हैं। साथ ही घरों में देसी मधुमक्खी पालने वाले को भी प्रति छत्ता 1000 रुपए दिए जाते है और यह अधिकतम 5000 हो सकते हैं।

हिमाचल में मौन पालन

आकंड़ों के मुताबिक प्रदेश में प्रतिवर्ष करीब 1500 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में करीब 1600 लोग व्यवसायिक मधुमक्खी पालन से जुड़े हैं। हिमाचल में 4 से 5 करोड़ रुपए का शहद का कारोबार होता है। हिमाचल में मधुमक्खी पालन की आपार संभावनाएं है। मधुमक्खी पॉलीनेटर का काम करती है, जो हमारे फलों, जड़ी–बूटियों और वनों की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मधुमक्खियां है।

मधुमक्खी पालन का उद्देश्य:

- प्रदेश में फल फसलों की उत्पादकता बढ़ाने तथा परागण हेतु बागवानों को मौन वंश प्रदान करना।
- मौन प्रजातियों को पालतू बनाना जिससे की प्रकृति में पारिस्थितिकी संतुलन बना रहें।
- परागण, निष्कर्षण एवं प्रदर्शन और शहद की उपयोगिता तथा अन्य मौन पालन उत्पादों के लिए छोटे–छोटे मौन पालन गृहों को बनाना।
- वैज्ञानिक मौन पालन हेतु किसानो की सहभागिता को प्रोत्साहित करना।
- राज्य में किसानो को तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के लिए छोटी अवधि वाले मौन पालन प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना।
- बेरोजगार युवाओं को उनकी आजीविका के साधन के रूप में मौन पालन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना ।
- **हिमाचल में 85 साल पहले शुरु हुआ था मौन पालन**
- हिमाचल प्रदेश में आधुनिक मौन पालन, वर्ष 1934 में कुल्लू घाटी में और वर्ष 1936 में काँगड़ा घाटी में आरम्भ किया गया था। राज्य में वर्ष 1961 में भारतीय एपिस कैराना इंडिका की प्रजाति को पाला जाता था, जबकि इटालियन एपिस मैलीफिरा प्रजाति की मधुमखियों को राज्य के मौन अनुसन्धान केन्द्र काँगड़ा (नगरोटा) में पाला गया था। फल उद्योग में मौन पालन की महत्वता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1971 में कृषि विभाग के विभाजन के समय बागवानी विभाग को कृषि विभाग से स्थानांतरित किया गया था। अप्रैल 1971 से पूर्व पूरे प्रदेश में आधुनिक मौन गृहों में केवल 1250 मौन छतों को रखने का प्रावधान था। वर्ष 1971, में इस योजना का बागवानी विभाग में स्थानांतरण होने के बाद मौन पालन के क्षेत्र में मौन पालकों की वृद्धि हुई है।
- फल पौध के परागण हेतु एवं मूल्यवान मधु के उत्पादों की महत्वता को ध्यान में रखते हुए उद्यान विभाग राज्य में मौन पालन योजना को प्राथमिकता के आधार पर रख कर प्रगति की ओर अग्रसर किया है। इस समय उद्यान विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न उपयुक्त स्थानों पर 32 मौन पालन प्रदर्शन गृह स्थापित किये गये है। पूरे प्रदेश को दो क्षेत्रों में बांटा गया है अर्थात् उतरी एवं दक्षिणी क्षेत्र। दक्षिणी क्षेत्र में 17 मौन पालन प्रदर्शन गृह जबकि उत्तरी क्षेत्र में 15 मौन पालन प्रदर्शन गृह है। 1983–84 से पूर्व एपिस कैराना इंडिका प्रजाति की मधुमखियाँ दक्षिणी क्षेत्र के सभी मौन पालन गृहों में पाली जाती थी, और एपिस मैलीफिरा प्रजाति की मधुमखियाँ को केवल उत्तरी क्षेत्रों में ही पाला जाता था। वर्ष 1983–84 के बाद एपिस कैराना प्रजाति की मधुमखियाँ स्कैबरौड़ के

कारण लुप्त होने लग गई थी। विभाग द्वारा 90 प्रतिशत से अधिक मौन गृह नियंत्रित किया जाता है तथा इसके अतिरिक्त अन्य मौन पालन गृह निजी क्षेत्र से सम्बंध रखते है, एपिस मैलीफिरा प्रजाति की मधुमखियों को मौन गृहों में न रख कर दीवारों में रख कर पाला जाता है। सर्दियों के मौसम के दौरान मौन पालकों के द्वारा मौन छतों को अन्य गर्म राज्यों में रखा जाता है जिस कारणवश राज्य के मौन गृहों में शहद की कमी हो जाती है।

- वर्ष 1981–82 में हिमाचल प्रदेश में एपिस मैलीफिरा प्रजाति के आंकडों के आधार पर 4200 मौन पालन गृह उपलब्ध थे। जबकि इस समय प्रदेश में करीब 80,000 मौन पालन गृह है, जहां पर 1500 से अधिक बेरोजगार शिक्षित युवाओं को पूर्ण रोजगार प्राप्त हुआ है। ये मौन पालन गृह प्रतिवर्ष 1600 मी० टन शहद उत्पादन करने की क्षमता रखतें है जबकि वर्ष 1981–82 के दौरान 3 मी० टन शहद का उत्पादन किया जाता था ।
- फल पौधों के परागण हेतु मौन वंशों के इलावा अन्य किसी पदार्थ की कोई आवश्यकता नहीं होती। प्रमाणित तथ्यों के आधार पर यह पता चलता है कि मौन वंशों के कारण फल फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है और साथ ही मौन पालन गृहों में भी 10 से 20 गुणा अधिक शहद प्राप्त किया जाता है। विभाग द्वारा बागों में निम्न दर फल फसलों के परागण हेतु मौन गृहों की व्यवस्था की जाती है। नवीनतम अनुमानों के आधार पर प्रदेश में फल पौधों के परागण हेतु बागों में लगभग 2,00,000 मौन कलोनियों की आवश्यकता होती है।

विभागीय योजनाएं

राज्य योजना:

- उद्यान विभाग द्वारा सात दिवसीय मौन पालन प्रशिक्षण शिविर पर रु० 50.75 प्रति प्रशिक्षणार्थी दैनिक भत्ता दिया जाता है ।
- उद्यान विभाग द्वारा मौन पालकों को मौन गृहों एवं अन्य आवश्यक उपकरणों पर उपदान दिया जाता है जोकि लघु किसानो को 25 प्रतिशत, सीमान्त किसानो को 33 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े क्षेत्रों एवं आई०आर० डी० पी० से सम्बंधित परिवारों को 50 प्रतिशत की दर से उपलब्ध है।

परागण सेवाएं

- बागवानी विभाग के द्वारा फल पौधों के परागण हेतु किसानो को न्यूनतम दरों पर मौन वंश प्रदान किये जाते है।

प्रदर्शन एवं तकनीकि ज्ञान:

- प्रदेश भर के हर जिले में सरकारी मौन पालन केन्द्र कार्यरत है, जहां पर मौन पालन गृहों में प्रदर्शन के माध्यम से मौन पालकों को तकनीकी ज्ञान एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। राज्य में सरकारी मौन पालन

क्र.सं.	जिलें का नाम	मौन पालन केन्द्र का नाम	
1	शिमला	1	शिमला
		2	हाटकोटी
		3	समोलीपुल
		4	डोडराक्वार
2	सोलन	1	कुनिहार
		2	कुठार
		3	कंडाघाट
3	सिरमौर	1	धोलाकुंआ
4	बिलासपुर	1	निहाल
5	मंडी	1	सुंदरनगर
		2	चौंतरा
6	कुल्लू	1	बियोनी
		2	उरला
		3	कोलिबेहर
7	किन्नौर	1	कटगांव
		2	गायाबोंग
		3	किल्बा
		4	उरनी
		5	सपीलो
8	चम्बा	1	जुधेरा
		2	सरोल
		3	बाकनी
		4	भरमौर
		5	होली
		6	लुना पुल
9	काँगड़ा	1	घुरकरी
		2	जच्छ
		3	चैटरू
10	हमीरपुर	1	भीरा
11	ऊना	1	बमगाना
12	लाहौल स्पीति	1	टिंडी

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

वर्तमान में, उद्यान विभाग द्वारा मौन पालन विकास हेतु दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं चलाई जा रही है जिनका विवरण निम्नानुसार नीचे दर्शाया गया है।

क्र. सं.	योजना का नाम	घटकों के नाम	गतिविधि	मौन गृहों पर स्वीकार्य सहायता
1	उद्यान प्रौद्योगिकी मिशन	मौन पालन का विकास	मौन गृहों की छतों के साथ आपूर्ति पर रु०/800 प्रति इकाई की सहायता।	पहले से पंजीकृत मौन पलकों को 20 मौन गृहों और नए मौन पलकों को 50 मौन गृहों की सहायता प्रदान करना।
2	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर० के० वी० वाई०)	उपरलिखित	उपरलिखित	उपरलिखित

सोलर चरखा मिशन .... रोजगार के क्षेत्र में नया कदम

सोलर चरखा मिशन योजना

भारत सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर काफी गंभीर है। सरकार ने कई ऐसी योजनाओं का संचालन किया है, जो महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करते हैं। ऐसी ही एक योजना राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 27 जून 2018 को संयुक्त राष्ट्र एमएसएमई दिवस के अवसर पर सौलर चरखा मिशन योजन की शुरुआत की गई। ताकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण आर्थिक भूमिका को चिह्नित किया जा सके। इस योजना का संचालन माइक्रो स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज एमएसएमई मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है । गाँव में रहने वाले कई ऐसे लोग हैं जो शिल्पकार भी है, लेकिन बेहतर प्रशिक्षण एवं उनकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उन्हें बेरोजगारी में रहना पड़ता है । इसको ध्यान में रखते हुए देश की राज्य सरकारों और केंद्र सरकार ने मिल कर कई कदम उठाये हैं । सोलर चरखा मिशन एक ऐसी ही योजना है जिसके माध्यम से महिला सशक्तिकरण और उन्हें बेहतर रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई गयी है । इस मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्रशिक्षण दिया जायेगा, ताकि वे कपड़ों का निर्माण कर अपनी बेहतर आजीविका चलाने में सक्षम हो सकें । इस योजना के अंतर्गत पहले 2 वर्षों में कुल 550 करोड रुपए सरकार सब्सिडी के रूप में खर्च करेगी । जिससे देश में करीब 5 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जाएगा । इसके साथ ही इस योजना द्वारा एक लाख से भी ज्यादा लोगों को नौकरियां प्राप्त करने का अवसर मिलेगा

सोलर चरखा मिशन से खासकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि सरकार का लक्ष्य है इस योजना से 5 करोड़ भारतीय महिलाओं को जोड़ना । इस बड़ी योजना के द्वारा एक लाख से ज्यादा नौकरियों का अवसर लोगों को मिलेगा । सोलर चरखा मिशन को सरकार ने स्वीकृति दे दी है और 50 क्लस्टर में 550 करोड़ रुपए भी इस योजना में सब्सिडी के लिए स्वीकृति दिया जा चुका । हर एक क्लस्टर में लगभग 400 से 2000 कारीगर काम करेंगे।

सरकार के अनुसार सोलर चरखा मिशन में लगभग 10000 करोड़ रुपए मात्र छोटे कंपनी सेक्टर में खर्च होने वाले हैं। यह योजना प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत एक बेहतरीन पहल है।

इसके लिए 15 नए टेक्नोलॉजी सेंटर शुरू किए जाएंगे जिनमें से 10 को इसी वर्ष शुरू करने की पूर्ण कोशिश की जाएगी । यहां सेंटर सभी छोटे उद्यमियों को तकनीकी सुविधाएं प्रदान करेंगे ।

सोलर चरखा मिशन के मुख्य उद्देश्य

- ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके कौशल के आधार पर नौकरी दिलाना।
- एक प्राकृतिक ऊर्जा संरक्षण का मॉडल बनाना है।
- खादी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना।
- हरित ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना।
- गरीब लोगों के लिए स्थानीय क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।

सोलर चरखा योजना का उद्देश्य

- देश के पारंपरिक कला से सम्बंधित कुटीर, लघु एवं माध्यम उद्योग को बढ़ावा देना है।
- सोलर चरखा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में कम लागत के प्रोजेक्ट स्थापित करने की योजना से महिला उद्यमियों को नए उद्यम लगाने के लिए प्रेरित करना है।
- खादी उद्योग में सूत कातने का काम ज्यादातर महिलाएं करती हैं। अतः सोलर चरखा के द्वारा सूत कम समय में ज्यादा तैयार होगें । जिससे देश की महिलाएं की आय में वृद्धि होगी और वो स्वावलंबी बनेंगी ।
- इस योजना के तहत सोलर चरखा के माध्यम से सूत तैयार करने में कम समय में ज्यादा उत्पादन होगा। पारम्परिक चरखे से बुनकर मजदूर दिन में 8 घंटे काम करने पर रूपए 160 कमाते हैं। वहीं सोलर चरखे के द्वारा दिन में रूपए 360 तक कमा पाएंगे। इस तरह उनके आमदनी में वृद्धि होगी।
- इस योजना का उद्देश्य बुनकर–शिल्पकार–सूत कातने वाले मजदूरों के आय में वृद्धि करना, तथा उनको रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
- खादी उद्योग को पुनर्जीवित करना है।

सोलर चरखा योजना के लाभ

- इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है।
- सोलर चरखा योजना के माध्यम से सोलर ऊर्जा के उपयोग से नागरिकों को परिचित करवाना है।
- पर्यावरण सुरक्षा हेतु सोलर ऊर्जा को देश में बढ़ावा देन है।
- सोलर चरखा के उपयोग से बुनकरों और सूत कातने वाले मजदूरों की आय में वृद्धि करना है ।
- इस योजना के माध्यम से देश भर में 5 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेंगे, तथा प्रत्येक पंचायत में 1100 नए रोजगार का सृजन होगा ।

सोलर चरखा योजना का बिजनेस मॉडल

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लोन दिए जायेगा । इस योजना के तहत सोलर ऊर्जा इकाई स्थापित करने का कुल खर्च 24,87,694/– रूपए है । इसमें से रुपये 22,38,925/ लोन बैंक से प्राप्त हो जायेगा, तथा बची हुई राशि का(मार्जिन मनी) रूपए 621924/ सब्सिडी सरकार की ओर से स्वरोजगार हेतु उद्यम स्थापित करने और देश में रोजगार के अवसर बढ़ने के एवज में प्डम्ळ के अंतर्गत मिलेगा। आपको अपने पास से लगाना है मात्र रूपए 248769/ और आपका सोलर चरखा प्रोजेक्ट लग जायेगा। इस उद्यम को लगाकर आप वार्षिक 80,000– 100000 रूपए तक कम सकेंगे ।

सौर चरखा मिशन के बारे में:

- सौर चरखा मिशन में 50 समूह शामिल होंगे.
- यह मिशन कारीगरों को रोजगार देने के उद्देश्य से शुरू किया गया हैं ।
- यह मिशन 50 क्लस्टर को कवर करेगा तथा प्रत्येक क्लस्टर 400 से 2000 कारीगरों को नियुक्त करेगा ।
- इस मिशन को भारत सरकार द्वारा अनुमोदिन कर दिया गया है ।
- इस मिशन के लिए एमएसएमई मंत्रालय कारीगारों को 550 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित करेगा ।
- सौर चरखा मिशन से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा होगा, जो पर्यावरण अनुकूल अर्थव्यवस्था में योगदान देगा ।
- सौर चरखा मिशन का मुख्य लक्ष्य देश भर में पांच करोड़ महिलाओं को जोड़ना है ।
- इस योजना के तहत, सरकार पहले दो वर्षों के दौरान एक लाख महिलाओं को नौकरियां देगी ।
- सौर चरखा मिशन 2018 के तहत महिलाओं के लिए एक नया काम पाने का एक शानदार अवसर होगा ।
- इस योजना को विशेष रूप से देश भर में महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया हैं ।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई)

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग वे उद्योग हैं जिनमें काम करने वालों की संख्या एक सीमा से कम होती है तथा उनका वार्षिक उत्पादन भी एक सीमा के अन्दर रहता है। किसी भी देश के विकास में इनका महत्वपूर्ण स्थान है।
- भारत की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का कुल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्यात में 45: हिस्सा है। केन्द्रीय या राज्य सरकार और बैंकिंग एमएसएमई अधिनियम के तहत लाभ को प्राप्त करने के लिए एमएसएमई पंजीकरण आवश्यक है।
- एमएसएमई क्षेत्र उद्यमशीलता के लिए प्रजनन भूमि की तरह होता है, जोकि अक्सर वैयक्तिक सृजनशीलता और नवाचार से संचालित होता है। यह क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 8 फीसदी, विनिर्मित उत्पादन में 45 और इसके निर्यात में 40 फीसदी का योगदान देता है।

ब्लॉक और पंचायत स्तर पर मध्यवर्ती गोदाम

खाद्यान्नों के सहज और निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक और पंचायत स्तर पर मध्यवर्ती गोदामों का एक नेटवर्क आवश्यक है । वर्तमान में, कई राज्यों में एफसीआई की भंडारण डिपुओं से खाद्यान्न उठाए जाते हैं और उचित दर दुकानों को सीधे भेज दिए जाते हैं । खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग मध्यवर्ती स्तर पर भंडारण सुविधाओं, जहां से खाद्यान्न उचित दर दुकानों तक भेजा जा सकता है, के निर्माण की जरूरत पर समय–समय पर राज्य सरकारों पर दबाव डालता रहा है । पंचायत स्तर पर निर्मित इस तरह का गोदाम किसानों को अपनी फसलों को बेचने, स्टॉफ रखने के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा ।

ऐसे गोदामों का निर्माण अब राज्य सरकारों द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना के तहत प्रदान की गई निधि का उपयोग कर किया जा सकता है । ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 में उपयुक्त संशोधन कर दिया है जिसके परिणामस्वीरूप इस तरह के निर्माण योजना के अंतर्गत पात्र गतिविधियों में शामिल हो गया है ।

द रीव टाइम्स संस्थापकः डॉ. एल.सी. शर्मा, द रीव टाइम्स पब्लिकेशन के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक श्री प्रदीप कुमार जरेट द्वारा एसोसिएट प्रैस सायब निवास समीप सेक्टर -2, बस स्टैंड मिडल मार्केट न्यू शिमला-9, हि.प्र. से प्रकाशित एवं मुद्रित प्रधान सम्पादकः डा. एल.सी. शर्मा, प्रबन्ध सम्पादकः आनन्द नायर फोन न. 0177 2640761,
मेलः editor@themissionriev.com RNI Reference No. 1328500

HP/129/SML/2019-2021

Advertorial

HPKVN

Skill India
कौशल भारत-कुशल भारत

N·S·D·C
National
Skill Development
Corporation
Transforming the skill landscape

PMKVY
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

KAUSHAL VIKAS SE AAYEGA NIKHAR KHULEGAE ROJGAR KE DWAR

An initiative by Indian Government

PRADHAN MANTRI KAUSHAL VIKAS YOJANA

Golden Opportunity for Skill Development

IIRD IN COLLABORATION WITH NSDC

REGISTER IN JUNIOR SOFTWARE DEVELOPER COURSE & GIVE NEW HEIGHTS TO YOUR CAREER

JOB ROLE DESCRIPTION	FEATURE OF CURRICULUM
TO MANAGE & STORE MEDICINES	FREE PRACTICAL & BEHAVIOURAL TRAINING
TO RECORD & MAINTAIN PERSONALISED PROFILE OF THE PATIENT	TRAINING OF INTERNATIONAL STANDARD

REGISTER IN JUNIOR SOFTWARE DEVELOPER COURSE & GIVE NEW HEIGHTS TO YOUR CAREER

JOB ROLE DESCRIPTION	FEATURE OF CURRICULUM
TO DEVELOP & EXAMINE SOFTWARE AT ENTRY LEVEL IN IT SECTOR	FREE PRACTICAL & BEHAVIOURAL TRAINING
TO MAINTAIN SAFE & HEALTHY ENVIRONMENT IN THE ORGANISATION	TRAINING OF INTERNATIONAL STANDARD

Educational Qualification

- Age 18-35 Years
- Pharmacy Assistant : Any +2 (Medical), Course Duration - 4 Months
- Junior Software Developer : Any +2, Course Duration - 4 Months
- Additional Benefits : Free Basic computer knowledge, Soft Skills and English learning

Junior Software Developer

FIRST COME FIRST SERVE
LIMITED SEATS

Main Features

- Free of cost training to all the Candidates
- Free Training kit and course booklet
- 100% Assured Placement
- After Successful completion of training, women and specially abled candidates will be given financial incentive from the govt. T.C*

Documents Required

- Photocopy of Aadhar Card
- Photocopy of Bank Account
- Five Passport size photographs
- Photocopy of Educational Qualification Certificate

Pharmacy Assistant

AFTER COMPLETION OF TRAINING SKILLED STUDENTS WHO WANT TO START THEIR OWN BUSINESS WILL BE FACILITATED MUDRA LOAN ON LOW RATE OF INTEREST WITHOUT GUARANTEE

* नियम और शर्तें लागू

KUSHAL HIMACHAL SAMRIDH HIMACHAL

ज़िंदगी जियें-नशे को नहीं
स्वस्थ एवं नशामुक्त हिमाचल बनाने में दें सहयोग

IIRD
हम जानते हैं गाँव को बेहतर
Institute for Integrated Rural Development

IIRD Complex, Bypass Road, Shanan, Sanjauli, Shimla, H.P.-171006
Phone No. : 0177 2640761, Mob. 91311 24634, 85280 89637
Email : info@missionriev.in, Web : www.missionriev.in

RURALIZING INDIA-EMPOWERING VILLAGE
RIEV
कि दुनिया देखती रह जाए